हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

02 मार्च, 2020

खण्ड–1, अंक–8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 02 मार्च, 2020

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ के अर्थशास्त्र विभाग के विद्यार्थियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बतौड़, जिला पंचकूला के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 02 मार्च, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहल बाद 02.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र□न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 360

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बलराज सदस्य कुंडू सदन में उपस्थित नही थे)

To Provide Permanent Service

***324. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to permanent the services of D.C rate employees working in State?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, डी.सी रेट पर लगे कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नही है।

श्री बिशन लाल सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि नहीं श्रीमान् लेकिन हरियाणा में डी.सी. रेट पर लगे हुए हरियाणा प्रदेश के जो भी युवा हैं उनके भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होती होगी? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या डी.सी. रेट पर लगे हुये युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की है या उनको निकाल दिया जायेगा?

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि डी.सी. रेट पर 11 हजार से 14 हजार कर्मचारी लगे हुए हैं। ये विभिन्न जिलों में विभिन्न कैटेगरीज में लगे हुए हैं जिनमें चौकीदार भी हैं, सेवादार भी हैं, ड्राइवर भी हैं तथा ऑप्रेटर इत्यादि भी हैं। उन सभी के अलग–अलग वेतनमान हैं। उनकी नौकरी बचाने के लिए हमने कोशिश की है। यह केस हाई कोर्ट में वे हार गये थे, इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रखा है तथा वहां पर स्टे हो रखा है। वे अभी भी नौकरी पर चल रहे हैं।

@ Reply given by the Power Minister

श्री बिशन लाल सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि केस हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में जो युवा डी.सी. रेट पर विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं क्या उनका भविष्य सुरक्षित है या नहीं है? जो लगे हुए हैं उनको लगे रहने दिया जायेगा या नौकरी से निकाल दिया जायेगा?

(बिजली मंत्री) श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक तो आउटसोर्सिंग पर लगे हुए हैं जो ठेकेदार के माध्यम से लगते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरकार की तरफ से भी लगाए गए हैं जो ग्रुप–डी में लगे हुए हैं जिनका वेतन लगभग 19 हजार रुपये से कम नहीं है। इसके अलावा माननीय सदस्य का कोई जवाब नहीं बनता है।

श्री बिशन लाल सैनीः अध्यक्ष महोदय, ग्रुप–डी अलग चीज है और डी.सी. रेट अलग चीज है। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, डॉ. बिशन लाल जी यह पूछना चाहते हैं कि हरियाणा में जो युवा डी.सी. रेट पर लगे हुए हैं, जिनको नौकरी करते हुए 5 से 7 साल हो गये हैं और जब वे ओवरएज हो जाते हैं तो उनको उस डी.सी. रेट की नौकरी से निकाल दिया जाता है। इनका कहना यह है कि अगर डी.सी. रेट पर नौकरी देते हैं तो पक्की दे दें, उनको हटाया न जाए। जहां तक ठेकेदार की बात है तो ठेकेदार तो हर साल बदलते रहते हैं और उनकी रोजाना शिकायतें भी मिलती हैं। ठेकेदार के माध्यम से नौकरी पर रखना तो बिल्कुल करप्शन को बुलावा देने जैसा होता है। ठेकेदारी सिस्टम तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। डी.सी. रेट पर लगने के बाद कर्मचारी कहीं के नहीं रहते हैं। न ही तो उनकोआगे जाने का रास्ता दिखता है और न ही पीछे जाने का और अगर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वे अपनी आजीविका कैसे चलायेंगे, वे कहां जायेंगे? डी.सी. रेट पर लगाओ तो उनको पक्का रखो। डॉ. सैनी पूछना चाहते हैं कि क्या डी.सी. रेट पर लगे हुए कर्मचारियों को रेगुलर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं यह प्रश्न समझ पाया हूं मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि रेगुलराईजेशन के पात्र केवल डायरेक्ट अप्वाइंटी होते हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए वर्ष 2014 में एक पॉलिसी बनी थी जो माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी उसके बाद

सरकार सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. में चली गई है और उस पर फिलहाल स्टेटसको है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नियमित भर्ती होने के बाद डी.सी. रेट पर लगे हुए कर्मचारी हट जायेंगे।

.....

Transportation of Soil for Private Use

***383. Shri Nayan Pal Rawat :** Will the Mines and Geology Minister be pleased to state whether it is a fact that transportation of soil on tractor trolley by farmers for private use is legal; if so, the details thereof?

परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद भार्मा) : नहीं, श्रीमान् जी। अतः इस प्रश्न का दूसरा भाग पैदा ही नहीं होता।

श्री नयन पाल रावतः अध्यक्ष महोदय, जो छोटे–छोटे किसान हैं उनको कई बार भैंसा गाड़ी से या ट्रैक्टर–ट्रॉली से मकान बनाते समय भरत के लिए मिट्टी लानी होती है। वैसे तो सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया है लेकिन इसके अलावा उनके और भी बहुत से छोटे–छोटे काम होते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन छोटे–छोटे किसानों को भैंसा गाड़ी और ट्रैक्टर–ट्रॉली से मिट्टी लाने के लिए छूट प्रदान की जाए।

श्री मूल चन्द ार्मा : श्रीमान जी, जो किसान अपने ट्रैक्टर–ट्रॉली से एग्रीकल्चर का काम करता है जैसे किसान उसमें अपनी फसल लेकर आता है या अपने घर के खेती से संबंधित काम करता है तो वह वैध की श्रेणी में आता है। वह कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं रोकते हैं । हमारा उदेश्य है कि जो किसान अपनी ट्रैक्टर–ट्रॉली में ईंट, पत्थर, रेत, मिट्टी, अवैध खनन या माइनिंग आदि का काम करते हैं अर्थात कॉमर्शियल काम करते हैं। वह वैध की श्रेणी में नहीं है। हम उनको रोकते हैं।

श्री नयन पाल रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं। मेरी मंत्री जी से इतनी ही विनती है कि किसान को इसमें अवाएड किया जाए अर्थात किसान को कॉमर्शियल यूज से बचाया जाए।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि किसान के लिए ट्रैक्टर–ट्रॉली को खेती के काम के लिए यूज करने पर फ्री किया हुआ है लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अगर कोई किसान अपने घर में भरत करने के लिए भी

मिट्टी लाता है तो उसके ट्रैक्टर–ट्रॉली को माइनिंग के नाम पर बन्द कर दिया जाता है और उस ट्रैक्टर–ट्रॉली की कीमत का 50 प्रतिशत जुर्माना भी वसूला जाता है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जितने भी ट्रैक्टर–ट्रॉली थानों में बन्द पड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री मूल चन्द भार्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल मेरे साथी विधायक जी ने पूछा है उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जो किसान अपने ट्रैक्टर–ट्रॉली से अवैध खनन करते हैं अर्थात कॉमर्शियल काम के लिए यूज करते हैं, अपने घर के लिए मिट्टी नहीं लाते हैं बल्कि वह व्यापार करते हैं। उनके पास न कोई पॉलिसी है, न कोई बिल है और न कोई ई–रवाना है तो उनके साथ एन.जी.टी. के तहत कार्यवाही होती है।

.....

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा पंजाब यूनिवर्सिटी,चण्डीगढ़ के अर्थभाास्त्र विभाग के विद्यार्थियों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में श्री दुर्गा दत्त अत्री, पूर्व विधायक अति विशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ के अर्थ शास्त्र विभाग के विद्यार्थी भी दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। उनका भी अभिनन्दन करता हूँ।

.....

तारांकित प्र□न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To construct Auto Market

***37. Dr. Krishan Lal Middha** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Auto Market in Jind City; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

@ भाहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) इसलिए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

डॉ. कृश्ण लाल मिड्ढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जीन्द शहर में जो ऑटो मार्किट के निर्माण की घोषणा हुई थी क्या उसको नगर परिषद को सौंपा गया था? उस ऑटो मार्किट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसका कोड नं. 9745 है और यह दिनांक 26.11.2014 की घोषणा है। मेरे पिता जी ने उस समय यह डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और उस समय की संबंधित मंत्री श्रीमती कविता जैन जी ने इसके लिए 'हां' में जवाब दिया था लेकिन अभी तक इस कार्य पर कोई कार्य नहीं हुआ है।

परिवहन मंत्री (श्री मूल चन्द भार्मा) : अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने जो प्रश्न रखा है। वह बिल्कुल ठीक है। यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा है जिसका कोड नं. 9745 है। इसके लिए राष्ट्रीय राज मार्ग–332 पर 100 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि जहां ट्रांसपोर्ट नगर बनना है हम चाहते हैं कि उसके साथ ही यह ऑटो मार्किट भी बसाई जाए, इसलिए माननीय विधायक से मेरी विनती है कि आप वहां जमीन उपलब्ध करवाएं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उसको पूरा करेंगे।

.....

To Start Construction work of Government Women College

***275. Shri Satya Parkash Jrawta:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start construction work of building of Government Women College at Manesar; If so, the time by which it is likely to be started?

.....

@ Reply given by the Transport Minister

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : हां, श्रीमान् जी। महाविद्यालय का निर्माण कार्य वन विभाग से महाविद्यालय स्थल की अनापत्ति प्राप्त होने उपरान्त शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा।

श्री सत्य प्रकाश जरावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह वन मंत्री भी स्वयं हैं और शिक्षा मंत्री भी स्वयं हैं और यह वर्ष 2014 की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन को पैंडैंसी क्लीयर करवाकर जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण करवाया जाए।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू करवा देंगे।

श्री धर्म सिंह छोक्कर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सरकार की एक घोषणा थी कि हरियाणा प्रदेश में लड़कियों को शिक्षा के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। इसी घोषणा के मद्देनज़र मैंने सरकार से पहले भी गुजारिश की थी कि समालखा जोकि एक बहुत बड़ा टाउन है, में कोई भी गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है। यहां की लड़कियों को पढ़ने के लिए पानीपत आना पड़ता है। समालखा से पानीपत की दूरी लगभग 21 किलोमीटर की पड़ती है। इस वजह से लड़कियों को बसों के न रूकने जैसी समस्या से भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि समालखा में भी एक गवर्नमैंट कॉलेज जरूर खोला जाये ताकि लड़कियों को दिन–प्रतिदिन आ रही इस समस्या से बचाया जा सके।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा यह थी कि हरियाणा प्रदेश में लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके नहीं जाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत सरकारी कॉलेज होने की कोई शर्त नहीं है। 20 किलोमीटर की दूरी के तहत प्राईवेट कॉलेज व सरकारी कॉलेज दोनों कवर होते हैं।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, समालखा में कोई भी गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है और हमारी लड़कियों को 20 किलोमीटर की दूरी तय करके पानीपत में

जाना पड़ता है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की शर्त को जिस ढंग से बता रहे हैं इससे तो कोई बात नहीं बनी?

श्री अध्यक्षः छोक्कर जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आपके समाने सब कुछ क्लीयर कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 20 किलोमीटर की दूरी के तहत गवर्नमैंट कॉलेज अनिवार्य नहीं है बल्कि यह प्राईवेट कॉलेज भी हो सकता है। अतः जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सब कुछ क्लीयर कर दिया है तो आप अब अपनी सीट पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छौक्करः अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट कालेजिज के बारे में सबको पता है कि वे कितने ज्यादा महंगे होते हैं। अतः अनुरोध है कि समालखा में भी सरकारी कॉलेज खोला जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा के लिए 21 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जबकि सरकार की पॉलिसी तो 20 किलोमीटर की है?

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि समालखा कस्बे में सरकारी कॉलेज नहीं है लेकिन यहां पर पहले से एक कॉलेज जरूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई ऐसी घोषणा नहीं है कि हर जगह सरकारी कॉलेज खोला जायेगा बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा है कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जायेगी।

श्री अध्यक्षः छोक्कर जी, अब सब कुछ क्लीयर हो गया है अतः प्लीज आप बैठिए और प्रश्न काल के समय का सदुपयोग होने दें।

.....

To Supply Proper Water For Irrigation

***64. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply proper water for irrigation in villages Masudpur, Datta, Lohari Ragho, Haibatpur, Rakhi Shahpur, Rakhi Garhi, Gamra, Kheri Jalab, Kheri Lochab in Narnaund Constituency?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, इन सभी 9 गांवों की भूमि, मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल, डाटा डिस्ट्रीब्यूट्री, सिंघवा डिस्ट्रीब्यूट्री व खेड़ी

श्योराण माईनर (भाखड़ा प्रणाली) व मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री व लोहारी माईनर (यमुना प्रणाली) से

.....

@ Reply given by the Agricultuer and Farmers Welfare Minister

सिंचित होती है जिसकी परियोजना सघनता 62 प्रतिशत से अधिक है। बेहतर सिंचाई के लिए लोहारी राघो, डाटा, ठरवा और शालाडेरी के कुछ क्षेत्र को लोगों की मांग के अनुसार यमुना प्रणाली में स्थानांतरण करने के लिए मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री को आगे बढ़ाने की प्रस्ताव है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जैसाकि कहा गया था कि अगर लोग जमीन की रजिस्ट्री करायेंगे तो उनको साथ ही साथ पैसा दे दिया जायेगा। हमारे यहां पर 75 प्रतिशत के करीब लोगों ने जमीन की रजिस्ट्रियां करवा दी हैं लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया है? अतः निवेदन है कि सरकार इस दिशा में जरूर ध्यान दे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, अभी तक महज 60 प्रतिशत ही रजिस्ट्रियां हुई हैं अतः जब एक निर्धारित सीमा तक यह रजिस्ट्रियां हो जायेगी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गांव लोहारी राघो की 17. 24 एकड़ जमीन में से 10.40 एकड़ जमीन मिल गई है इसी प्रकार गांव केरवा की 1.94 एकड़ जमीन में से 0.96 एकड़ जमीन मिल गई है इस हिसाब से अभी 7.82 एकड़ जमीन मिलनी बाकी है। कहने का भाव यही है कि अब तक 60 परसेंट जमीन मिल चुकी है अगर बाकी की जमीन और मिल जायेगी तो जल्द से जल्द लोगों को पेमेंट भी कर दी जायेगी और नहर भी बन जायेगी।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठे बैठे कहा कि 60 परसेंट जमीन ही मिली है और माननीय मंत्री जी ने भी कुछ इसी तरह का जवाब दिया है के संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि लोगों की हौसलाअफजाई के लिए अर्थात जैसाकि कहा गया है कि 60 परसेंट जमीन मिल चुकी है, अगर इन 60 परसेंट लोगों को जल्दी पेमेंट देना शुरू कर दी जाये तो बहुत बढ़िया बात होगी। अध्यक्ष महोदय, गांव डाटा और मसूदपूर में पानी

की बहुत ज्यादा समस्या है। यही नहीं यहां तो पीने के पानी तक की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। यहां पर पहले एक पानी की डिग्गी होती थी जोकि अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसको नई बनवाने की बहुत जरूरत है। एक दो और जगह है, इनके बारे में मैं बाद में बताउंगा। जिन गांवों की मैंने बात बताई है, इनमें पानी की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा यथासंभव प्रभावी कदम जल्द से जल्द उठाये जाने चाहिए।

श्री अध्यक्षः गौतम जी , माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है, अतः प्लीज आप बैठिए।

.....

To Open a Government Girls Polytechnic College

*** 122. Shri Sita Ram:** Will the Technical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls Polytechnic College in Ateli Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अटेली विधान सभा क्षेत्र में गर्ल्ज पोलिटेक्निकल कॉलेज खोलने की बहुत पुरानी मांग है अतः अनुरोध है कि यहां पर गर्ल्ज पोलिटेक्निकल कॉलेज जल्द से जल्द खोला जाये।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कुल 52 प्राईवेट पोलिटेक्निकल कॉलेज हैं जिसमें से 4 पोलिटेक्निकल कॉलेज महेन्द्रगढ़ जिले में हैं। अगर इनमें खाली पड़ी सीटों की प्रतिशतताः देखें तो पायेंगे कि 62 प्रतिशत सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। अटेली और महेन्द्रगढ़ की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की है और महेन्द्रगढ़ जिले में एक पोलिटेक्निकल कॉलेज ऑलरेडी है और वहां पर भी 56 प्रतिशत सीट्स are laying vacant. अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में नया बहुतकनीकी संस्थान खोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अगर माननीय सदस्य अटेली से महेन्द्रगढ़ बहुतकनीकी संस्थान तक जाने के लिए बस की मांग करते हैं तो उसकी व्यवस्था

सरकार कर सकती है। लेकिन नया बहुतकनीकी संस्थान खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री सीता राम : अध्यक्ष महोदय, नारनौल में बॉयज बहुतकनीकी संस्थान है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि लोगों की मांग के अनुरूप अटेली में महिला बहुतकनीकी संस्थान खोला जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने महिला बहुतकनीकी संस्थान अम्बाला, सिरसा, सोनीपत, खानपुर कलां, फरीदाबाद आदि क्षेत्रों में भी खोले हुए हैं। इन संस्थानों में इन्टैक्ट ही नहीं है, फुटफाल ही नहीं है, किसी भी कारण से बच्चें एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं तो इस प्रकार से नया महिला बहुतकनीकी संस्थान नहीं खोला जा सकता है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि इसका क्या कारण है कि इन बहुतकनीकी संस्थानों में 60 प्रतिशत सीटें से ऊपर खाली रह जाती हैं। क्या हम अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर, अच्छा स्टाफ व अच्छी फैसिलिटी बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं झज्जर के को–एड बहुतकनीकी संस्थान के बारे में माननीय मंत्री जी से जाना चाहती हूँ कि गर्ल्ज को सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा शिकायतें रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर प्राइवेट बहुतकनीकी संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेजिज आर्थिक मंदी के कारण से बंद हो गए हैं। सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों में इन्टैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके क्या कारण रहे हैं? लड़कियों की सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? अध्यक्ष महोदय, दूसरी मेरी सप्लीमैंट्री यह है कि बाबू जग जीवन राम छात्रावास योजना के तहत हमारी सरकार के समय में बहुतकनीकी संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजिज में हॉस्टल्ज बनाए गए थे लेकिन अब कई वर्षों से इन संस्थानों में हॉस्टल्ज नहीं बन रहे हैं। इसका क्या कारण है, यह बात भी माननीय मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न से संबंधित पहले भी सदन को जानकारी दे चुका हूँ। हमारे प्रदेश के बच्चों की साईंस के विषय में रूचि कम होती जा रही है। इस बात को स्टडी करवाने के लिए हम एक बड़ी कमेटी कांस्टीच्युट करने जा रहे हैं, जो जल्दी ही नोटिफाई हो जायेगी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे साईंस स्ट्रीम में ज्यादा रूचि लें। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इंजीनियरिंग

कॉलेज में इन्टैक्ट 25 प्रतिशत रह गया है। वाकई में यह चिंता का विषय है हम इस पर लगातार वर्क कर रहे हैं।

.....

तारांकित प्र□न संख्या 75

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

Maintenance work of Park

***61**. **Rao Dan Singh:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the maintenance work of Chaudhary Ranbir Singh Hooda Park constructed in Municipal Council, Mahendergarh is not being performed in proper manner for the last few years; and

(b)if so, whether there is any proposal under consideration of the Government for beautification of the said park togetherwith the time by which it is likely to be completed ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) नहीं, श्रीमान् जी। जरूरत के अनुसार मुरम्मत का कार्य निरन्तर कराया जाता है। हाल ही में दिसम्बर 2019 में नगर पालिका महेन्द्रगढ़ द्वारा पार्क के फटपाथ एंव रंग रोगन के कार्य पर 1 लाख 75 हजार रूपये खर्च किये गये है।

(ख) इसलिये प्रश्न का यह भाग नही बनता है।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहां नगर परिषद्, महेन्द्रगढ़ में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा एक मात्र बड़ा पार्क है जिसको पहले बहुत ही अच्छी तरह से डिवैल्प किया गया था। जिसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम भी अच्छी तरह से काम कर रहा था। लोगों का

फुटफाल भी बहुत अच्छा था। लोगों के बैठने के लिए पार्क में बैंचिज वगैरह भी लगे हुए थे और लाइट की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अभी इस पार्क की हालत यह है कि घास को पानी देने के लिए पार्क में टयूबवैल की व्यवस्था तो है लेकिन पानी नहीं है क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी का जल स्तर हर वर्ष नीचे चला जाता है। नगर निगम ने इसके लिए पाइप वगैरह डालने की कोई भी व्यवथा नहीं कर रखी है कि किसी तरह से बोरिंग वगैरह करके इस टयूबवैल को ऑपरेशनल कर दे। पार्क में घुमने वाले लोगों ने अपनी जेब से पैसा इक्ट्ठा किया और उस टयूबवैल में पानी लाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस पार्क में लाइट व रखरखाव का सवाल है, माननीय मंत्री जी स्वयं जाकर देखेंगे तो जरूर कहेंगे कि इस पार्क की हालत काफी दुर्दशा में है। अध्यक्ष महोदय, इस पार्क की रखरखाव की सख्त से सख्त जरूरत है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वहां के पार्क के बारे में सदन को बताया है। वैसे इस पार्क के रखरखाव के लिए 8 माली, 4 गार्ड, 2 स्वीपर और 1 इलेक्ट्रिशियन रखे हुए हैं। ताकि उस पार्क की बराबर रखरखाव किया जा सके। अगर माननीय सदस्य चाहे तो जैसे हमने कई नगर पालिकाओं में आर0डब्ल्यू0ए0 में पार्क दे रखें हैं। यदि माननीय सदस्य चाहे वहां की कोई आर,डब्ल्यू0ए0 इस पार्क को ले लें और इस पार्क की रखरखाव करें, सरकार उसके लिए पैसे भी देती है। इस तरह से इस पार्क का और अच्छी तरह से रखरखाव हो जायेगा।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस स्टाफ की सूचना माननीय मंत्री जी ने सदन को बताई है, वह ठीक है। नगर परिषद् की तरफ से जितने समय तक उस स्टाफ ने पार्क में काम किया उनको कोई सैलरी नहीं दी गई। आज वही लोग कह रहे हैं कि हमने इतने दिनों तक काम किया था लेकिन हमें कोई भी पैसा नहीं मिला और हमारी जगह दूसरे नये आदमियों को काम पर रख लिय है। माननीय मंत्री जी इस पार्क के रखरखाव के लिए भविष्य में क्या प्रावधान किया गया है? इस बारे में माननीय मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस बात को हम चैक करेंगे और इस पार्क को लेकर कोई त्रुटि होगी तो ठीक करेंगे।

.....

Total Number of Post of Teachers

***225. Shri Ram Kumar Kashyap :** Will the Education Minister be pleased to state the total number of posts of teachers in schools of State togetherwith the number of posts lying vacant thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, दोनों संख्याएं क्रमशः 124270 तथा 29646 हैं।

श्री राम कुमार कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी ने बजट में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 प्रतिशत पहले से ज्यादा का प्रावधान किया है। बजट में आठवीं की परीक्षा के लिए बोर्ड की परीक्षा का प्रावधान किया गया है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। परंतु शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ठीक हो कोई भी स्कूल में अध्यापकों का रिक्त पद न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, राजकीय स्कूल्ज में अध्यापकों के रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि 29 हजार 646 रिक्त पदों में से जो पद प्रमोशन द्वारा भरे जाने हैं उनको 3 महीने में भर दिया जायेगा। जिन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है उनको दो महीने में उनका विज्ञापन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया जायेगा।

श्री राम कुमार कश्यप : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बात सदन में कही है, वह ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था करना विभाग का काम होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पिछले साल कितने अध्यापकों की भर्ती हुई हैं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, इस समय पिछले साल की जानकारी तो मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य लिखित में प्रश्न मेरे पास भेज देंगे तो मैं लिखित रूप में उनको उत्तर भेज दूंगा। वैसे माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पी0आर0टी0/जे0बी0टी0 के 5702 पद रिक्त हैं इनको भरने के विज्ञापन दो महीने के अंदर एच0एस0एस0सी0 को भेज दिया जायेगा। हैड

टीचर के 790 पद रिक्त हैं। ये प्रमोशनल पद हैं और तीन महीने के अंदर सभी प्रमोशन कर दी जायेगी। एलीमैंट्री स्कूल हैड मास्टर के 1900 पद रिक्त हैं, ये पद भी प्रमोशनल हैं और तीन महीने के अंदर सभी प्रमोशन कर दी जायेगी। टी0जी0टी0 के 8137 रिक्त पद हैं, जिसमें 33 प्रतिशत पोस्ट्स प्रमोशन के माध्यम से भरी जाएगी, जिसको तीन महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा और 67 प्रतिशत पोस्ट्स सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी, जिनका विज्ञापन दो महीने के अंदर एच0एस0एस0सी0 को भेज दिया जाएगा। इस तरह से पी0जी0टी0 के 13129 पद रिक्त हैं, जिनको भरने के लिए दिनांक 07.08.2019 को 3864 पदों को भरने के लिए एच0एस0एस0सी0 को विज्ञापन दिया चुका है। 5248 पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा, जिसकी प्रक्रिया तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 4017 पदों को भरने के लिए दो महीने के अन्दर विज्ञापन एच0एस0एस0सी0 को भेज दिया जायेगा।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूँ कि मेवात शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमने मेवात काडर बनाकर शिक्षा की नई शुरूआत की थी। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पूरे हरियाणा में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। मेवात क्षेत्र के लिए मेवात काडर इसलिए बनाया गया था कि शिक्षकों के ट्रांसफर व प्रतिनियुक्तियां न हो। लेकिन हमारे क्षेत्र से अध्यापकों के ट्रांसफर व प्रतिनियुक्तियां जरूर हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले ही हमारे क्षेत्र में शिक्षकों की कमी हैं और सरकार अध्यापकों के ट्रांसफर व प्रतिनियुक्तियां कर रही है। मेवात काडर के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाये और अध्यापकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्तियों पर रोक लगाई जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्ष मंत्री से कहना चाहता हूँ कि मेवात काडर के माध्यम से जल्दी से जल्दी अध्यापकों की भर्ती करें और जो मेवात क्षेत्र में अध्यापकों की ट्रांसफर व प्रतिनियुक्तियां चल रही हैं उन्हें रोका जाये। सरकार ने मेवात क्षेत्र के लिए जिन अध्यापकों के ट्रांसफर व प्रतिनियुक्तियों के ऑर्डर किए हुए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से कैंसिल करें और मेवात क्षेत्र में नई भर्ती करें।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

.....

Shortage of Bus Service

***53. Shri Pardeep Chaudhary** : Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that there is acute shortage of bus service in the Kalka Constituency due to which the students as well as general public are facing problem; if so, the time by which the shortage of bus service is likely to be met-out togetherwith the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री मूलचन्द भार्मा) : श्रीमान् जी, नहीं।

श्री प्रदीप चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनको उनके विभाग ने बहुत ही गलत जानकारी दी है क्योंकि मेरे कालका हल्के में बसों की बहुत भारी कमी है। अगर हम चण्डीगढ़ से नारायणगढ़ और पंचकुला की तरफ सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक जाना चाहते हैं तो वहां से कोई भी बसों की सुविधाएं नहीं हैं। इसी तरह से अंबाला से भी सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे तक आने के लिए भी कोई बसों की सुविधा नहीं है जिसके कारण वहां पर स्टूडैंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां की जनता अपने गन्तव्य स्थान पर जाने के लिए दूसरे साधनों पर लटक कर जोखिम भरा सफर तय करती हैं। रायपुररानी से पंचकुला आने के लिए बसों की सुविधाएं नहीं हैं। पिंजौर और कालका जैसे शहरों से पंचकुला तथा चण्डीगढ़ आने के लिए बसों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विभाग के संबंधित जी.एम. को इन एरियाज में भेजकर जानकारी प्राप्त करवा लें कि वहां पर जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री मूल चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय आपने स्वयं आज सुबह–सुबह ही संबंधित डिपो के लिए 20 बसें और हरी झंडी दिखाकर चालू करवायी हैं।`

श्री अध्यक्षः प्रदीप जी, मैंने आज सुबह ही हरी झंडी दिखाकर 20 अतिरिक्त बसें चालू करवायी हैं।

श्री मूल चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, इससे पहले चण्डीगढ़ डिपो के अधीन एक सब डिपो है और उस सब डिपो के लिए पहले 65 बसों की स्वीकृति थी। अब टोटल 144 बसें हो गयी हैं, इसमें 82 बसें पंचकुला डिपो के लिए और 42 बसें कालका डिपो के अंडर दी जाएंगी। इसमें सबसे लम्बी दूरी की बसों का रूट कालका से जम्मू – कटरा तक है और सबसे छोटा रूट पंचकुला से खेत पालड़ी तक का है। इस डिपो के अधीन कालका, पंचकुला, बराला और रायपुररानी के बस

स्टैंड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सभी जगहों तक पहुंचने के लिए एक–एक बस का वितरण कर दिया गया है। इस प्रकार वहां पर किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए बसों की कमी नहीं रहेगी। अर्थात, प्रदेश में नयी बसें आ रही हैं और बसों की कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हमारा मोरनी का एरिया शिवालिक की पहाड़ी का इलाका है। वहां पर सफर करते समय ढलान– चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए क्या विभाग का वहां पर मीनी बस चलाने का कोई इरादा है ?

श्री मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, कालका से मोरनी तक जाने के लिए मीनी बसें आ रही हैं। बेटियों के लिए मिनी बसें चालू करेंगे।

.....

Shortage of Doctors

***100. Smt. Shalley Choudhary :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of Medical Officers and specialist doctors in Civil Hospital of Naraingarh; if so, the time by which the shortage of doctors in abovesaid hospital is likely to be met out?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : हां, जी। इस महीने की शुरुआत में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर चिकित्सकों के पद भर लिए जाएंगे।

श्रीमती शैली चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कह रहे हैं कि इस महीने में संबंधित डॉक्टर्ज की भर्ती पूरी कर ली जाएगी, लेकिन मेरे हल्के नारायणगढ़ के हॉस्पिटल में 39 डॉक्टर्ज के पद खाली हैं। मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करती हूं कि इनकी पूर्ति जल्दी की जाए क्योंकि 3–4 कैटेगरीज के स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग के डॉक्टर्ज शामिल है, इसलिए ये डॉक्टर्ज वहां पर तुरंत भेजे जाने चाहिए।

Shri Anil Vij: Sir, I am aware of this that there is a big shortage of doctors and para-medical staff in the State and that's why the recruitment process is on. Yesterday only, the written test for filling up the posts of 400 doctors was taken. As on today, we have 3240 sanctioned posts of doctors and out of which 2451 are available and we have a vacancy of

789 doctors and with the recruitment of doctors this time within a month of March-April, you can say the shortage will be recovered.

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे लाडवा हल्के के बबैन गांव की पी.एच.सी. को 3 महीने पहले ही सी.एच.सी. मे अपग्रेड किया गया था। वहां पर नयी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी है और संबंधित बिल्डिंग उद्घाटन का इन्तजार कर रही है, लेकिन अभी तक वहां पर संबंधित डॉक्टर्ज नहीं लगाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर डॉक्टर्ज लगाये जाएं और संबंधित बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाए।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, लाडवा के बबैन गांव की सी.एच.सी. मेरी जानकारी में है। वहां पर डॉक्टर्ज और इक्विपमैंट के अलावा दूसरी जरूरी चीजें लगवाकर काम शुरू करवा देंगे।

———————————

Increas in Crime Rate

***150. Smt Geeta Bhukkal:**
Shri Jagbir Singh Malik:
Shri Chiranjeev Rao:
Shri Aftab Ahmed:
Shri Ishwar Singh:

Will the Home Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that crime rate is increasing in the Sate specially against women, children and other weaker sections of society; and

(b) if so, the steps taken by the Government to control/prevent the crime?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) राज्य में विशेष रूप से महिलाओं, और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध दर में थोड़ी वृद्धि हुई थी। हालांकि, वर्ष–2019 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध में 3.8ः की कमी आई है। वर्ष 2017, 2018 और 2019 का तुलनात्मक चार्ट इस प्रकार हैः–

शीर्ष	2017	2018	वर्ष 2017 व 2018 की प्रतिशत भिन्नता	2018	2019	वर्ष 2018 व 2019 की प्रतिशत भिन्नता
महिलाओं के विरूद्ध अपराध	9989	12691	27.04%	12691	13104	3.25%

बच्चों के विरूद्ध अपराध	3188	4022	26.2%	4022	3870	-3.8%
अन्य कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराध	804	1016	26.4%	1016	1097	7.9%

(ख) **<u>हरियाणा सरकार द्वारा महिला विरूद्व अपराधों की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए है उनमें भामिल है–</u>**

1. हरियाणा सरकार द्वारा 33 महिला पुलिस थानें अधिसूचित किए है और उनमें से 32 थानें कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक महिला थानो में परामर्ष केंद्र, महिला हेल्प लाईन 1091, महिला पी.सी.आर. और स्कूटी सवार, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्त जिला संरक्षण अधिकारी का कार्यालय है और महिला विघिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक महिला पुलिस थाने के लिए एक महिला वकील की नियुक्ति की गई है।
2. जिला मुख्यालयों से दूरदराज के इलाकों में रहने वाली महिलाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य के सभी जिलों के सब–डिविजन स्तर पर 'महिला हैल्प डेस्क' स्थापित किए गए है।
3. राज्य में चार अंकीय महिला हैल्पलाईन नम्बर 1091 सक्रिय है। जिस पर विषेष रूप से प्रषिक्षित महिला पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इस महिला हैल्पलाईन पर प्राप्त सभी षिकायतों पर उचित तथा शीघ्र कार्रवाई सुनिष्चित करने व उसके कामकाज पर नज़र रखने के लिए मध्य व वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
4. महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहली बार 'दुर्गा शक्ति' ऐप को 12.07.2018 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 'एक और सुधार' पहल के अंतर्गत शुरू किया गया। कोई भी महिला इस ऐप को डाउनलोड करके पंजीकरण कर सकती है और केवल 'ALERT' बटन को दबाकर संकट के समय तत्काल सहायता ले सकती है। दिनांक 31.12..2019 तक कुल 165328 लोगों द्वारा इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप पर मिली सुचना के तहत अभी तक कुल 56 एफ0आई0आर0 दर्ज की जा चुकी हैं, व 62 मामलों में रोकथाम की कार्रवाई की जा चुकी हैं। इसके इलावा 1079 मामलों का शान्तिपूर्वक निपटारा किया जा चुका है।
5. राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और उनके खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए, महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा संचालित पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन विषेष रूप से प्रत्येक जिले में मुसीबत में फंसी महिला की मदद व त्वरित कार्यवाही हेतु तैनात किए गए हैं। ऐसे 31 पी.सी.आर. वैन राज्य में प्रचलन में है। इन वाहनों पर नियुक्त महिला कर्मचारी प्रशिक्षित, सतर्क और महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनषील है। ये पुलिस कर्मचारी महिलाओं/लड़कियों से प्राप्त अपराध की षिकायत के सम्बन्ध में कॉल पर त्वरित प्रतिक्रिया करते है और सुरक्षा और तत्काल चिकित्सा सहायता, यदि आवष्यक हो, उपलब्ध कराते हैं। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए प्रमुख स्थानों पर गष्त भी करते हैं।
6. 1 मई 2017 से सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए 'आपरेषन दुर्गा' षुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, वर्दीधारी पुलिस इकाईया और सादे कपड़ों में विद्यालयों, कॉलेजों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहनो में शरारती तत्वों पर नज़र रखने, उन्हें समझाने के लिए और उचित कार्रवाई करने के

लिए तैनात किये गयें है। इस उद्देश्य के तहत, समर्पित दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की 30 कम्पनियॉ, 50 मारूति एर्टिगा गश्त वाहन सहित राज्य के सभी जिलों में तैनात की गई है।

7. प्रत्येक जिले के महिला पुलिस थाने में महिलाओं और बच्चों के लिए जिला स्तरीय विशेष इकाई की स्थापना की गई है। यह इकाई जिला संरक्षण अधिकारी के अधीन कार्य करती हैं।
8. कन्या छात्रों के लिए विशेष बसों में सुरक्षित यात्रा प्रदान करने हेतु महिला पुलिस सिपाहियों को तैनात किया जा रहा है।
9. महिला विरूद्ध अपराध की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और उनका पता लगाने के लिए विभिन्न नगर निगमों व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पूरे प्रदेश में दो लाख से अधिक सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरे लगाए गए है।
10. सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष महिला पुलिस दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित के लिए 'मुख्यमंत्री सर्वोत्तम सेवा मेडल' योजना शुरू की है।
11. भारत सरकार द्वारा 11/8/2018 को जारी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 की पालना करने हेतू सभी क्षेत्र इकाइयों को दिशा–निर्देश जारी किए गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि बालात्कार के मामलों की जांच दो महीने मे पूरी की जाएगी। उक्त के सम्बन्ध मे यह निर्णय लिया गया है कि पीडिता और आरोपी के डी.एन.ए. के नमूने का परीक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
12. महिला विरूद्व अपराधों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिलों में एक उप–पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति नोडल आफिसर के तौर पर की गई है।
13. माननीय मुख्यमंत्री की धोषणा दिनांक 12.07.2018 के अर्न्तगत सरकार ने बलात्कार के मामले में दोषी एवं ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ आरोप तय किये गए है को प्राप्त सरकारी सहायता/लाभों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ को छोड़कर) जैसे बुढापा पेंशन/विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति, ड्राइविंग और शस्त्र लाइसेंस इत्यादि को वापिस लेने का फैसला किया है।
14. प्रत्येक पुलिस थाना में बलात्कार और छेडछाड के मामलों में निरन्तर जॉच का प्रावधान होगा। बलात्कार के मामलों की जांच एक महीने में पूरी करने व छेडछाड तथा यौन उत्पीडन के मामलों में 15 दिन के अन्दर जांच पूरी करने के आदेश जारी किए गये हैं। यदि बलात्कार के मामले में जॉच एक महीने के भीतर और छेडछाड के मामले में जॉच 15 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो अनुसन्धान अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
15. सरकार ने यह भी फैसला किया है कि यदि बलात्कार पीड़ित सरकारी वकील के अलावा अपने वकील को शामिल करना चाहती है तो, वित्तीय सहायता के रूप में 22,000/– रू0 की फीस सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
16. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सनसनीखेज मामलों का संचालन करने के लिए सभी उत्कृष्ट अभियोजकों में से एक विशेष सरकारी अभियोजक की नियुक्ती की जा सकती है। इसके अलावा, सरकार ने पब्लिक अभियोजकों को महिलाओं विरूद्व अपराध के मामलों से निपटने और उन्हे पेश करते समय संवेदनशीलता दिखाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के आरोपियों की सजा को सुनिश्चित किया जा सके।
17. महिला विरूद्ध जघन्य अपराधों के मामलों के शीघ्र अभियोजन के लिए वर्तमान में 11 फास्ट ट्रैक कोर्टो की स्थापना अम्बाला, भिवानी, फतेहाबाद, पानीपत, हिसार, झज्जर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल मे की गई हैं। विशेष रूप से

बलात्कार के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए हरियाणा सरकार ने 6 नए (फरीदाबाद में दो और गुरूग्राम, पानीपत, सोनीपत और नूह में एक–एक) शीघ्र निपटारा अदालत (Fast Track Court) स्थापित करने का फैसला किया है।

18. हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गंभीर अपराधों में शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाई गई है। इस नीति के अनुसार बलात्कार के मामलों में धमकियों का सामना करने वाले पीड़ितों और गवाहों को पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

19. हरियाणा पुलिस महिलाओं के लिए राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए तीन–बिंदु कार्य योजना लागू कर रही हैः–

    (क) वर्दीधारी गश्त के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों और जन परिवहन में यौन उत्पीड़न को रोकना ।

    (ख) सादे कपड़ों में तैनाती, महिलाओं के विरूद्ध अपराध के खिलाफ लड़ने में पुलिस का समर्थन करने के लिए स्वयंसेवकों को शामिल करना ।

    (ग) संवेदनशीलता के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने और मजबूत करने और आत्मरक्षा का प्रोग्राम ।

20. महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम और पहचान के प्रति सभी रैंकों के पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जा रहा है। पीड़ितों के साथ अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा गॉव के दौरे और गॉवों में महिलाओं ओर विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं में आत्म विश्वास और विश्वास को प्रेरित करने के तरीके समझाए गए है। गॉव के दौरे के दौरान, स्थानीय स्कूलों/कॉलेजों के मुख्याध्यापक, शिक्षकों के साथ बातचीत की जा रही है। पुलिस जिला अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त जल्द से जल्द अपराध के घटनास्थल पर जा रहे हैं और धटना वाले दिन बलात्कार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं।

21. महिलाओं और बाल शिकायतों को संभालने के लिए, सभी पुलिस आयुक्त/रेंज पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक, हरियाणा द्वारा राज्य में यातायात पुलिस थानों और महिला पुलिस थानों को छोड़कर प्रत्येक पुलिस थाना में महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिला और बाल डेस्क को चलाने के लिए पत्र क्रमांक 381-40/CAW-4 दिनांक 20.12.2012 द्वारा निर्देश दिये गये थें। उस समय से ऐसी महिला और बाल डेस्क बनाए गए है।

22. हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार एवं अन्य अपराधों के पीड़ितों के लिए पत्र क्रमांक 10681/2009/MS/HSLSA दिनांक 31.08.2009 द्वारा एक कानूनी सहायता अभियोजन परामर्श योजना तैयार की है। इस योजना के तहत, प्रत्येक सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधीकरण द्वारा बलात्कार और अन्य महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराध के पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए महिला वकील की नियुक्ति की गई है। इस योजना को सभी पुलिस आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र क्रमांक 46572 दिनांक 15.09.2009 द्वारा कड़ी अनुपालना हेतु प्रसारित किया गया है।

23. राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2012 को जारी हरियाणा मेडिको कानूनी मैनुअल–2012 की प्रति सभी जिला पुलिस प्रमुखों को भेजी जा चुकी है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि जघन्य यौन अपराध जैसे बलात्कार/भेदक यौन आक्रमण के मामलों मे पीड़ित एवं आरोपियों की चिकित्सा जॉच मेडिको कानूनी मैनुअल–2012 के अनुसार की जाए ताकि वैज्ञानिक सबूत संग्रह की गुणवता में सुधार कर सकें और सजा की दर में सुधार किया जा सके और इस प्रकार के मामलों में निवारक प्रभाव पैदा हो सके।

24. हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने यौन हमले के मामलों को संभालने के लिए राज्य में अस्पतालों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। इसमें प्रत्येक जिले के सामान्य

हस्पताल और सब–डिविजनल हस्पताल में यौन आक्रमण उपचार इकाई (एसएटीयू), की सक्रियता, यदि कोई मामला संज्ञान मे लाया जाता है तो, प्रत्येक जिले के सामान्य हस्पताल और सब–डिविजनल हस्पताल में बलात्कार संकट केन्द्र (आरसीसी) की स्थापना और NIC द्वारा तैयार किए गए, MedLEaPR सॉफ्टवेयर, का उपयोग करके हरियाणा मेडिको लिगल मैन्युअल–2012 में निर्धारित प्रारूप पर महिला मैडिकल ऑफिसर/बोर्ड द्वारा मेडिको लिगल रिपोर्ट को तैयार करना इत्यादी शामिल है।

25. राज्य सरकार ने सामान्य रूप से महिलाओं और विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं के खिलाफ अपराध से सम्बन्धित मामलों की निगरानी के लिए दिनांक 12.10.2012 को उच्च अधिकारी को नियुक्त किया है। यह अधिकारी पुलिस महानिदेशक को महिलाओं के विरूद्ध हुए अत्याचार के मामलो मे पंजीकरण के स्तर से लेकर दोषीगण की गिरफतारी एवं मामलो के संचालन की निगरानी करने में सहायता करेंगे। वर्तमान में, पुलिस अधीक्षक स्तर की महिला अधिकारी को पुलिस महानिदेशक, महिला विरूद्ध अपराध की सहायता के लिए तैनात किया गया है।

26. राज्य सरकार ने एक ही छत के नीचे महिला पीड़ितों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर (OSCC) स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में राज्य के सात जिलों–भिवानी, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, नारनौल, फरीदाबाद और गुरूग्राम में ये सेंटर स्थापित किए गए हैं।

27. चिह्नित अपराध योजनाः महिला विरूद्ध जघन्य अपराधों का शीघ्र अन्वेषण और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे मामलों से जुड़े अन्य पहलू, जिनमें पीड़ित को कानूनी सहायता, मुआवजा, परामर्श व चिकित्सा सहायता आदि शामिल है, की कड़ी निगरानी हेतु राज्य सरकार ने जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिला न्यायवादी की जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा बच्चों के खिलाफ अपराध को नियंत्रित/रोकने के लिए उठाए गए कदमों में भामिल हैं :-

1. राज्य स्तर के साथ–साथ जिला स्तर पर भी नियमित अपराध रोकथाम बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सभी क्षेत्र इकाइयों को अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सभी संभव कदम उठाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।
2. पुलिस मुख्यालय अपराध, हरियाणा से जिलों के पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही हैं और उन्हें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में अपराध रोकने हेतु स्थानीय स्तर पर शिक्षित या संवेदनशील बनाने के निर्देश दिये गये हैं।
3. अंतर्राज्यीय अपराध समन्वय बैठकें नियमित अंतराल में आयोजित की जा रही हैं ताकि अंतर्राज्यीय अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान समय पर और पर्याप्त पुलिस सहायता सुनिश्चित हो सके।
4. समन्वय बैठकों के दौरान वास्तविक समय के आधार के साथ–साथ जरूरत के अनुसार जानकारी सांझा सुनिश्चित करना।
5. धारा 82/83 भा.द्र.प्र. के प्रावधानों के तहत भगौड़े व्यक्तियों/अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों/अपराधियों की गिरफ्तारी में स्थानीय खुफिया इकाइयों की सहायता भी ली जा रही है।
6. बच्चों के खिलाफ, विशेष रूप से 12 वर्ष से कम उम्र के, अपराध को रोकने के लिए समय सीमा के भीतर यानी 60 दिनों में जांच पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

7. बच्चों के लापता होने की घटनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है और रिपोर्ट मिलते ही प्रत्येक लापता बच्चे की तलाष के लिए सभी संसाधन लागू किए जाते हैं।
8. जिला क्षेत्र इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वे एफ0आई0आर दर्ज करने से लेकर सक्षम न्यायालय द्वारा मामले के निपटान तक बच्चों के विरूद्ध अपराध को उपयुक्त स्तर पर उचित निगरानी सुनिश्चित करें।
9. सक्षम पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित पी.सी.आर. वाहनों को दिन और रात में गश्त के लिए तैनात किया जा रहा है।
10. सभी क्षेत्र इकाइयों को मादक पदार्थों की आपूर्ति, नशीले पदार्थों के परिवहन में शामिल अपराधियों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। युवाओं को ऐसी बुराई से दूरी बनाने के लिए शिक्षित किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों को नियंत्रितध्रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम।

राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील है और उनकी सुरक्षा और गरिमा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए कई उपाय किए हैंः–

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज मामलों पर नजर रखने के लिए एडीजीपी /एसपी स्तर के अधिकारी की देखरेख में पुलिस मुख्यालय में एक एससी /एसटी संरक्षण सैल बनाया गया है।
2. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों को देखने के लिए प्रत्येक जिले में एक उप पुलिस अधीक्षक, नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत है।
3. एससी/एसटी के खिलाफ अपराध की सूचना मिलने पर, शिकायत के तथ्यों के आधार पर तुरंत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है।
4. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक अराजपत्रित अधिकारी (एनजीओ) तैनात है विषेष रूप ऐसे षिकायतकर्ताओं की सुविधा के लिए जो एससी/एसटी के खिलाफ किए गए अपराधों के बारे में शिकायतों को दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन का दौरा करते हैं।
5. इसी प्रकार, एससी/एसटी की शिकायतों की सुविधा के लिए प्रत्येक महिला पुलिस स्टेशन में एक महिला अधिकारी (एनजीओ/ओआरएस्) की भी नियुक्ति की गई है।
6. सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिस द्वारा षिकायतकर्ता, अभियुक्त या एफ0आई0आर0 या अन्य किसी पुलिस कार्रवाई में जाति के नाम का उल्लेख ना करें।
7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सभी मामलों की जांच के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं।
8. हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति कैलेंडर वर्ष में, पीड़ितों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं और अन्य जुड़े मामलों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, आयोजित की जाती है। अंतिम बैठक 07.02.2020 को आयोजित की गई थी।

हालांकि, एससीध्एसटी के खिलाफ अपराध के मामलों के पंजीकरण में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर तेजी मुख्य रूप से मामलों के निःशुल्क पंजीकरण और राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के बीच बढ़ती जागरूकता के कारण हुई है। अनुसूचित

जातियोंध्कमजोर वर्गों के मन में असुरक्षा की भावना नहीं है। सभी समुदाय भाईचारे और सद्भाव के माहौल में रह रहे हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, श्रीमती गीता भुक्कल जी ने जो क्वैश्चन पूछा था, वह सभी 5 सदस्यों की तरफ से एक ही विषय पर पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको क्लब कर दिया है। इसमें संबंधित विषय पर पहले श्रीमती गीता भुक्कल जी अपना क्वैश्चन पूछें।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, हमें इस विषय पर अलग–अलग सप्लीमैंटरी पूछने का मौका दिया जाए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, एक प्रश्न पर केवल 2 सप्लीमैंट्री ही अलाउड हैं।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि एक विषय पर 5 माननीय सदस्यों ने क्वैश्चन पूछें हैं तो उन सभी माननीय सदस्यों को अलग–अलग सप्लीमैंट्री पूछने का मौका दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, I am only asking for my information. आप जो क्वैश्चन ड्रा ऑफ लॉट्स से निकालते हो तो ये पांच सदस्यों के क्वैश्चन किस प्रकार से क्लब कर दिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं क्वैश्चन ड्रा ऑफ लॉट्स से ही निकलता हूं और पांच क्वैश्चन ऐसे आये थे जो सेम नेचर के थे, इसलिए इन पांचों क्वैश्चनों को मैंने क्लब कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या आप क्वैश्चंज ड्रा ऑफ लॉट्स से ही निकालते हो? आपने मेरे ख्याल से इन पांचों क्वैश्चंज को ड्रा ऑफ लॉट्स से नहीं निकाले हैं। आपको किस प्रकार पता लगा कि इनको क्लब कर दिया जाये? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इन पांचों प्रश्नों का एक ही विषय था, इसलिए मैंने इनको क्लब कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का विषय भले ही एक हो परन्तु प्रश्न तो अलग–अलग सदस्यों ने दिए हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इन प्रश्नों का सब्जैक्ट एक ही है, इसलिए इन प्रश्नों को मैंने क्लब कर दिया है और मैं उन माननीय सदस्यों के नाम बोल रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

िक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : किरण जी, आपको इस बात के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की तारीफ करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय की अच्छी सोच दर्शाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप यह कह दीजिए कि मैंने इन प्रश्नों को ड्रा ऑफ लॉट्स से नहीं निकाले हैं?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, सभी प्रश्नों को ड्रा ऑफ लॉट्स से ही निकाले जाते हैं?

श्री कंवर पाल : किरण जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय सभी सदस्यों के क्वैश्चंज ड्रा ऑफ लॉट्स से ही निकालते हैं?

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, सभी क्वैश्चंज ड्रा ऑफ लॉट्स से नहीं निकलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, प्लीज आप बैठ जायें। किरण जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बातना चाहूंगा कि आप यह बात कह रहे हो कि मैंने इन प्रश्नों को ड्रा ऑफ लॉट्स से नहीं निकाले हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी ड्रा ऑफ लॉट्स के समय उपस्थित थे और उनके सामने ही इन प्रश्नों को निकाला गया था। अगर किसी माननीय सदस्य ने इससे संबंधित क्वैश्चन पूछा है और वह क्वैश्चन ड्रा ऑफ लॉट्स में नहीं आया, फिर मैंने यह देखा कि इन पांचों प्रश्नों का एक ही विषय है और अन्य सदस्यों के भी प्रश्न आये हुए हैं, तो उनको भी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाये इसलिए मैंने इनके द्वारा दिए गए प्रश्नों को भी समान विषय होने के कारण क्लब करने का काम किया है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, देखिय I am only asking for my information. सारे सदस्य अपना–अपना क्वैश्चन लिखकर भेजते हैं। मैंने भी आपको 50 क्वैश्चन लिखकर भेजे थे लेकिन इन प्रश्नों में से मेरा एक ही क्वैश्चन आपने लगाया that is a separate story परन्तु आपने इन पांचों प्रश्नों को किस आधार पर क्लब कर दिया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप इन प्रश्नों को ड्रा ऑफ लॉट्स से नहीं निकालते हो और आप अपनी मर्जी से ही इन प्रश्नों को लगा रहे हो और यह बात आज साबित भी हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इन प्रश्नों का सब्जैक्ट एक ही है। जहां तक ड्रा ऑफ लॉट्स से इन प्रश्नों को निकालने की बात है। मैंने ड्रा ऑफ लॉट्स निकालते वक्त की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई हुई है और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं, उनके सामने ड्रा निकाला गया है हमने कोई अलग से ड्रा नहीं निकाला है। आप यह बात कैसे कह सकते हो कि मैंने ये प्रश्न ड्रा ऑफ लॉट्स से नहीं निकाले हैं, मैंने इन प्रश्नों को लगाते वक्त इस बात की पूरी कोशिश की है कि अधिक से अधिक सदस्य इस पर इन प्रश्नों पर सप्लीमैंट्री कर सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप ड्रा ऑफ लॉट्स में किस प्रकार के प्रश्नों को चिन्हित करते हो?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, हम ड्रा ऑफ लॉट्स में क्वैश्चन नहीं डालते हैं केवल इसमें विधायक का नाम डाला जाता है। जिस विधायक ने प्रश्नों के लिए पूर्ण समय अवधि का पालन किया है उसी हिसाब से प्रश्न लगाये जाते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसे मान लो मैंने 50 प्रश्न भेजें हैं और आपने मेरा नाम एक बार ही ड्रा ऑफ लॉट्स में डाला तो क्या अगली बार मेरा नाम ड्रा ऑफ लॉट्स में नहीं आयेगा?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों की समय अवधि खत्म हो जायेगी तो उसके बाद दोबारा से सदस्यों के नाम आते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न भेजें हैं उन सभी के नाम डालते जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, उन सभी सदस्यों के नाम डाले जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मान लो अगर मुझे 45 सदस्यों ने क्वैश्चन लिखकर भेजें हैं तो 45 सदस्यों का नाम ड्रा ऑफ लॉट्स में डाल दिए जाते हैं, इनमें से 20 सदस्यों का नाम आ गया और 25 बच गये उसके बाद फिर 25 सदस्यों के नाम ड्रा ऑफ लॉट्स में डाल दिए जाते हैं और इनमें से 20 सदस्यों का नाम आ गया और 5 फिर बच गये और जो 5 बच गये हैं, इन पांचों को इन्क्लूड करके 15 और सदस्यों के नाम ड्रा ऑफ लॉट्स में डाले जाते हैं। किरण जी, मेरा मकसद यही है कि हाउस में सभी सदस्यों के क्वैश्चंज लगने चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जिन पांच सदस्यों के क्वैश्चंज क्लब किए हैं? (शोर एवं व्यवधान) यह सिस्टम ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मुझे कोई सदस्य 100 क्वैश्चंज लिखकर भेजेगा, कोई दूसरा सदस्य 50 क्वैश्चंज लिखकर भेजेगा और कोई तीसरा सदस्य 25 क्वैश्चंज लिखकर भेजेगा। (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार कोई न कोई सिस्टम अपनाना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका यह सिस्टम ठीक नहीं लगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अगर आपको यह सिस्टम ठीक नहीं लगता है तो मैं इस सिस्टम को बदल देता हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किरण जी, उसके बाद मुझ पर ब्लैम मत लगाना कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जिन पांच सदस्यों के क्वैश्चंज क्लब किए हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैंने तो इसमें पूरी कोशिश की है कि इन सभी सदस्यों को सप्लीमैंट्री पूछने का मौका मिल सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुककल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप पहले मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान) जब क्वैश्चन का ड्रॉ निकाला गया उस समय आपकी पार्टी के सदस्य भी मौजूद थे। उन्हीं के सामने यह ड्रॉ निकाला गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्म सिंह छोक्कर : स्पीकर सर, मेरा आपको यह कहना है कि इस सैशन में मेरा एक भी क्वैश्चन नहीं लगा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : छोक्कर जी, आपके जो क्वैश्चन लगे हैं मैं आपको उनकी जानकारी दे दूंगा। अभी आप कृपया बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि विधान सभा के इतिहास में अब तक कभी भी इस प्रकार से विभिन्न क्वैश्चंज को क्लब नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि

आपने कौन से नियमों के तहत इन क्वैश्चंज को क्लब किया है? (शोर एवं व्यवधान) मैं इसकी रूलिंग के बारे में जानना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, मैंने क्वैश्चंज को क्लब नहीं किया। यह श्रीमती गीता भुक्कल का सवाल है। उसके बाद मैंने चार सप्लीमैंट्रीज अलाउ की हैं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मलिक साहब से यह कहना है कि आपने ऐसा सिस्टम अपनाकर एक अच्छा और सराहनीय प्रयास किया है। अब ये इस बात पर भी अनावश्यक प्रश्नचिन्ह् उठा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर माननीय अध्यक्ष महोदय इनमें से केवल एक ही प्रश्न को लगाते तो फिर कांग्रेस के माननीय साथी क्या करते? (शोर एवं व्यवधान) ऐसा करके माननीय अध्यक्ष जी ने दरियादिली ही दिखाई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि अगर किसी भी माननीय सदस्य को कवैश्चंज को सिलैक्ट करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शंका है या किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे क्वैश्चन ऑवर के बाद मेरे चैम्बर में आ जायें मैं उनकी तमाम शंकाओं और तमाम संशयों को दूर कर दूंगा। उनको इस सम्बन्ध में वीडियो भी दिखा दी जायेगी और जहां पर ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुए हैं, उसमें जो–जो मैम्बर शामिल हुए थे उनको भी वीडियो दिखा दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) एक क्वैश्चन के ऊपर दो सप्लीमैट्री अलाउ होती हैं मैंने तो इस क्वैश्चन के ऊपर चार सप्लीमैंट्रीज अलाउ की हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप यह चाहते हैं कि अगली बार उसी मैम्बर को सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछने की इजाजत दी जाये जिसका बेसिक क्वैश्चन होगा, तो ठीक है मैं अगली बार ऐसी ही व्यवस्था कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मुझे यह तो बता दिया जाये कि आपने इन सभी क्वैश्चंज को क्लब कैसे किया है?

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, मैंने क्वैश्चंज को क्लब नहीं किया बल्कि मैंने तो इनको चार सप्लीमैंट्री कहा है। मलिक साहब, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सदन में पहले भी इस प्रकार की प्रैक्टिस हो चुकी है यानि क्वैश्चंज क्लब हुए हैं। आप मेरे पास चैम्बर में आ जाना मैं आपके सारे के सारे संशय दूर कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) ऐसा आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब, आप मुझे यह बतायें कि अगर ऐसा होता है और चार लोग इस क्वैश्चन पर बोल पायें तो इससे नुक्सान क्या है? इन सभी क्वैश्चंज का

विषय सेम नेचर का है और सभी मैम्बर भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, प्रत्येक सदस्य अपने अलग–अलग तरीके से क्वैश्चन पूछता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह : स्पीकर सर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस पार्टी के ये लोग 10 साल सत्ता में रहे हैं। अब इनके पास सत्ता तो नहीं रही है लेकिन ये अपने आपको समय के हिसाब से अभी तक भी नहीं बदल पाये हैं। मेरा तो इनको यही कहना है कि इनको अब तो अपने आपको बदल ही लेना चाहिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। मेरे विचार से यही इन सभी के हित में होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मंत्री जी ने एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में गृह मंत्री के नाते जवाब दिया है जो कि बहुत गम्भीर स्थिति है। यह प्रश्न भी उतना ही गम्भीर है जो आज लगा हुआ है इसलिए हमारे साथी इस पर इतना शोर मचा रहे हैं। आज प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है और क्राइम बढ़ रहा है। चाहे वह महिलाओं के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो और बच्चों में भी बच्चियों के प्रति बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। चोरी और डकैती के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपने जो रिप्लाई दिया है उसमें आपने स्वयं माना है और जो नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हुई है जो कि एक चिन्ता का विषय है। इनको कंट्रोल करने के लिए पौलिटिकल विल के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। स्कीम्ज और पॉलिसीज बहुत ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्षः गीता जी, आप अपना सप्लीमैंट्री पूछिए।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में बलात्कार के 1248 केस हुए थे जो अब बढ़ कर 1734 हो गये हैं। इसी प्रकार से महिला उत्पीड़न के मामले 4868 हो गये हैं। दहेज हत्या के मामले भी बढ़े हैं। रोजाना 57 घरों में चोरी हो रही हैं और रोजाना 5 रेप हो रहे हैं। मेरा पहला सप्लीमैंट्री तो यह है कि क्राइम अगेंस्ट वूमन और जनरल क्राइम जिसमें चोरी, डकैती और लॉ एण्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। तो इस बारे में मेरी पहली सप्लीमैंट्री यह है कि who is the nodal Department and who is

the nodal agency. यह मामला महिला एवं बाल विकास विभाग से भी जुड़ा हुआ है और इसमें स्टेट कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स भी है, पॉक्सो एक्ट भी है और वुमैन कमीशन भी है, तो क्या यह केवल गृह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? आपने जो स्कीम्ज लिखी हैं वे ज्यादातर महिला एवं बाल विकास की स्कीम्ज हैं तथा कुछ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की भी हैं। इसलिए यह बताया जाए कि नोडल ऐजेन्सी कौन सी है? बहुत सारी जो स्कीम्ज आपने इसमें मेन्शन की हैं क्या एक्ट, कानून, हैल्पलाईन, पुलिस स्टेशन, वन स्टॉप सैन्टर, पॉक्सो एक्ट तथा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड होने के बावजूद भी क्या कारण है कि नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह बताते हैं कि हरियाणा में स्थिति बहुत खराब है। मेरा पहला सप्लीमैंट्री नोडल ऐजेन्सी का है और दूसरा लॉ एण्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ तथा तीसरा प्रश्न यह है कि एग्जिक्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? स्कीम्स तो हैं पर इनका क्या एग्जिक्यूशन है? क्यों हम बद से बदतर होते जा रहे हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, जो क्राइम अगेंस्ट वूमैन के आंकड़े हैं उनमें वर्ष 2018–19 में 3.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसमें स्लाइटली इनक्रीज हुआ है। इसी प्रकार से वर्ष 2018–19 में क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में 3.8 प्रतिशत की कमी आई है और क्राइम अगेंस्ट अदर विक्कर सैक्शन 7.9 प्रतिशत बढ़ा है। हमने इसको कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने लगभग 30 महिला थाने खोले हैं और दुर्गा शक्ति ऐप हमने लांच की है और अब तक 1,66,920 लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं। ओवरऑल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अगर देखा जाए जिसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं तथा सभी आ जाते हैं। अगर पुलिस एक डिस्ट्रैस टाईम पर जल्दी लोगों तक पहुंच पाए तो भी क्राइम रेट कम हो सकता है। इसके लिए हम डायल 112 चालू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने सी–डैक को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तथा पुलिस पर्सोनल को ट्रेनिंग देने का कांट्रैक्ट हमने अलॉट कर दिया है तथा उनके साथ इस बारे में एम.ओ.यू. साईन हो चुका है। हम 630 नई गाड़ियों की खरीद करने जा रहे हैं। हर थाने में 2–2 गाड़ियां दी जायेंगी। कॉल आने पर 15 मिनट के अन्दर–अन्दर पुलिस पहुंचेगी। हम काफी कदम उठा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, जो फंक्शनिंग ठीक कर रहे हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं उसी के कारण वर्ष

2018–19 में जो क्राइम रेट डाउन आया है वह वर्ष 2019–20 में और डाउन आयेगा, हम इसको और इम्प्रूव करेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहती हूं कि हम लोग इस मैटर को लेकर बहुत गम्भीर हैं। हमने बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओं का नारा भी दिया हुआ है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे विभाग इनवॉल्व हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इसमें चूंकि बहुत सारे विभाग इनवॉल्व हैं तो किसी एक विभाग को या एक ऐजेन्सी को नोडल विभाग या नोडल ऐजेन्सी क्यों नहीं बनाया जाता है? यह चिन्ता का विषय है क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और कुछ नैशनल रिपोर्ट्स भी हैं। इसके लिए हमें अपनी सोशल विल और पौलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी। मैं इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहती हूं। क्राइम चाहे हमारे समय में बढ़ा हो या अब बढ़ रहा हो लेकिन यह चिन्ता का विषय है क्योंकि हरियाणा में क्राइम सामान्य तौर पर इंक्रीज हो रहा है। यही कारण है कि बाहर से हरियाणा में इंडस्ट्रीज अर्थात फैक्ट्रिज नहीं आ रही हैं। मेरे झज्जर में हुडा सैक्टर में इक्ट्ठे 5 मर्डर हुए हैं लेकिन वह आज तक ट्रेस नहीं हुए हैं। सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी क्या कारण है कि वे ट्रेस नहीं हो रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री केवल मात्र मेरे एक सप्लीमैंट्री का जवाब दे दें। क्या सरकार ने इसके लिए ऐसी कोई नोडल एजेंसी, नोडल विभाग या कोई ऐसा ठोस प्रयास किया है? माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी हुआ है और बजट भी पेश हुआ है, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि Who will be responsible for it? I mean to say that which department will be responsible for it? कृपा करके माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब सदन में जरूर दें ताकि हम सभी लोग मिलकर इस गम्भीर विषय को गम्भीरता से लेते हुए प्रदेश की तरक्की में जो योगदान होना चाहिए उसको निभा पाएं।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, इसके लिए होम डिपार्टमैंट रिस्पोंसिबल है। होम डिपार्टमैंट ही सारा सिस्टम कंट्रोल करता है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस स्टेशंज हैं। उसमें से एक महिला ए.एस.आई. को पीट दिया गया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी की महिला पुलिस स्टेशंज और बाकी

पुलिस स्टेशंज को भी आप Fully empowered with equipments कीजिए क्योंकि अधिकतर पुलिस स्टेशंज में लाठी डंडों वगैरह भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, महिला पुलिस स्टेशंज में जो ऑफिसर्ज नियुक्त हैं उनको सबसे पहले बढ़िया से बढ़िया असला प्रोवाईड करें और उनको इम्पावर्ड करें। धन्यवाद।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हम ऑफिसर्ज को इम्पावर्ड करेंगे और उनको ट्रैनिंग भी दिलाएंगे। उनको हम साईकोलोजिस्ट भी मुहैया कराएंग। महिला थानों के साथ एक डी.एस.पी. भी अटैच किया गया है ताकि उनकी फंग्शनिंग को और अच्छे ढंग से चलाया जा सके।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जो क्राइम रेट के आंकड़े दिये गये हैं, इसमें जो लेटेस्ट आंकड़ा है वह 7.9 प्रतिशत दिखाया गया है इसको एक बार वैरीफाई कर लें क्योंकि अब क्राइम रेट 9.45 प्रतिशत है। इसका मतलब क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। महिलाओं में भी क्राइम रेट की बढ़ौत्तरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो आजकल साईबर क्राइम चल रहा है क्या उसके लिए कोई अलग से विंग बनाई गई है? अगर अलग से विंग है तो कितनी जगहों पर ये साईबर क्राइम के ऑफिसिज हैं? आजकल जो ऑन लाईन के नाम पर ठगी चल रही है, उसमें साईबर क्राइम के कितने मामले ट्रेस किये गये हैं? इस साईबर क्राइम में कितना स्टाफ लगाया हुआ है? यह भी माननीय मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि विकर सैक्शन में 7.9 प्रतिशत क्राइम इन्क्रीज हुए हैं। जो हमारे लिए चिन्ता का कारण है। वर्ष 2018 में क्राइम के केस 1016 थे और वर्ष 2019 में क्राइम के केस 1097 हो गये हैं। सर, फिर भी हमने सभी चीजों पर नियंत्रण रखा हुआ है। हमारे राज में कोई मिर्चपुर कांड नहीं हुआ है। हमारे राज में कोई गोहाना कांड नहीं हुआ है। हमारे राज में डी.जी.पी के ऑफिस के आगे किसी को आत्मदाह नहीं करना पड़ा है। हम हर तरफ से चौकस हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमैंट्री है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपने सप्लीमैंट्री पूछ लिया है।

श्री चिरंजीव राव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर पिछले 10 महीनों में तकरीबन 1400 रेप की घटनाएं और तकरीबन 150 गैंगरेप की घटानाएं हुई हैं। हरियाणा के अन्दर तकरीबन हर दिन 5 रेप होते हैं और हर दूसरे दिन गैंगरेप होते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सैंटरल गवर्नमैंट की तरफ से हमारी स्टेट गवर्नमैंट को कितना निर्भया फंड मिला है और उसमें से हमारी स्टेट गवर्नमैंट कितना यूज कर पाई है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, निर्भया फंड से रिलेटिड यह एक सैपरेट क्वैशचन है जिसमें डाटा वगैरह का मसला है अतः इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी लेने के पश्चात ही माननीय सदस्य को कुछ बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जब यह डाटा आपके पास आ जाये तो आप इस संबंध में लिखकर माननीय सदस्य को जरूर सूचित कर दें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निर्भया फंड का बहुत कम फंड का प्रयोग किया गया है। मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक सैंटर से 16 करोड़ 70 लाख रूपये हरियाणा को प्राप्त हुए थे जिसमें से मात्र मात्र 6 करोड़ रूपये ही हरियाणा प्रदेश में प्रयोग किए गए हैं। अतः ऐसी अवस्था में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इतना कम पैसा क्यों प्रयोग किया गया?

श्री अध्यक्षः चिरंजीव जी, माननीय मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे ही दिया है कि वे आपको लिखकर बता देंगे, अतः अब आप प्लीज बैठिए।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं निर्भया फंड का सारे रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करके लिखित में माननीय सदस्य को उनके प्रश्न का जवाब दे दूंगा।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के जवाब के संदर्भ में दो बातें पूछना चाहूंगा। महिलाओं और बच्चियों के साथ जो बलात्कार और गैंगरेप की घटनायें घटती हैं उनके संदर्भ में कहा जाता है कि ऐसे केसिज में निश्चित समयावधि में सभी तरह के एक्शन ले लिए जाते हैं लेकिन अकसर देखते में आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे अनेकों केसिज हैं जिनमें निश्चित समयावधि का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यदि इस तरह के केसिज में

निश्चित समयावधि में एक्शन नहीं होता है तो क्या सरकार की तरफ से संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाती है? ऐसी केसिज में यदि देरी होती है तो इससे पीड़िता बहुत हताश हो जाती है। इस तरह के केसिज में मुकदमा हो जाता है, एफ.आई.आर. दर्ज हो जाती है तथा इंवेस्टिगेशन हो जाती है लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि बावजूद इस तरह की एक्टिविटी के बाद भी कंविक्शन रेट बहुत कम होता है और इसकी वजह से रेप की घटनाओं को अंजाम देने वालों का हौंसला बढ़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस तरह के केसिज में अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं? अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसिज में मॉनिटरिंग और कंविक्शन रेट में बढ़ौतरी करके ही अंकुश लगाया जा सकता है। सरकार द्वारा इस दिशा में बार–बार कड़े कठोर कदम उठाने की बात कही जाती है लेकिन कंविक्शन रेट कम होने का दुष्प्रभाव यह होगा कि जो कल्प्रिट है वह स्कॉट फ्री हो जाता है जिसकी वजह से समाज में गलत मैसेज जाता है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, अगर रेप के केसिज में कोई अपराधी कंविक्शन में कमी रहने की वजह से या किसी और लापरवाही की वजह से छूट जाता है तो ऐसे केसिज के संदर्भ में मैंने अपने विभाग में आदेश जारी कर दिए है तथा इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर भी आया है कि जिन अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ होता है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विभाग में बाकायदा तौर पर लिखकर दिया है कि ऐसे केसिज जिनमें कंविक्शन में अधिकारियों की वजह से कोई कमी रह गई है, ऐसे शत–प्रतिशत केसिज को एग्जामिन किया जायेगा और उनके संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जायेगा।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, भाई आफताब जी ने अभी बताया कि वर्तमान हालात में क्राइम रेट बढ़ रहा है और कंविक्शन रेट घट रहा है, के संदर्भ में मैं भी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यह कंविक्शन रेट घटकर 13 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। सरकारी वकील केस लड़ने में इतने समर्थ नहीं होते हैं और न ही मेहनत करके जाते हैं और कई बार सरकारी वकील मौके पर जाकर हाजिरी नहीं देते हैं या फिर तारीख पर तारीख लेते रहते हैं और तंग होकर पीड़ित परेशान होकर बैठ जाता है। यह बहुत गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ–साथ मेरा मानव तस्करी के संबंध मे एक दूसरा प्रश्न भी है। मैंने इसके

बारे में लिखकर भी दिया था लेकिन मेरा प्रश्न नहीं लगा लेकिन बावजूद इसके मैं अब अपने पहले प्रश्न के साथ माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से मानव तस्करी की घटनायें बढ़ती जा रही है, इन घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गए हैं? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अब तक 28 लड़कियां गुमशुदा हैं उनमें से अब तक कितनी लड़कियां बरामद की गई हैं? अगर बरामद नहीं की गई हैं तो क्यों नहीं की गई हैं?

श्री अनिल विजः सर, मैं इस सदन में पहले भी अपने विभाग से जुड़े प्रश्न के बारे में बड़ी गम्भीरता के साथ बता चुका हूँ और एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कंविक्शन रेट बढ़े इसके लिए हमने अनेकों कदम उठाये हैं और इस दिशा में मैंने अपने विभाग में लिखकर आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर कहीं पर कंविक्शन रेट में कमी रहती है तो उसका चाहे जो भी कारण रहा हो या किसी भी स्तर पर रहा हो निःसंदेह हर हाल में उस कारण व स्तर के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।

.....

To Make Hisar Free From Railway Crossing

***19. Dr. Kamal Gupta :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to make Hisar City free from railway crossings; if so, the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला): नही श्रीमान् जी।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हिसार जिले में 11 रेलवे क्रासिंग्ज हैं जिसमें से सरकार के पिछले कार्यकाल में 2 पर काम पूरा हो चुका है और 2 पर काम चल रहा है और 1 एप्रूव्ड है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो बाकी 6 रेलवे क्रासिंग्ज बचे हैं और जैसाकि बजट के 146वें प्वॉयंट में कहा भी गया है कि हरियाणा सरकार मुख्य जिला सड़कों पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग की जगह रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण करेगी के संदर्भ में मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो बाकी 6 रेलवे क्रॉसिंग्स रह गए हैं उनका भी प्रोसैस शुरू करके उन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए ताकि शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हिसार में 11 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं । मैं उनको करैक्ट करना चाहूंगा । वहां पर 11 की बजाय 13 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं । इनमें से 4 रेलवे क्रॉसिंग्स पर काम कम्पलीट कर दिया है, 3 रेलवे क्रॉसिंग्स पहली, सूर्य नगर वाली एल.सी. 89 और 60, दूसरी सदर्न बाइपास सैक्टर–16 और सैक्टर एल.सी. 4 ए., तीसरी हिसार से कैमरी रोड एल.सी. 6 बी. पर काम चल रहा है । इनके अलावा बालसमंद डिस्ट्रिब्यूट्री पर रेलवे लाइन है । उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है और उसका जी.ए.डी. (जनरल अरेंजमैंट ड्रॉइंग) बनने के लिए दिया जा चुका है । वहां पर स्ट्ड फार्म के साथ एक सड़क है । वह स्ट्ड फार्म आर्मी का है । हमने उसके लिए आर्मी से आग्रह किया था कि वह जमीन हमें दे दें लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया । अतः अब हम उसका पुनः जी.ए.डी. बनवा रहे हैं ताकि उसको किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए । इसके अलावा हमने बचे हुए ब्रिजिज की रिपोर्ट मंगवाई है । रिपोर्ट के आ जाने के बाद हम उसे चैक करेंगे । हमारी सरकार का प्रयास है कि जहां यात्रियों और गाड़ियों की अधिक क्रॉसिंग है और अत्यधिक सघन क्षेत्र है उनको हम जीन्द के बाइपास या रोहतक के रेलवे ब्रीच जैसी सुविधा उपलब्ध करवा दें । इसके लिए उनकी स्टडी करवायेंगे ।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में यमुना नदी पर 2 पुल सनौली और कुरड़ी नांगल में बने हुए हैं । वहां पर यू.पी. के बिलासपुर से हमारे समालखा से होते हुए वह ट्रैफिक नैशनल हाइवे तक जाता है लेकिन वह रास्ता सिंगल है ।

श्री अध्यक्ष : धर्म सिंह जी, यह प्रश्न हिसार के लिए पूछा गया था । आप बिल्कुल अलग ही प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यू.पी. के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक बैठक हुई थी । उस बैठक में पैंडिंग पड़े हुए 4 पुलों को बनाने की मंजूरी हो चुकी है। उनमें से 1 पुल हरियाणा सरकार, 1 पुल एन.एच.ए.आई. और 2 पुल यू.पी. सरकार बनाएगी । अगर माननीय सदस्य का एन.एच.ए.आई. से संबंधित अलग से कोई प्रश्न है तो मैं उसके बारे में भी माननीय सदस्य को रिटन में रिप्लाई दे दूंगा ।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई नया पुल बनवाने की मांग नहीं कर रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि जो पुल बने हुए हैं उनसे नैशनल हाइवे की तरफ जाने वाला रोड़ सिंगल है । वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए उस रोड को फॉरलेन बनाकर स्टेट हाइवे का दर्जा दिया जाए । इसके अलावा गांव मनाना और गांव चुल्काना में जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, को क्रॉस करने वाले रोड को आगे नैशनल हाइवे तक मिला दिया जाए ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद बजट को पूरा नहीं पढ़ा है । हमारी सरकार ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि प्रदेश में अगर कोई भी एन.डी.आर. स्टेट हाइवे होगा तो उसको फाटक मुक्त किया जाएगा । इसके अलावा माननीय सदस्य जिस सड़क की बात कर रहे हैं उसको भी 10 मीटर चौड़ी करने का प्रपोजल ऑलरेडी हमारी सरकार के पास है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है । (शोर एवं व्यवधान)

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र□नों के लिखित उत्तर

Construction Work of University

***128. Shri Leela Ram :** Will the Education Minister be pleased to state the time by which the construction work of Maharishi Balmiki Sanskrit University in village Mundri, district Kaithal is likely to be started?

□िक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : महोदय, महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, गांव मुंदरी, जिला कैथल का निर्माण कार्य छः महीने के भीतर आरम्भ होने की संभावना है।

To Release Electricity Connections

***264. Smt. Naina Singh Chautala:** Will the Power Minister be pleased to state the time by which the electricity connections for tubewells are likely to be released by the Government in Dark Zone area together with the details thereof?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : इस संदर्भ में कोई भी समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों/डार्क जोन में कोई भी कृषि नलकूप कनैक्शन जारी नहीं किया जा सकता।

Replacement of Flow Pumps

***114. Shri Mamman Khan :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace Banarsi Distributary canal's three 35 CS vertical axial flow pumps which were installed since it came into existence at Ranyala Patakpur Pump House of Ferozepur Jhirka in District Nuh;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace obsolete electrical cables at Ranyala Patakpur Pump House of Ferozepur Jhirka in District Nuh; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Umra Landwha Nullah and Akera cunnette to L-Section at District Nuh?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां, श्रीमान जी। गांव रनयाला में बनारसी पम्प हाऊस के तीन पुराने पम्पों के प्रतिस्थापना के लिए 98.00 लाख रू0 का परियोजना प्राक्कलन को अगली विभागीय स्थायी तकनीकी समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा ।

(ख) हां, श्रीमान जी। गांव रनयाला में बनारसी पम्प हाऊस में बिजली की तारों को एक माह में बदल दिया जाएगा।

(ग) हां, श्रीमान जी। लैडंवाह नाले (उमरा नाला) की बुर्जी 0 से 26956 फीट तक के सैक्शन को अपने वास्तविक डिजाईन पर लाने के लिए प्रस्ताव हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 51वीं बैठक में स्वीकृत किया गया । यह कार्य 30.06.2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अकेरा क्यूनेट की आन्तरिक सफाई का कार्य भी 30.06.2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

Vacant Post of Doctors

***159. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the vacant posts of doctors in Civil Hospital, Gohana and CHCs and PHCs of Gohana Assembly Constituency are likely to be filled up togetherwith the details thereof ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, मार्च 2020 में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर चिकित्सकों के रिक्त पद भर लिए जाएंगे।

To Replace Old Sewerage Pipe Line

***286. Shri Surender Panwar :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the steps taken by the Government to improve the sewerage system in Sonipat City togetherwith whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the 40 years old sewerage pipe line which was laid without level?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, अमृत के अन्तर्गत सोनीपत में 106.60 करोड़ रू की लागत का सीवरेज सिस्टम के सुधार का कार्य प्रगति पर है, जिसमें 1,55,847 मीटर की नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है। ककरोई में स्थित एसटीपी के संचालन के लिए हाल ही में 527.00 लाख रू की राशि का एक कार्य भी आबंटित किया गया है जिसमें मेन पम्पिंग स्टेशन तक की 1100 मि.मी. व्यास और 1400 मि.मी. व्यास की मौजूदा सीवर लाइन का सुदृढ़ीकरण करना शामिल है ।

'अमृत' के तहत सोनीपत शहर में 14,000 मीटर की पुरानी सीवर लाइनों को बदलने का कार्य भी प्रगति पर है।

Shortage of Staff in Hospitals

***238. Shri Jagdish Nayar:** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of staff in hospitals of Hasanpur and Hodal; if so, the time by which the shortage of staff in abovesaid hospitals is likely to be metout?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, मार्च 2020 तक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने पर व विभाग के अन्य पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजे हुए मांग पत्र के फलस्वरूप नियुक्ति कर दी जाएगी।

अतारांकित प्र□न उत्तर

To Set-Up 33 K.V Sub-Station

17. Dr. Krishan Lal Middha : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33 K.V sub-station in village Bohatwala of Jind Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be set-up?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : हां श्रीमान। इसके 31.03.2021 तक चालू हो जाने की संभावना है।

To Set-up Sub-Division In Raipur Rani

18. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up sub-division in Raipur Rani in Kalka Constituency; if so, the time by which it is likely to be set-up?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

To Construct a Distributory

71. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a distributory from Sayana minor upto Dadhi Chhillar Boundry; if so, the time by which it is likely to be constructed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): नहीं, जी।

To Open Veterinary Hospitals

72. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal

under consideration of the Government to open Veterinary Hospitals in villages Kari Dharni, Kubja Nagar, Mehra, Mandoli and Ladawas of Badhra Assembly Constituency; if so, the time by which these are likely to be opened?

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल) : नहीं जी।

To construct Vyayamshalas

73. Smt. Naina Chautala : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Vyayamshalas in the villages Bhandwa, Bijna, Mandoli, Mai Khurd, Shishwala, Mandola and Surajgarh of Badhra Assembly Constituency?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : नहीं, जी।

To Construct Sports stadium

74. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct sports stadium in the villages Kubja Nagar and Dudhwa of Badhra Assembly Constituency?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

To Develop Food Park

42. Shri Amit Sihag : Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Food processing plant and to develop the Food park in Dabwali constituency in order to promote the marketing of orange and other agriculture produce in Dabwali Constituency; and

(b) If so, the time by which these are likely to be set up/Developed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) राज्य सरकार हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018 के प्रावधानों के अनुसार हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। सरकार प्रसंस्करण के संवर्धन और सुविधा के लिए राज्य में पहचान किए गए बागवानी समूहों में संतरे और अन्य कृषि की ऊपज के पैदावार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है ।

(ख) (क) की प्रतिक्रिया को देखते हुए कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

Kilometer Scheme Scam

28. Shri Kuldeep Bishnoi : Will the Transport Minister be pleased to state the action taken by the Government against the persons involved in kilometre scheme scam carried out in Haryana Roadways?

परिवहन मंत्री (श्री मूलचन्द भार्मा) : श्रीमान् जी, किलोमीटर स्कीम में कोई घोटाला नहीं हुआ क्योंकि इन बसों को कभी पुरानी दरों पर किराए पर नहीं लिया गया था। चूंकि कोई घोटाला नहीं था, किसी भी व्यक्ति के घोटाले में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता।

Accumulation of Dirty Water Under the Bridge

81. Shri Lakshman Napa : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the dirty water is accumulated under the bridge on Ratia Budhlada road above the Ghaggar River for which the Hon'ble Chief Minister has announced two crores rupees on 31st October, 2018 at Bhuna (Fatehabad) but no action has been taken on it till to date?

उप–मुख्यमंत्री (दुष्यन्त चौटाला) : श्री मान्, रतिया बुढलाडा सड़क पर घग्गर नदी के ऊपर बने पुल के नीचे नदी का बेड लेवल के ऊंचे उठे होने के कारण गंदा पानी एकत्रित होता है। लेकिन इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई थी। समस्या को हल करने के लिए सरंचना के सुधार हेतु 94ण80 लाख रूपये का प्राक्कलन किया गया है और अनुमानित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य किया जाएगा।

Reservation to the Local Youth in Industries

88. **Shri Nayan Pal Rawat** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) Whether it is a fact that there is provision of 25% reservation to the local youth in industrial jobs in State; and

(b) if so, the action taken against the Industries which have not being following the said provision?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी,

(क) नहीं! राज्य में स्थानीय युवाओं को औद्योगिक नौकरियों में 25 प्रतिशत आरक्षण का कोई ऐसा प्रावधान नहीं हैः

(ख) चूकि कोई ऐसा प्रावद्यान नहीं है, इस कारण उद्योगों के विरूद्व कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

Details of Government Schools

86. Shri Nayan Pal Rawat : Will the Education Minister be pleased to state the following details of Government schools in Prithla Legislative Assembly for the last five years-

(a) the number of Government schools upgraded;

(b) the number of school buildings renovated; and

(c) the number of new schools buildings constructed togetherwith the extent of amount spent on above said works ?

शिक्षा मंत्री (श्री कवंर पाल) :

(क) महोदय, पृथला विधानसभा में 11 राजकीय विद्यालयों को स्तरोन्नत/अपग्रेड किया गया है, जिनमें से 02 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है, 04 विद्यालयों को माध्यमिक से वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया गया और 05 विद्यालयों को उच्च से वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत/अपग्रेड किया गया पिछलें पाँच वर्शो के दौरान।

(ख) उपरोक्त विद्यालयों के भवनों को पिछले पाँच वर्शो से पुननिर्मित नहीं किया गया है।

(ग) पृथला विधानसभा क्षेत्र में पिछलें 5 वर्शो के दौरान केवल राजकीय मॉडल वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर बिलोच की नई इमारत का 322.40 लाख रुपये की राषि से निर्माण करवाया गया है।

To Link theDhanies Electricity Connection-with Village Electricity Line

80. Shri Kuldeep Bishnoi : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to release new electricity connections and to link the electricity connection with regular electricity line to dhanies of villages in Aadampur Constituency alongwith to replace low capacity transformers with high capacity transformers?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान, आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य में ढाणियों को बिजली कनैक्शन देने की नीति पहले से ही है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई ट्रांसफार्मर कम क्षमता का पाया जाता है, तो आवश्यकता अनुसार इसे उच्च क्षमता के साथ बदल दिया जाएगा।

To Construct Bye-Pass

82. Shri Lakshman Napa : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the traffic is a big problem in Ratia city due to which traffic remain Jammed in the city all the time; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye pass in Ratia City if so, the details thereof ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : क व ख नहीं, श्रीमान जी।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको धान घोटाला, माइनिंग घोटाला आदि विभिन्न विषयों पर कॉलिंग अटैंशन मोशंज दी हुई हैं । उनका क्या फेट है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र सिंह जी, आपकी दी हुई 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज हमने ऐडमिट की हुई हैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी दी हुई कॉलिंग अटैंशन मोशंज को ऐडमिट ही नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज के अलावा बाकी सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज रिजैक्ट कर दी गई हैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप जीरो ऑवर चलाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप जिस विषय को जीरो ऑवर में रेज करना चाहते हैं उस परा बजट पर चर्चा करते हुए अपनी बात रख लीजिए । (शोर एवं व्यवधान) कल ओलावृष्टि के विषय पर आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन लगा हुआ है । उस पर आप कल चर्चा करना । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य चिंतित हैं, उनकी चिंता का कारण पिछले दो दिनों में प्रदेश में हुई बारिश और ओलावृष्टि है । हमारे पास इससे हुए नुकसान के बारे में कई जिलों की रिपोर्ट आई है । मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने फसल में ज्यादा नुकसान वाले क्षेत्रों के लिए स्पैशल गिरदावरी के लिए आदेश कर दिए हैं और अगले दो दिन में स्पैशल गिरदावरी की रिपोर्ट आ जाएगी ।

.....

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बजट पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ होगी और श्री असीम गोयल जी चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री असीम गोयल (अंबाला शहर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं अपनी बात रखने से पहले कहूंगा –

यकीन हो तो कोई रास्ता जरूर निकलता है,
हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है ।

इस तरह की सोच को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के नाते इस सामान्य बजट को पेश करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, बजट सरकार की नीति और नीयत का आइना होता है । सरकार किस नाते हरियाणा के

निवासियों को कौन–सी सुविधाएं देना चाहती है, उनके बारे में क्या सोचती है, क्या विजन रखती है, इस सारे विजन डॉक्यूमैंट को बजट के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस महान सदन में रखा है । यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सभी सांसदों, विधायकों, जिला परिषद के चेयरमैनों, विभिन्न व्यापारिक संगठनों और अन्य संगठनों से विचार–विमर्श करने के बाद बजट बनाया गया है । जिस प्रकार से समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलता है उसी प्रकार यह बजट इस बार जनता के लिए अमृत और संजीवनी का काम करने वाला है । यह बजट सर्वहितकारी और सर्वस्पर्शी है । सरकार ने प्री–बजट डिस्कशन में सभी विधायकों के सुझाव लिये गए जबकि आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया था । पहले वित्त मंत्री को यह लगता था कि विधायक अपने हल्कों की समस्याओं और अन्य मांगों के लिए पैसा मांगेंगे तो इतना बजट कहां से आएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के नाते बड़े उदार मन से प्री–बजट डिस्कशन करवाकर इस बजट को रखने का काम किया । मेरा विश्वास है कि हर सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने वाला, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि के माध्यम से आजीविका कमाने वाला आम हरियाणवी इस बजट के माध्यम से अपने जीवन में एक सुगमता महसूस करेगा । अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा हमारी परम्परागत और सांस्कृतिक तरीकों को समेटे हुए है । आधुनिकता के नाते इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में हमारे हरियाणा प्रदेश के गुरूग्राम का नाम है । अध्यक्ष महोदय, आज भी जब मेहनतकश किसान, मजदूर सभी सुबह उठकर खेत में जाते हैं तो वे इंद्र देवता को अपनी फसल का भाग्यविधाता मानते हैं । पक्षियों के कलरव से सुबह उठते हुए और शाम की बोध धूलि की उस पवित्र वेला तक वह दिन–भर अपना पसीना बहाता है । इसके अलावा साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरूग्राम पूरी दुनिया में हरियाणा का परचम लहरा रहा है । यह सब हरियाणा के मेहनतकश लोगों की वजह से है और इन मेहनतकश लोगों को और मजबूत करने की अवधारणा इस बजट में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है । आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मजबूत राज्य के लिए मजबूत नागरिक होने जरूरी हैं । यह बजट अपने नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करवाने वाला का बजट है । वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय में 35.5 परसैंट की बढ़ौत्तरी हुई है यानी वर्ष 2018–19 में प्रति व्यक्ति आय 1,59,409 की तुलना में वर्ष 2019–20 के अन्दर 1,80,026 रुपये प्रति

व्यक्ति आय हुई है। इसमें प्रति व्यक्ति आय में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2019–20 के अनुमान के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय 2,64,207 रुपये हो जाएगी। जोकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 रुपये की तुलना में दोगुनी है। यह हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वर्ष 2020–21 में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलायी हैं। उदाहरण के तौर पर सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग से संबंधित, पिछड़े वर्गों से संबंधित, अनुसूचित जाति से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, बागवानी से संबंधित, कृषि, मत्स्य और सिंचाई से संबंधित बहुत सी योजनाओं को त्रैमासिक व्यय की सीमा से निकालने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से इस पूरे साल के लिए इन महत्वपूर्ण डिपार्टमैंट्स को निर्बाध रूप से पैसे की सप्लाई होती रहेगी। माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मुख्य मंत्री के साथ–साथ वित्त मंत्री की अवधारणा से निकालकर कॉमन मैन और फील्ड मैन के लिए संबंधित बजट बनाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुख्य रूप से चार पिलर बजट के अन्दर रखे हैं। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन शामिल हैं। इस पूरे बजट में हरियाणा प्रदेश का कोई ऐसा सर्वस्पर्शी प्वॉयंट नहीं है जिसको लाभ पहुंचाने की कोशिश न की गयी हो। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपनी बात में कहा कि सभी वर्गों के समुदायों को इस बजट के माध्यम से कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। इस बजट में लगभग 300 प्वॉयंट्स हैं। इस बजट में प्रमुख रूप से चार बातों पर अधिक ध्यान दिया गया है। आज हरियाणा प्रदेश का कुल बजट 1,42,343.78 करोड़ रुपये का हो गया है। यह हरियाणा प्रदेश का अब तक का सर्वाधिक बजट पेश किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा किः–

इस मोड़ पर ना घबराकर आप जाइए,
जो बात नयी है उसको आप अपनाईये,
डरते हैं नयी राह पर चलने से क्यों,
हम आगे–आगे चलते हैं, पीछे–पीछे आइये आप।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि वे कहां पर जाने की बात कह रहे हैं ?

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उनके पास बजट की किताब है, इसलिए वे उसको पढ़ लें। इसमें लगभग 300 प्वॉयंट हैं, उनको पढ़ने से सभी बातों के बारे में पता चल जाएगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री असीम गोयल जी को बताना चाहूंगा कि इस बजट की किताब में 302 प्वॉयंट्स हैं।

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने यही कहा था कि इस बजट की किताब में लगभग 300 प्वॉयंट्स हैं। अध्यक्ष महाहेदय, इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि सक्षम छात्रवृति योजना के तहत पांचवी कक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्याथियों, छठी और सातवीं कक्षा तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,500 से 6,000 रुपये तक की छात्रवृति देने की योजना बनायी है। पहली बार हरियाणा प्रदेश में 4,000 प्ले– वे स्कूल्ज बनाने की व्यवस्था करने की बात की गयी है। यानी पहले जिन बच्चों को शुरू में आंगनवाड़ियों में भेजा जाता था। अब 4,000 आंगनवाड़ियों को प्ले वे स्कूल्ज में परिवर्तित किया जाएगा ताकि बच्चों का बचपन से शिक्षा के नाते से जो विकास होना चाहिए, वह हो सके। इसके अतिरिक्त 5,00 नये क्रैचिज कामकाजी महिलाओं के लिए खोले जाएंगे। प्रदेश में पहले केवल 22 मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय थे और अब हरेक ब्लॉक के अन्दर एक–एक के हिसाब से 119 लेट्स्ट मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय खोले जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बस्ता मुक्त और अंग्रेजी माध्यम के 418 प्राथमिक विद्यालय हैं। ऐसे 1,000 और प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020–21 के बजट के माध्यम से 1487 वरिष्ठ माध्यमिक साइंस स्ट्रीम विद्यालयों को स्मार्ट क्लासिज में परिवर्तित करने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। पहली बार हरियाणा प्रदेश के स्कूल्ज में आर.ओ. से शुद्ध पेयजल मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा था कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। इस नाते से जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं, उनमें विज्ञान विषयों को बढावा देने के लिए नये पॉलिटैक्निक कॉलेज बनाये जाएंगे। हमारी सरकार ने पुराने पॉलिटैक्निक कॉलेजों को अपग्रेड करके मॉर्डन बनाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पहली बार हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए पासपोर्ट योजना बनाने का काम किया है। जिसके तहत सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनवाये जायेंगे। अगर वे बच्चे अपने जीवन में विदेश में जाकर

भी कैरियर को बनाना चाहते हैं तो उसमें उनको कोई बाधा न आये ताकि वे बच्चे अधिक से अधिक आगे बढ़ सकें। मैं समझता हूं कि इससे हमारे बच्चे एक अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। हमारी सरकार ने पहली बार डिजिटल लाईब्रेरी हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए बनाने का काम किया है इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सर्व सुलभ डिजिटल लाईब्रेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई में देने का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षा देने के लिए 2000 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन इस शिक्षा व्यवस्था में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट की राशि के लगभग 15 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। (**इस समय मेजें थपथपाई गई।**) अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो मैं इस बारे में सदन मं बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर किसी परिवार का आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं है या उनके किसी कारणवश आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाये हैं तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है या जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है ऐसे परिवारों को इस आयुष्मान कार्ड के समकक्ष हरियाणाा प्रदेश के लोगों को 16,27,870 गोल्डन कार्ड बनाकर दे दिए गये हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हरियाणा प्रदेश में कैथ लैब, एम.आर.आई. और सीटी स्कैन ये तीनों सुविधाएं जरूरी रूप से हर जिला अस्पतालों में अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत अच्छी सुविधा है, जो कि आम आदमी की पहुंच से कहीं न कहीं दूर थी। हमारे प्रदेश के जितने भी प्राइवेट अस्पतालों के संचालक हैं, वे स्वास्थ्य के नाम पर कई बार इन सुविधाओं के नाते हमारे प्रदेश के जरूरतमंद लोग हैं, उनसे कहीं न कहीं ज्यादा पैसा वसूलने का काम करते हैं लेकिन हमारी सरकार इन गरीबों के लिए इस प्रकार की योजना लेकर आई जिसमें कैथ लैब, एम.आर.आई. सीटी स्कैन ये तीनों योजनाएं अनिवार्य रूप से लागू कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्रदेश की जनता के लिए सभी जिला अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए कीमोथैरेपी का प्रावधान भी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के

लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि प्रदेश के हर जिले में एक मैडिकल कॉलेज खुले ताकि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके और हमारी सरकार उस कमी को पूरा करने के लिए दृढ़ता से लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भिवानी, जींद, महेन्द्रगढ़ और गुरूग्राम में बहुत जल्दी ही मैडिकल कॉलेज खोलने का काम करने जा रही है। इसी तरह से वर्ष 2020–21 में तीन नए सरकारी मैडिकल कॉलेज कैथल, सिरसा और यमुनानगर जिलों में भी बनाने का भी निर्णय लिया है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को हरियाणा सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया है।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं गीता भुक्कल जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भिवानी जिले का मैडिकल कॉलेज बनाये जाने के बाद क्लासें कब शुरू करवाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपनी ही योजनाओं का गर्भपात किया। इन्होंने झाड़सा और बाढ़सा में एम्स बनाने के नाम पर सिर्फ पत्थर लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने यह भी नहीं सोचा कि कांग्रेस सरकार के पास इसके लिए बजट का प्रावधान है या फिर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का जिक्र भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिर्फ वहां पर पत्थर लगाकर छोड़ दिया और हरियाणा की जनता के ऊपर कुठाराघात करने का भी काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों को योजनाओं के बारे में बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : असीम जी, आप यहां पर जिस योजना के बारे में बार–बार नाम ले रहे हो। उस योजना का नाम बता दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, असीम जी, मनेठी एम्स के बारे में बता दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जाये। आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आप सदन में अपनी बात रखेंगे तब आप इनकी का जवाब दे देना। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, श्री असीम जी सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य सवाल लगाकर वर्तमान सरकार से जवाब ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने बाढ़सा में जो जमीन दी है उस बारे में आदरणीय मंत्री श्री अनिल विज जी ने जो जवाब दिया कि इसमें बहुत उबड़–खाबड़ जमीन थी, पहले ये लोग खुद गड्ढों वाली जमीन को चिन्हित करने का काम करे। मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा कि जब वह जमीन वायबल ही नहीं थी तो उसका ठीकरा हमारी सरकार पर फोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इन लोगों ने प्रदेश में केवल और केवल यही काम किए हैं। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : असीम जी, मैं माननीय सदस्य से मनेठी की लैंड के बारे में पूछना चाहती हूं (विघ्न)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इनके प्रश्नों का जवाब न जाने इस हाउस में कितनी ही बार दिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप बैठ जाये। गीता जी, जब आपको बोलने का समय दिया जायेगा तब अपनी बात सदन में कह देना। प्लीज आप बैठ जायें। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, इनके इस सवाल का जवाब पिछले पांच सालों में कम से कम 20 से 30 बार इस सदन में आ चुका है लेकिन हर बार केवल प्रदेश की जनता के प्रति अपने आपको ज्यादा ज्वाबदेह दिखाने के लिए या मीडिया में ओ के लिए ये साथी बार–बार ऐसी बातें करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा के नाते हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले, प्रत्येक नागरिक के अपने सपनों का हरियाणा बने और इस हरियाणा को आपराधिक राज्य बनने से रोकना हमारी सरकार का सर्वप्रथम उद्देश्य है। जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे। स्पीकर

सर, आपने आज बड़ी उदारता दिखाते हुए हमारे पांच कांग्रेसी विधायक साथियों के सवाल का एक जैसा कंटैंट था उसको लगाने का बड़े दिल से काम किया और उसके जवाब में आदरणीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से सारी डिटेल के साथ जवाब सदन में रखा कि किस प्रकार से 630 नई गाड़ियां, डायल 112 की योजना के बारे में बात कही। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो नजराना, जबराना और शुक्राना की प्रथा चलती थी उस नजराना, जबराना और शुक्राना की प्रथा को बंद करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भी हमारी सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वाबलंबन योजना के नाते सभी के लिए आवास एक नया विभाग बनाया जायेगा और 294 रुपये प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी के नाते और दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 10 हजार के लगभग स्वयं सहायता समूह बनाये जायेंगे ताकि वे गरीबी उन्मूलन में और बेरोजगारी को कम करने में अपना सहयोग दे सकें। पहले की सरकारों के समय में पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ शादी के महीने, दो महीने, चार महीने और छह महीने बाद मिल पाता था लेकिन इसको निश्चित रूप से जरूरी किया जायेगा कि शादी से पहले या शादी वाले दिन शगुन की राशि पात्र परिवारों को प्राप्त हो जाये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि – वाकिफ कहां दुश्मन हमारी उडान से, वो कोई और थे जो हार गए तूफान से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक नई तरह की जो मिसाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कायम की 80 करोड़ रुपये प्रत्येक विधान सभा के लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास को लेकर निर्धारित किये हैं। स्पीकर सर, मुझे एक किस्सा याद आ रहा जोकि वास्तव में घटी एक घटना है। असंध विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक बंधराला गांव पड़ता है। वहां पर पंचायत के चुनाव होने थे। गांव के सभी लोगों ने मिलजुल कर एक बुजुर्ग जिसका नाम बिच्छा सिंह था उसको कहा कि पंचायत के सम्बन्ध में आप जो भी फैसला करेंगे वह सारे के सारे गांव को मंजूर होगा। उस बुजुर्ग ने पूरी पंचायत के आगे अपनी लाठी घुमानी शुरू की और अपने आगे लाकर उस लाठी को छोड़ दिया और कहा कि मेरे से बढ़िया कोई और सरपंच हो नहीं सकता। इसी प्रकार से पलवल के गांव का भी एक ऐसा ही किस्सा है। (विघ्न) वहां पर भी एक बुजुर्ग को पंचायत चुनने का अधिकार दे दिया गया। वहां पर सात लोगों की पंचायत थी। उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है कि

सरपंच मैं हूं, महिला पंच के नाते मेरी धर्मपत्नी, मेरे चार बेटे हैं वे चारों पंच हैं और जो मेरा स्वीपर है वह एस.सी. पंच के नाते काम करेगा इस प्रकार से पूरी पंचायत का गठन हो गया। ऐसे बजट का आबंटन पहली सरकारे अपने मुख्यमंत्री को और अपने वित्त मंत्री को खुश करने के लिए किया करती थी यानि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उस समय की सरकारों पर पूरी तरह से लागू होती थी। पुरानी सरकारों की रिवायतों को दूर करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास के नाते जो सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। (विघ्न) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों को एक बात और कहना चाहता हूं कि– कुछ तो फूल खिलाये हमने और कुछ फूल खिलाने बाकी हैं, मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। ये जो पुरानी रिवायतों से हरियाणा चलता था हमारी सरकार ने उसको बदला है। अंत में मैं इस महान् सदन से निवेदन करता हूं कि इस सर्वस्पर्शी और सर्वहितकारी बजट को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। भारत माता की जय।

.....

राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय, बतौड़, जिला पंचकूला के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बतौड़, जिला पंचकुला के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत करता हूं।

.....

वर्श 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनराराम्भ)

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, बजट पर तो सत्ता पक्ष की तरफ से दूसरे सदस्य को सैकेंड नहीं करना होता है इसलिए दूसरा मौका तो विपक्ष को मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को तो रूलिंग पार्टी की तरफ से सैकेंड करना होता है लेकिन यह तो बजट है और इस

पर बोलने के लिए दूसरा मौका विपक्ष के सदस्य को मिलना चाहिए। अब तक तो यही परम्परा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैं आपको भी बोलने के लिए पूरा समय दूंगा। इनको सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया है और ये जल्दी ही अपनी बात रख लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा मत डालिए। दूसरा मौका तो विपक्ष को मिलना चाहिए। आपने दूसरा मौका भी सत्ताधारी पार्टी को ही दे दिया यह गलत बात है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तो परम्परा है कि रूलिंग पार्टी को सैकेंड करना होता है। बजट पर आपने रूलिंग पार्टी से ओपन करवा लिया लेकिन सैकेंड तो हमारा बनता है। हम उम्मीद करते थे कि आप फेयर चलेंगे, ऐसा नहीं चलता है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। आप भी बोल लेना, मैं आपकी पार्टी को पूरा समय दूंगा। आपकी तरफ से भी दो सदस्यों को बुलवा दिया जायेगा। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उनको केवल 5 मिनट का समय दिया है।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट प्रस्तुत किया है और बजट से पूर्व सभी सदस्यों से जो परामर्श किया, इस प्रकार का यह सबसे पहला केस है। बजट पूर्व 8 परामर्श किए गए और उनमें अनेक सुझाव आए हैं। माननीय विधायकों ने भी 3 दिन तक लगभग 620 सुझाव दिये हैं और ज्ञापनों और अन्य पत्रों के द्वारा भी सुझाव मिले हैं। इन सभी सुझावों में से लगभग 300 सुझाव वे थे जो सीधे–सीधे बजट से संबंधित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनमें से लगभग 70 प्रतिशत सुझावों को अपने बजट के प्रावधान जो उन्होंने विधान सभा में प्रस्तुत किया, उसमें जोड़ा है, उसमें रखा है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह कुल बजट 1,42,343.78 करोड़ रुपये का है जो हरियाणा के इतिहास में सर्वाधिक है, सबसे बड़ा बजट है और इस बजट में सभी परम्पराओं का पालन करते हुए राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत और ऋण सीमा को 25 प्रतिशत तक सीमित रखने की परम्परा का पालन किया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि अर्थात कृषक

की आय दोगुनी हो इसके लिए बजट में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले तो जो किसानों को गन्ने का भाव 340 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है यह देश में सर्वाधिक है इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही 'भावान्तर भरपाई योजना' को शुरू करना और इस योजना के शुरू करने के पश्चात 10 नई सब्जियों को उसमें जोड़ना। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को धरातल पर उतारना और अटल भूजल योजना के माध्यम से जो भूमिगत वाटर है वह सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों के काम आए। इसका प्रयास किया गया है। 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' स्कीम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश का हर किसान अपनी फसल को मंडी में एम.एस.पी. रेट पर बेचेगा और उसमें कोई कमी रहती है तो 'भावान्तर भरपाई योजना' के तहत उस कमी को पूरा करने का प्रावधान है। किसानों ने अपनी आय अपने जोश से बढ़ानी होती है। किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से यह जानकारी देने का प्रयास किया गया है कि जोत की क्या स्थिति है ? इसके लिए किसानों को 81 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये गये हैं और 111 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी मृदा का, अपनी जोत का स्वास्थ्य जानकर कृषि वैज्ञानिकों या कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा सुझाई गई खाद व दवाई की मात्रा से कैसे फसल अच्छी हो सकती है। उस संबंध में जो भी कृषि वैज्ञानिक सुझाएंगे उससे किसान कम से कम लागत से अधिक से अधिक फसल लेकर अपनी आय को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं। उस पर सरकार 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है ताकि किसान अपनी फसल के अवशेष की जमीन में ही कुट्टी काट कर और उसको गलाकर एक प्रकार की खाद के रूप में प्रयोग कर सके। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। मैं बड़े विश्वास पूर्वक यह कह सकता हूं कि आज अधिकतर किसानों ने फसल अवशेष का लाभ उठाना शुरू किया है और फसल अवशेष प्रबंधन के निमित ही हर ब्लॉक में पराली फीस सैंटर बनाने की योजना की है। इसके साथ ही हम अत्यधिक रासायनिक, उर्वरक व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करके अपनी जमीन का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और जमीन के नीचे जो पानी है उसकी गुणवत्ता को भी खराब कर रहे हैं। इससे बचने के लिए अगले तीन वर्षों में किसान का एक लाख एकड़ में जैविक खेती पर आना और किसान को जीरो बजटिंग खेती के लिए प्रेरित करना किसान की आय बढ़ाने में निश्चित रूप

से भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही जैविक खेती पर्यावरण को सुरक्षित व ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हर व्यक्ति व जीव जन्तु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसी तरह मंडियों में किसान अपनी फसल को क्रोप ड्रायर के माध्यम से सुखाकर बेचे इसकी व्यवस्था भी सरकार ने बनाई है। किसान को पहले केवल सहकारी समितियों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता था लेकिन अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। बागवानी का क्षेत्र जो कि अभी 8.17 प्रतिशत है। उसको वर्ष 2030 तक दुगुना करके किसान फसल वृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाए इसके लिए किसान को प्रेरित किया जाएगा। वर्तमान में कृषि पर जो बजट रखा गया है वह 6481.48 करोड़ रुपये का है जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.92 प्रतिशत अधिक है। यह बजट निश्चित रूप से किसानों को आगे बढ़ाने में, उनका जीवन स्तर सुधारने में, उनकी उपज बढ़ाने में और उनकी आय को दुगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' अभियान के तहत हमारी सरकार ने लिंग अनुपात 923 किया है। हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड स्कीम के माध्यम से 16,27,870 गोल्डन कार्ड बनाए हैं। प्रायः जब हम अपने–अपने क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे कि मेरा नाम नहीं आया मेरा नाम नहीं आया। हम गरीब हैं कैसे करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है कि 1 लाख 80 हजार वार्षिक आय से कम व्यक्ति या जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन व्यक्तियों को भी इस योजना में शामिल किया जायेगा। निश्चित रूप से यह प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात की बात है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही जिला अस्पतालों में एम.आर. आई. की सुविधा, सी.टी. स्कैन की सुविधा और कैंसर जैसी भयानक बीमारी की रोकथाम के लिए कीमोथैरेपी आदि की सुविधायें भी सुलभ करवाई गई हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः धनश्याम जी, आप जल्दी से अपनी बात समाप्त करें। मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे कम से कम समय में अपनी बात रखें क्योंकि सदन के 35 सदस्य ऐसे हैं जिनको पिछली बार भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का भी समय नहीं मिल पाया था। मै चाहता हूँ कि सदन के इन सभी 35 सदस्यों जिनमें नए सदस्यों की संख्या ज्यादा है, को भी बोलने का मौका मिले। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि एक

निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए ही सभी माननीय सदस्य अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पार्टी के सदस्यों का बोलने का एक निश्चित समय होता है। आप वह समय बता दीजिए फिर आपको बार बार टोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः ठीक है, मैं बता देता हूँ। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी हुड्डा साहब की पार्टी के सदस्यों को यह एतराज रहता ही है कि उन्हें बोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया गया है। अतः जैसाकि सदन में अब इस संबंध में बात चल ही रही हैं तो संभव है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को सुन ही लिया है इसलिए आप अरोड़ा जी बोलने की आज्ञा देकर सदन की कार्यवाही को चलायें।

श्री अध्यक्षः घनश्याम जी, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा जल्दी करके अपनी बात समाप्त करें।

श्री घनश्याम दास अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय आज प्रदेश के अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्ज उपलब्ध हैं। वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश में 700 विद्यार्थी एम.बी.बी.एस. में प्रवेश ले सकते थे जबकि आज यह संख्या बढ़कर 1710 के आंकड़े पर जा पहुंची है और इसी प्रकार पी.जी. कोर्सिज में पहले 289 बच्चे एडमिशन ले सकते थे लेकिन आज यह संख्या भी बढ़कर 464 हो गई है। तीन नए मैडिकल कालेज यमुनानगर, सिरसा और कैथल में बनाना प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जबरन भूमि अधिग्रहण की परिपाटी को समाप्त करना, सड़कों का सुधार और चौड़ीकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अंडरपास बनाना और जलजीवन मिशन जो प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है कि हर घर में नल हो और हर नल में जल हो को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य, per drop more crop सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत 1200 करोड़ रूपये की महत्वकांक्षी योजना, हर खेत को पानी सुलभ कराने के लिए कच्चे जल मार्गो को पक्का करना और म्हारा गांव–जगमग गांव के तहत 4500 गांवों में 1048 फीडर्ज स्थापित करना तथा 9 जिलों में सातों दिन 24 घंटे बिजली की सप्लाई करना, लाइन लॉस को घटाकर 17.45 प्रतिशत करना, बिल निपटान

योजना को 13 लाख 61 हजार उपभोक्ताओं द्वारा अपनाया जाना और लंबित कनेक्शंज को जल्द से जल्द देना, सभी के लिए आवास योजना और किराया आधारित आवास की एक नई योजना लाना यह सब वे बातें है जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के रूप में बहुत ही सराहनीय कदम उठाये हैं। इन कदमों की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। इतना कहते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि यह सदन इस बजट को सर्वसम्मति से पास करें। मैं अपनी ओर से इस बजट का अनुमोदन करते हुए वाणी को यहीं विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो उसके सामने बजट एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हर फाइनेंस मिनिस्टर की यह दिली इच्छा होती है कि वह ऐसा बजट बनाये कि सदन में सभी सदस्य बजट के समर्थन में मेजें थपथपायें तथा बजट की दिशा और दशा भी प्रदेश को दिखाई दे। ऐसा ही कुछ प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी करने की कोशिश की है। इन्होंने भलेपन में तथा घूम फिरकर प्रदेश के हित में ऐसा बजट बनाने की कोशिश की है कि बजट में प्रदेश के सभी एम.एल.एज./एम.पीज. की भावनाओं को सम्मिलित करते हुए प्रदेश हित में बेहतर बजट बनाया जाये लेकिन यह जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं समझता हूँ कि यह सब अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाशा था। चौधरी चन्द्र शेखर जी जो इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वह छह महीने की भारत यात्रा पर निकले ताकि वे हिंदुस्तान की समस्याओं को नजदीक से जान सके। उन्होंने जगह जगह पर फार्म हाउसिज में अपने यात्रा केन्द्र बना रखे थे। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि जिस आदमी को भारत की समस्या का ही नहीं पता है तो वह आदमी भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? अध्यक्ष महोदय, इस बजट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने दो महीने वैसे ही घूम फिर कर खराब कर दिये और बजट को अच्छा बनाने के झमेले में पड़े रहे। बजट में हरियाणा प्रदेश का रोड मैप तैयार करना चाहिए था। सरकार को उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एफ0डी0 के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बजट को तैयार करने के लिए दिन रात एक किया हुआ था। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकवाद देता हूँ। एफ0डी0 विभाग के कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी की चमड़ी को बचाने के लिए अपनी पूरी महारथ बजट में लगा दी

है। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट सरकार की गतिविधियों पर पूरी कांट–छांट के साथ पेश होती है। वह कैग की रिपोर्ट सदन में पेश होनी चाहिए थी। जब से हरियाणा बना है तब से कैग की रिपोर्ट सदन में रखी जाती है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार कैग की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई थी तो मैंने इस सवाल को सदन में उठाया था। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट ऐसी होती है जो विपक्ष को बोलने के लिए मजबूर कर देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सोच के अनुसार सदन में कहूँगा और बजट के विरोध में पौजीटिव सोच के साथ अपनी बात सदन में रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे सवालों का जरूर जवाब देना। बजट में वन विभाग के साथ–साथ 15–16 विभागों का कोई भी जिक्र नहीं है। इसमें सरकार की अनुभवहीनता तो नहीं हो सकती क्योंकि यह सरकार पहले भी बन चुकी है और उस समय किसी विषय को लेकर जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम अनुभवहीन है। लेकिन अब तो सरकार ने सब कुछ सीख लिया है, इसलिए इसमें अनुभवहीन का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का एक ए0सी0एस0 रैंक ऑफिसर बजट को तैयार कर सकता है लेकिन सरकार बजट को लेकर वैसे ही दो महीने तक घूमती रही। इसका कारण यह है कि बजट को लेकर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार गठबन्धन की है। गठबन्धन सरकार में भाजपा का भी चुनावी घोषण पत्र था और जजपा का भी चुनावी घोषणा पत्र था। भाजपा का वर्ष 2014 से वर्ष 2019 का चुनावी घोषण पत्र और वर्ष 2019 से वर्ष 2024 का संकल्प पत्र था और वर्ष 2019 में जजपा का चुनावी घोषण पत्र था। जब सरकार अपना बजट तैयार कर रही थी तो इन चुनावी घोषण पत्रों में इतना सामान भरा पड़ा था अगर सरकार उसे ही पूरा कर देती तो हरियाणा प्रदेश में 20 वर्ष के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन इन चुनावी घोषणा पत्रों को छोड़ दिया गया है। सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया लेकिन बजट में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया। गठबंधन सरकार की यह प्रिर्योरिटी होती है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर हरियाणा में नया काम की शुरूआत करें। इस प्रकार का कोई भी काम बजट में दिखाई नहीं दिया है और न ही बजट में गठबन्धन धर्म को निभाया गया है। यह जनता के साथ किया गया एक छलावा है। अध्यक्ष महोदय, जब हम जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि हम यह चुनावी घोषण पत्र लागू करेंगे, इसलिए हमें वोट दें। चुनावी घोषण पत्रों से संबंधित

कोई भी बातें इस बजट में शामिल नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय राजनीतिक तौर पर काफी स्मार्ट हैं और वे स्वयं ही अकेले बजट तैयार कर देते और माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय बजट तैयार करते समय अपने चुनावी घोषण पत्र के मुताबिक 5100 रुपये प्रति महीना सामाजिक सुरक्षा बुढ़ापा पेंशन वाली बात का जरूर जिक्र करते। इस प्रकार से बजट में गठबन्धन धर्म भी नहीं निभाया गया, इस बात का भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार से इस बजट पर चर्चा का कोई भी महत्व नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बजट का सबसे बड़ा कंपोनैंट एलोकेशन है और मैं इस पर बोलना चाहता हूं । एलोकेशन में वर्ष 2020–21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 6,481.48 करोड़ रूपये अलॉट किये हैं । वर्ष 2019–20 के लिए इस क्षेत्र में 5,230 करोड़ रूपये रखे गए थे । सरकार ने इसमें 23.92 परसैंट की वृद्धि बताई थी और इस पर मेजें थपथपाई गई थी । यह 23.92 परसैंट की वृद्धि नहीं है । पिछले बजट का आकार 1.32 लाख करोड़ रुपये था । यह परसैंटेज इस वित्त वर्ष के 1.42 लाख करोड़ रुपये के बजट के हिसाब से बताई गई है । इस तरह से यह वृद्धि कितनी हुई ? यह वृद्धि सिर्फ 0.6 परसैंट है । यह गलत रिकॉर्ड है जिस पर मेजें थपथपाई जा रही थी कि यह 23.92 परसैंट की वृद्धि है । (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से वित्त विभाग का कोई अधिकारी कैसे कह सकता है कि यह वृद्धि पिछले बजट से 0.6 परसैंट से ज्यादा है । पिछले बजट में 3.95 प्रतिशत बजट कृषि क्षेत्र पर लगाया गया था जबकि अब 4.95 परसैंट इंक्रीज किया गया है । दोनों में सिर्फ 0.6 परसैंट का फर्क है । इसमें 23.92 परसैंट की वृद्धि नहीं है । इस तरह से सदन में गलत डाटा रखा गया है । मैं सदन में बहुत सीरियस बात रख रहा हूं । इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी गुमराह किया गया है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि एजूकेशन में 15 परसैंट बजट एलोकेट किया गया है । इसके हिसाब से इसका बजट शेयर 21,351 करोड़ रुपये बनता है जबकि सरकार ने इसमें केवल 19,039 करोड़ रुपये एलोकेट किया है । यह केवल 13.79 परसैंट वृद्धि है । यह सरकार की गम्भीरता दिखाता है । सरकार ने कैसे कह दिया कि हमने इसमें 15 परसैंट की वृद्धि की है जबकि 15 परसैंट 21,351 करोड़ रुपये बनता है । सरकार चाहे तो 1.42 लाख करोड़ रुपये की राशि को एजूकेशन सैक्टर को प्राप्त राशि से कैलकुलेट कर ले । अतः सरकार को इनको करैक्ट करना चाहिए । दूसरा, ये कह रहे हैं कि वर्ष 2020–21 में हाइएस्ट एलोकेशन हुई है ।

वर्ष 2020–21 में हाइएस्ट एलोकेशन नहीं हुई है । हाइएस्ट एलोकेशन वर्ष 2015–16 में हुई थी जोकि 16.20 परसैंट थी । टोटल बजट का 16.20 परसैंट एलोकेशन आपकी ही सरकार ने वर्ष 2015–16 में किया था । मैंने कुल 6 बजट देखे थे । यह एलोकेशन उन सबमें ज्यादा था । वर्ष 2015–16 में एजूकेशन पर 16.20 परसैंट, वर्ष 2017–18 में 14.24 परसैंट और इस बार 13.79 परसैंट बजट एलोकेशन किया गया है । अतः इस बार एजूकेशन का एलोकेशन तीसरे नंबर का है जबकि सरकार ने लिख दिया कि हमने 13.79 प्रतिशत एलोकेशन किया है और यह जब से हरियाणा बना है तब से सर्वाधिक है । सदन में यह रोंग स्टेटमैंट दी गई है । मैं यह मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एलोकेशन का मुद्दा किसी भी बजट का मेजर हैड होता है । एलोकेशन में ही हमें सरकार की गम्भीरता दिखाई नहीं दे रही है । ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं । उसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण को देखिये । इसमें इन्होंने कहा कि यह वृद्धि 23.61 प्रतिशत है । पिछली बार टोटल बजट का 0.51 प्रतिशत था । इस बार वर्ष 2020–21 में टोटल बजट का 0.59 प्रतिशत है । इस तरह से इसमें केवल 0.08 परसैंट इंक्रीमैंट है । 0.08 परसैंट इंक्रीमैंट को 23.61 प्रतिशत इंक्रीमैंट बताया गया और इस पर भी सदन में मेजें थपथपाई गई थी । What is the fun? अतः सरकार को बजट बनाते समय ध्यान देना चाहिए था कि बजट की परसैंटेज फलां बजट के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं बाद में बजट पर सभी माननीय सदस्यों को उत्तर दूंगा लेकिन इस समय माननीय सदस्य सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वे बिल्कुल अलग हैं, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। एक आंकड़ा है कि टोटल एलोकेशन में कितनी इंक्रीमैंट हुई है। 0.05 परसैंट, 0.06 परसैंट जो इंक्रीमैंट है वह टोटल बजट का एलाकेशन है । दूसरा है budget in itself. किसी एक विभाग को पिछले बजट में एलोकेट किये गए फंड से इस बार के बजट में एलोकेटिड फंड कितना बढ़ाया है ।

Dr. Raghuveer Singh Kadian: Speaker Sir, amount carrying no meaning at all.

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में परसैंटेज और एलोकेशन दोनों बता रहा हूं । मान लीजिए कि हमने टोटल 1.42 लाख करोड़ रुपये के बजट में से शिक्षा विभाग में 10 हजार करोड़ रुपये लगाए और अगली बार उसको 12 हजार

करोड़ रुपये दे दिए गए तो इसमें 20 परसैंट बढ़ौत्तरी हो जाती है । हमने कैल्कयूलेशन किया कि पिछला बजट कितना था और उस पर कितने प्रतिशत बढ़ाया है ? यह उस हिसाब से 23 प्रतिशत है। टोटल बजट की 1,42,343.78 करोड़ रुपये की एलोकेशन में से देखेंगे तो शिक्षा पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये के बजट के हिसाब से तो यह मात्र 7 प्रतिशत है। अगले साल यह बजट बढ़कर लगभग 12,000 करोड़ रुपये हो जाएगा तो फिर यह उस 7 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह बजट एलोकेशन की बात नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी बजट के एलोकेशन की बात कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले साल का जो बजट था, उसके ऊपर कितना इन्क्रीज हुआ है ? उसके बारे में बता रहा हूं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पता नहीं संबंधित आंकड़े किस हिसाब से दिखाये गये हैं। मान लीजिए, इकोनामिक सर्वे में पर– कैपिटा इन्कम 2,36,000 रुपये स्टेटस में दिखायी है, परन्तु बजट एट ए ग्लांस 2,83,000 रुपये दिखा रहे हैं। इस प्रकार से पर– कैपिटा इन्कम में 50,000 रुपये का डिफरैंस हो जाता है। सरकार ने बजट में आंकड़े किस हिसाब से दिखाये हैं ? (विघ्न)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः ऑनरेबल स्पीकर सर, इसी प्रकार से हैल्थ का वर्ष 2019–20 में टोटल बजट का 4 प्रतिशत था। अब टोटल बजट 4.6 प्रतिशत रखा गया है। इस हिसाब से तो इसमें सिर्फ 0.6 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी की गयी है। यानी 28.3 प्रतिशत की वृद्धि नहीं है। इस प्रकार से बजट में जितनी भी अलग–अलग एलोकेशंज की गयी हैं, उसमें इसी हिसाब से बढ़ोतरी की गयी है। इसमें आपकी एक इन्टैंशन ठीक है कि आप ये सब चीजें एलोकेशन में दिखाना चाहते हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से महकमे रहे गये हैं जिनमें बजट की कोई एलोकेशन नहीं की गयी है। उदाहरण के तौर पर 5100 रुपये बुढ़ापा पैंशन देने की बात की गयी थी। बजट में सरकार को बुढ़ापा पैंशन बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए था। इसमें शुरू में 3100 रूपये मासिक करके प्रत्येक साल 500–500 रुपये के हिसाब से बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। ऐसा करने से पांच सालों में बुढ़ापा पैंशन 5100 रुपये हो जाती। ये बातें मैनिफेस्टो में दी गयी हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले सालों में प्रदेश के समाज

का हजारों साल के भाईचारे का ताना–बाना टूटा है। भाईचारे में एक नकली दीवार खड़ी गयी गयी है। घरों में लोग कैसी–कैसी बातें करते हैं, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं है ? लोगों के मन में विचारों का बहुत जहर फैला हुआ है। इस बजट का 50 प्रतिशत एलोकेशन हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को बनाने में लगा देते तो भी वह बहुत थोड़ा था। हमारे प्रदेश का भाईचारा पहले है और अगर भाईचारा नहीं बनेगा तो सामाजिक परपज पूरा नहीं होगा। (विघ्न)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। यह बजट सरकार ने इसी बात के लिए रखा है। (विघ्ने)

श्री लीला रामः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः लीला राम जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ड्रग्स ऐडिक्शन बहुत बड़ी समस्या है, परन्तु इसमें कोई एलोकेशन नहीं की गयी है।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सभी चीजों के लिए बजट की एलोकेशन की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीट्स पर बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए बजट में कोई एलोकेशन नहीं की गयी है। प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। किसानों की कर्ज माफी की कोई बात नहीं की गयी है और न ही किसानों को कोई सब्सिडी दी गयी है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की गयी है। बजट में न ही क्रॉप डायवर्सिफिकेशन का जिक्र किया गया है। बजट में क्रप्शन को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश में बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले करप्शन का एक मामला सामने आया था और वह विधान सभा में भी उठाया गया है। दो माननीय सदस्यों ने संबंधित मुद्दे को उठाया था। संबंधित मुद्दे पर माननीय मुख्य मंत्री को यह कहना चाहिए था कि मामले की इन्कवायरी करवायी जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, वे सदन में रखे जाएंगे परन्तु सरकार द्वारा संबंधित मामले में क्लीन चिट दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं करप्शन की बहुत बड़ी मिसाल बता रहा हूं। यह डिक्टेटरशिप

नहीं है तो क्या है ? (विघ्न) स्पीकर सर, लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर भी पॉलिसी एट दा गवर्नमैंट लेवल पर बने, लेकिन इम्पलीमैंटेशन विभाग के द्वारा किया जाए। ताकि पुलिस का काम अच्छी तरह से चल पड़े। इसके अतिरिक्त उद्योगों की रिहैबिलिटेशन की जाए क्योंकि नोटबंदी और जी.एस.टी. के कारण जगाधरी का बर्तन उद्योग, यमुनानगर का प्लाईवुड उद्योग, रोहतक का नट बोल्ट उद्योग, पानीपत का हथकरघा उद्योग, करनाल का चावल उद्योग और अंबाला के साइंस के सामान के उद्योग भी बन्द हो गये हैं। इस प्रकार अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग उद्योग थे जोकि बन्द हो गये, परन्तु सरकार ने उनके लिए बजट में कोई एलोकेशन नहीं की। ऑनरेबल स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की कोई बात नहीं की गयी और न ही पुरानी पैंशन की बहाली की बात गयी। दादूपुर नलवी नहर के कन्जर्वेशन वर्क के लिए कोई बात नहीं की गयी। एस.वाई.एल. नहर के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह नहर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए था क्योंकि इसमें पुल और दूसरी चीजें भी बनायी जाएंगी। सरकार ने इस हिसाब से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। सरकार के द्वारा बनायी गयी परियोजनाओं के लिए भी बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए भी बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, एलोकेशन के साथ–साथ एक ऐसा मामला भी रखूंगा जो गवर्नमैंट की गवर्नैंस की तरफ भी इशारा करता है कि गवर्नैंस कैसी है ? ऑनरेबल स्पीकर सर, गवर्नमैंट ने पूछा है कि आपको कितना बजट चाहिए ? अध्यक्ष महोदय, मान लो मुझे इसके लिए 1 हजार रुपये का बजट चाहिए और मैं 900 रुपये खर्च कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मेरे पास 6 वर्षों का वित्तीय लेखा जोखा है कि कितना किस मेजर डिपार्टमैंट में बजट एलोकेट हुआ और कितना खर्च हुआ?

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, पहले 16 वर्षों का हिसाब–किताब ले आओ क्योंकि 6 वर्षों के बजट के बारे में बताने से बात नहीं बनेगी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं 16 वर्षों के बजट का हिसाब–किताब ले आऊंगा परन्तु मैं वर्ष 2015–16 से वर्ष 2020–21 के बजट के बारे में बताना चाहूंगा

कि इसमें कम से कम 56 के करीब मेजर डिपार्टमैंट्स हैं और इन 56 डिपार्टमैंट्स में करीब–करीब 80 प्रतिशत बजट एलोकेट बजट किया गया है जैसे इसमें बजट एस्टिमेट्स कुछ हैं और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कुछ हैं और एक्चुअल खर्च कुछ है। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि जो एक्चुअल खर्च और बजट एस्टिमेट्स में फर्क दिखाई देता है, वह सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है।

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, आप इस महान सदन में वर्ष 2005–06 के वित्तीय लेखा जोखा के बारे में भी तो बता दें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहता हूं कि सरकार इसमें कोशिश करे कि बजट यूटिलाईजेशन किया जाये और अगर सरकार यूटिलाईजेशन नहीं करती है तो That is the accountability of the concerned officer and concerned officer is answerable for that और इसमें सरकार खुद स्टैप उठाए। मैं तो आपकी गर्वनैंस के लिए ही यह बात कह रहा हूं कि यूटिलाईजेशन इन्श्योर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बजट की टोटल रिसीट्स की जानकारी है, इसमें यह नहीं दिखाया गया है कि considerable increase है। सरकार की वर्ष 2019–20 में 1,11,908 करोड़ रुपये और वर्ष 2020–21 में 1,19,751 करोड़ रुपये है और इसमें लगभग 8 करोड़ रुपये का अंतर आया है। गवर्नमैंट की जो कैपेसिटी है वह Tax structure पर डिपैंड करती है कि सरकार का टैक्स स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। अगर सरकार बजट पर पूछने की बजाय यह पूछती कि सरकार के लिए बजट जनरेट करने के बारे में बताया जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार का revenue deficit लगातार बढ़ रहा है। जिसका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है वर्ष 2016–17 में 15,906 करोड़ रुपये, वर्ष 2017–18 में 10,562 करोड़ रुपये, वर्ष 2018–19 में 8,506 करोड़ रुपये, वर्ष 2019–20 में 12,022 करोड़ रुपये और वर्ष 2020–21 में 15,373 करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय, revenue deficit consistently increase कर रहा है और इस बजट में जो most important चीज है वह वही है और यह काफी सीरियस मैटर है।

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, आपने कहा था कि absolute value पर न बोले, सिर्फ परसेंट्ज पर ही बोलें। मैं समझता हूं कि अगर आप भी परसेंट्ज पर बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं कहना चाहता हूं कि absolute value तो हर साल बढ़ेगी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें fiscal deficit का सबसे बड़ा सीरियस मैटर है और इसमें consistently increase हो रही है। मैं इस बारे में भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017–18 में 19,114 करोड़ रुपये और वर्ष 2018–19 में 19,399 करोड़ रुपये, वर्ष 2019–20 में 22,461 करोड़ रुपये और वर्ष 2020–21 में 25,681 करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से एग्री भी करता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि fiscal deficit percentage के हिसाब से अमाउंट के रूप में बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015–16 के बजट में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने कहा था कि हम fiscal deficit जीरो लाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूं कि fiscal deficit जीरो लाने की बजाय consistently बढ़ रही है यह एक सीरियस मैटर है। सरकार का जो राजकोषीय घाटा होता है वह गवर्नमैंट पर क्वैश्चन मार्क लगाता है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मैटर है इसलिए सरकार fiscal deficit पर ध्यान देने की कोशिश करे। स्पीकर सर, जहां तक डैट लॉयबिलिटी की बात है। इसमें मैं कोई बात ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करूंगा लेकिन जो पेपर की बात है उसको तो मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। इसमें जिस तरह से वर्ष 2013–14 में सरकारी खजाने के ऊपर 61 हजार करोड़ रूपये का कर्ज था और अब वर्ष 2020–21 में बजट एस्टीमेट्स में 1,98,700 करोड़ रुपये हो गया है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में कुछ बातें क्लीयर कर देना चाहूंगा। स्पीकर सर, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अगर सभी विषयों को तथ्यों के हिसाब से रखा जायेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पहली बात तो मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा इनके अंतिम बजट हमेशा वर्ष 2013–14 क्यों गिना जाता है 2014–15 क्यों नहीं गिना जाता? कांग्रेस पार्टी की सरकार का दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वर्ष 2013–14 न होकर 2014–15 का था। उस समय सरकारी खजाने पर लगभग 70,900 करोड़ रुपये का कुल कर्ज था लेकिन अगर हम पॉवर यूटीलिटीज के उस समय के घाटे को सरकार अदा न करती तो हमारी सरकार के समय में भी सरकारी खजाने पर भार 1.98 लाख करोड़ रुपये न होता। हमने पॉवर यूटीलिटीज का 27 हजार करोड़ रुपये का घाटा उदय योजना के अंतर्गत इसमें ऑब्जर्व किया है। अगर आप लगभग 71 हजार करोड़ रुपये में 27 हजार करोड़ रुपये जोड़ दें तो ये नैट उस समय का 98 हजार करोड़ रुपये हो

जायेगा। अगर कादियान साहब उस समय का कुल कर्ज 98 हजार करोड़ रुपये कहकर आज का 1.98 लाख करोड़ रुपये कहेंगे तो मुझे वह बात स्वीकार होगी लेकिन अगर 61 हजार करोड़ रुपये से 1.98 लाख करोड़ रुपये कहेंगे तो वह मुझे स्वीकार होगा। अगर माननीय सदस्य इस बारे में सदन में बोलते समय साफ तौर पर यह कहें कि ठीक है विद उदय आज इतना कर्ज है और विद् आउट उदय जो आंकड़ा है उसके बारे में बताया जाये क्योंकि उस समय उदय शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उस समय जो पॉवर यूटीलिटी का कर्ज था, वह अलग था और वह अलग अकाउंट में चल रहा था। जब सारे देश भर में उदय का कांसैप्ट आया। उससे पहले वर्ष 2002 में भी यह हुआ था। वर्ष 2002 में भी जो पॉवर यूटीलिटीज का कर्ज था उसको सरकार द्वारा ऑन किया गया था। उस समय भी दूसरी तरफ उस कर्ज को जीरो किया था लेकिन वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2017 तक यह कर्ज 27 से 28 हजार करोड़ रुपये बढ़ गया। आखिर जो 27 हजार करोड़ रुपये था उसको हमने सरकार के कुल कर्ज में शामिल किया तो उसका इम्पैक्ट हरेक इंडिकेटर और हरेक पैरामीटर पर आना स्वाभाविक था जो कि आया भी, इसलिए हम जब कभी भी ये हिसाब लगाते हैं तो इनको 98 हजार करोड़ से आगे लगाए तो 1.98 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को हम सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन अगर विपक्ष 61 हजार करोड़ रूपये से शुरू करके कहेगा तो 1.98 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बिल्कुल नहीं है फिर उसमें 27 हजार करोड़ रुपये और उसका ब्याज इस प्रकार से कुल मिलाकर यह 35 हजार करोड़ रुपये बनता है। अगर हम इस कुल कर्ज में से 35–36 हजार करोड़ रुपये घटायेंगे तो वह जाकर के 1.60 लाख करोड़ रूपये बनेगा। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने जो उदय के बारे में कहा वह कर्ज वर्ष 2015–16 में इंक्लूड हुआ है। ना ही वो वर्ष 2012–13 में और ना ही 2013–14 में इंक्लूड हुआ है। पॉवर यूटीलिटी का कर्ज वर्ष 2014–15 में 70 हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2015–16 में उदय का कंसैप्ट सारे देश में आया है। क्या सरकार बिजली डिपार्टमैंट से इसको वापिस नहीं लेगी?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, जब वर्ष 2002 में पॉवर यूटीलिटी के कर्ज को तत्कालीन सरकार द्वारा ओन किया गया था तो क्या बाद में हुड्डा साहब ने उसको वापिस लिया था? किसी के घाटे को जब सरकार ओन कर लेती है तो उसको रिवाईव करने के लिए करती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, अगर ऐसी बात है तो फिर सरकार द्वारा इनकी फिग्गर्ज अलग–अलग क्यों नहीं दी जा रही है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि जब दोनों के पैरामीटर्स मुकाबला करेंगे तो आखिर चार साल और पांच साल जब उदय का इफैक्ट इसके ऊपर है तब अलग–अलग दोनों दिखाये जा रहे हैं। इस बार से अब चूंकि पिछला सारे का सारा इफैक्ट कंज्यूम कर लिया गया है और उसके पैसे दे दिये गये हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरा मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि निकट भविष्य में अगर कोई और स्कीम आ जायेगी तो फिर यह कर्ज और भी बढ़ जायेगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि आज की तारीख में एच.एस.आई.आई.डी.सी. का भी ऐसा ही मामला है। अब चार साल का समय हो गया है इसलिए अब उदय के लिए जरूरत नहीं है। चार साल में यह कंज्यूम हो गया है। आगे के चार–पांच साल के उदय और बिना उदय के दोनों ही पैरामीटर्स आ गये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरा मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि जो फिग्गर्ज वे बता रहे हैं वे मिसलीडिंग फिग्गर्ज हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि जो फिग्गर्ज मैंने दी हैं वे मिस–लीडिंग नहीं हैं बल्कि मिस–लीडिंग तो ये फिग्गर्ज हैं कि 27 हजार करोड़ रुपये वर्ष 2014–15 के कुल कर्ज के आंकड़े में जोड़ दें और 98 हजार करोड़ रूपये से शुरू करें मैं तो सारी बातें सुनूंगा लेकिन अगर 98 हजार करोड़ नहीं बोलेंगे और 1.98 लाख करोड़ बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा।

16:00 बजे

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, 98 हजार करोड़ का कर्ज हरियाणा बनने के बाद 48 साल में हुआ जिस दौरान कई सरकारें आई और कई मुख्यमंत्री आए और 6 साल में 1 लाख करोड़ कर्ज इन्होंने ले लिया। 48 साल में तो 98 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया और आपने 6 साल में 1 लाख करोड़ रुपये का कर्जा ले लिया। आज के दिन एक बच्चा अगर हरियाणा में पैदा होता है तो वह 80 हजार रुपये का कर्ज लेकर पैदा होता है यह अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मिसलीड कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014–15 में 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था और 2013–14 में 60,300 करोड़ रुपये का कर्जा था। जो उदय स्कीम आई है यह तो 2015–16 में आई है उसका कर्ज हमारे साथ कैसे जोड़ा जा सकता है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, पॉवर यूटीलिटीज का घाटा तो आप उस समय भी छोड़ कर गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 27 हजार करोड़ रुपये का जो ये पॉवर यूटीलिटीज का घाटा बता रहे हैं उसके अलावा इन्होंने उस घाटे को घटाया है या बढ़ाया है? ये यह बतायें कि इनका घाटा कैसे बढ़ा? ये गलत नीति पर चल रहे हैं। आप कर्जा लेकर घी पीने वाली नीति पर चल रहे हैं और यह सोचते हैं कि उसके बाद देखा जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि पॉवर यूटीलिटीज का घाटा वर्ष 2002 से शुरू हुआ था। वर्ष 2002 में भी एक बार ऐसे ही घाटे को सरकार ने एब्जॉर्ब किया था। उस समय पॉवर डिपार्टमैंट का नाम एच.एस. ई.बी. था। उस समय भी सारा घाटा कंज्यूम किया गया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बोर्ड और कारपोरेशन में फर्क होता है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब को जानकारी होगी कि आज उसी एच.एस.ई.बी. का नाम बदल कर कॉर्पोरेशन रखा गया है। उस समय सारे कर्ज को कंज्यूम करके घाटा जीरो कर दिया गया था। जो 27 हजार करोड़ रुपये का क्युमुलेटिव घाटा है वह वर्ष 2016 तक का है। वर्ष 2016 तक के सारे कर्ज को एब्जॉर्ब किया है तब जाकर यह घाटा बढ़ा है। अगर आपने उसके बिना आज तक का आंकड़ा सुनना है तो वह भी सुनिए। वर्ष 2004–05 की जो डैट लायबिलिटी थी वह लगभग 17 हजार करोड़ रुपये थी। इसके बाद 5 साल आगे चला जाए तो वर्ष

2010–11 में 34,672 करोड़ रुपये हो गई तथा वर्ष 2014–15 में 70,900 करोड़ रुपये हो गई।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह तो आपकी सरकार के समय का है। अक्तूबर, 2014 में आपकी सरकार आ गई थी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब को पता होना चाहिए कि 2014–15 का बजट तो मार्च, 2014 में ही पास हो गया था। हमारी सरकार तो अक्तूबर, 2014 में आई है तथा हमने तो वर्ष 2015–16 का बजट पेश किया है। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हमारी नीयत कोई कांट–छांट करने की नहीं है। हमारी नीयत यह है कि अगर आप आज दिशा और दशा बदलने में अपनी अच्छी नीयत से कुप्रबन्धन को सुधारने में अगर आप अपनी एनर्जी लगाओगे तो अच्छा रहेगा। जवाब आप बजट के रिप्लाई के समय दे देना। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014–15 में सरकार की देनदारियां 7841 करोड़ रुपये थी जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंट्रस्ट भी आ गया जो वर्ष 2015–16 में बढ़ कर 18598 करोड़ तक पहुंच गई। वर्ष 2016–17 में इंट्रस्ट 9616 करोड़ रुपये बना और प्रिंसिपल 6280 करोड़ रुपये बना, इस प्रकार से कुल मिलाकर सरकार की देनदारियां 15896 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इसी प्रकार से वर्ष 2017–18 में इंट्रस्ट 11961 करोड़ रुपये और प्रिंसिपल 6338 करोड़ रुपये और कुल मिलाकर 18299 करोड़ रुपये सरकार की देनदारियां हो गई। वर्ष 2018–19 में सरकार की देनिदारियां इंट्रस्ट और प्रिंसिपल को मिला कर 31442 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इसी प्रकार से वर्ष 2019–20 में वही देनदारियां बढ़ कर 36889 करोड़ रुपये पर पहुंच गई और वर्ष 2020–21 की सरकार की देनदारियां 40749 करोड़ रुपये बन रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि टोटल बजट का 28 प्रतिशत पैसा, यानी कि 40749 करोड़ रुपये आपने ब्याज की अदायगी में लगा दिये। यदि इस कुप्रबंधन की तरफ ध्यान दिया जाता तो यह बचाया जा सकता था। आपका प्लान बजट तो शायद 40 हजार करोड़ रुपये का भी नहीं होगा उतनी तो आपने देनदारियां ही दे दी हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका बजट 81 प्रतिशत के करीब नॉन

प्लान बजट है। आपका बजट तनख्वाह में, पेंशंज में, ब्याज में, प्रिंसिपल में जा रहा है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर मैं आपसे 1000 रुपये उधार लूं और अगले साल मैं आपको 200 रुपये ब्याज के और 200 रुपये मूल के दे दूं अर्थात 400 रुपये दे दूं तो उसमें से 600 रुपये रहने चाहिए लेकिन वह 1200 रुपये बन गये हैं। वह तो बढ़ रहा है । देनदारी दी जा रही हैं। ब्याज भी दिया जा रहा है लेकिन ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है यह सीरियस मैटर है। इसी तरह से अब घर कैसे चलाया जा रहा है ? हम तो पुरानी किताबों में सुनते थे कि तीन तरह का पूत होता है। पूत, सपूत और कपूत और घर में कर्जा बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप तो महाजन कम्यूनिटी से हैं जो हिन्दुस्तान के पैसे को, बजट को उसके लेनदेन को, उसके चलाने में आपसे ज्यादा तो कोई समझ रखता नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री जी को मेरा एक सुझाव है कि इस वितीय कुप्रबंधन की तरफ ध्यान दें और प्रदेश को सही दिशा देने का काम करें।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आपको बोलते हुए 33 मिनट हो गये हैं। इसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पार्टी के बाकी सदस्यों का ही टाईम कटेगा।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर सरकार रेल या मैट्रो का कोई बड़ा प्रोजैक्ट लाती तो हम कहते कि खर्च किया है लेकिन आप ये बताइये कि खर्च कहां किया गया है और फिर भी सरकार 1.98 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। आप इस पर श्वेत पत्र जारी कीजिए। आप इस पर श्वेत पत्र जारी कर दो मैं आपको मान जाऊंगा। हमारे समय की सरकार के समय में भी तो मैट्रो आदि के प्रोजैक्ट थे लेकिन आप फिर भी श्वेत पत्र लेकर आए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार ने कर्ज लेने की सीमाओं को लांघ लिया है। आज हजारों करोड़ रुपये के टैक्सिज की वसूली नहीं हो रही है। यह आपका इकोनोमिक कह रहा है। सरकार का वर्ष 2020–2021 के लिए कर्जों पर खर्च की गई ब्याज की दर 28.61 तक पहुंच गई है। आज रेवैन्यु घाटा और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपकी गलत नीतियों के कारण आज किसान दुगर्ति के कगार पर चला गया है। आज यह कहना गलत है कि किसान खुशहाल है। मुख्यमंत्री जी, आप जो यह सोच रहे हैं कि अबकी बार 40 सीटें आई है जिसकी आपने पिछली बार प्रतिशतता भी गिनाई थी कि सरकार की इतनी प्रतिशतता है और इतनी प्रतिशतता जजपा की है तथा इतनी प्रतिशत्ता कांग्रेस पार्टी की है। अब यह

प्रतिशत्ता नहीं है। इब्राहिम लिंकन ने 150 साल पहले डैमोक्रेसी को डिफाइन किया था। Government of the people, by the people, for the people. यह जो गवर्नमैंट है यह Government of the R.S.S, by the R.S.S. and for the R.S.S. है। मुख्यमंत्री जी, को क्या इस बात का पता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : हम गांधी परिवार के पालतू लोग नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री(श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, वह आर.एस.एस. ही है जिसने हमें सिखाया है कि 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक।' वह आर.एस.एस. ही है जिसने हमें सबके लिए समान बंटवारा करना सिखाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं तो आपको बैठने के लिए कहूंगा नहीं क्योंकि हुड्डा साहब ने कहा हुआ है कि कादियान साहब जितना बोलना चाहें, बोलने देना, पर बाकी के जो नये सदस्य हैं उनके लिए समय नहीं बचेगा। जब उनकी बोलने की बारी आएगी तो वह तड़फेंगे।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी भी इलैक्शन से पहले रथ यात्रा लेकर घूम रहे थे। लोगों से भी मिले हैं, पंफलेट्स भी लगवा दिये गये। उन्होंने पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। बस 75 पार 75 पार का नारा देते थे और लोगों को बहकाने की पोजीशन में लेकर आए थे। अध्यक्ष महोदय, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में लिखा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा कसूर एग्जिट पोल और ओपीनियन पोल का था और अगर इस बाबत इतिहास लिखा गया तो इतिहास में यह स्पष्ट लिखा जायेगा कि हरियाणा प्रदेश में इस सरकार को लाने में सबसे बड़ा कसूर एग्जिट पोल, ओपीनियन पोल, सी.बी.आई., ई. डी. तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, ऐसा नहीं है, सरकार को लाने में सबसे बड़ा योगदान जनता का रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, देश का बंटवारा करने वाले ये लोग आज हमको नसीहत दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किस तरह विचलित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी पार्टी के सदस्य को बोलने के लिए मौका दिया है

और सत्ता पक्ष के लोग उनको बोलने से रोक रहे हैं और अनाप–शनाप ढंग से आरोप लगा रहे हैं। यह ठीक नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा): अध्यक्ष महोदय, यह लोग आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। यह इस सदन में ये क्यों नहीं बताते कि देश का बंटवारा किसने किया है। (शोर एवं व्यवधान) इन लोगों ने इस देश का बंटवारा कर दिया था और यह लोग हमें सलाह दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मेवात में इन लोगों ने मारकाट मचा दी थी उसके बारे में क्यों नहीं कहते? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई कि जो चाहे बोल दो। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी मेवात में मारकाट की बात कर रहे हैं, जरा बतायें तो सही कि मेवात में क्या हुआ था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप सब बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सदन में कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं होनी चाहिए। आफताब जी, आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, देखिए मंत्री मूलचंद शर्मा जी कैसे बात कर रहे हैं। मेवात में क्या हो गया बताइये तो सही? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आफताब जी, प्लीज आप बैठिए।(शोर एवं व्यवधान) सदन की मर्यादाओं का तो ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठिए (शोर एवं व्यवधान) आफताब जी अगर आप अपनी सीट पर नहीं बैठे तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको नेम कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, नेम करना है तो कर दीजिए लेकिन अगर कोई हमारे पर उंगली उठायेगा तो उसका जवाब दिया ही जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आपको सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी अपनी सीटों पर बैठने की सलाह देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए, सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि सदन की मर्यादा का ध्यान जरूर रखा जाये। हुड्डा साहब, मैं सभी लोगों से बैठने की अपील कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मैं सभी को बैठने के लिए कह रहा हूँ।

(शोर एवं व्यवधान) मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाये रखें।(शोर एवं व्यवधान)

मौहम्मद इलियासः सदर साहब, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इलियास जी, आपको खड़ा होकर बोलने की इजाजत किसने दी है। आप अपनी सीट पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, इलियास जी क्या कहना चाहते हैं आपको एक बार उनसे पूछ तो लेना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप पूछ लूंगा। इलियास जी, आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

मौहम्मद इलियासः सदर साहब, यह बी.जे.पी. केवल आर.एस.एस. के लिए काम करती है और देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इलियास जी, मैं आपको बार–बार कह रहा हूँ कि आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि इन लोगों ने देश को बांटने का काम किया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने प्रदेश को जलाने का काम किया था। यह लोग अपने बारे में क्यों भूल जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस पार्टी ने ही पाकिस्तान बनाकर हिंदुस्तान का बंटवारा किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कंवर पाल जी, प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, शाहीन बाग भी तो बी.जे.पी. वालों को याद रखना चाहिए। यह इनकी ही देन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गोगी जी, प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भपूेन्द्र सिंह हुड्डा जी आप भी प्लीज बैठिए और आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने सदस्यों

को समझायें कि वे इस तरह से सदन की कार्यवाही बाधित न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आपको सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी तो समझाने को काम करना चाहिए। आप हमें ही सलाह देते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्य अभी भी अपनी सीटों से उठकर खड़े हैं। आप उन्हें भी बिठाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, मैं आपको भी कह रहा हूँ और उनको भी कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है। (शोर एवं व्यवधान) बार–बार बिना पूछे खड़ा होकर सदन की व्यवस्था को खराब करने की इजाजत आपको कौन सा नियम देता है? (शोर एवं व्यवधान) अब मेरा निवेदन है कि आप सभी बैठ जायें और डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी बोलने के लिए काफी देर से खड़े हैं उनको प्लीज अपनी बात सदन में रखने दें।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि face the facts squarely otherwise the fact stabs on the back हमेशा आदमी किसी चीज को अनदेखा करता है तो उसका भुगतान करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के लिए भले ही अपने आपको भलेमानस का रूप दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि भलेमानसी से सरकार को चलाया जाये और हरियाणा प्रदेश को अच्छा बजट दिया जाये। लेकिन बजट में सरकार की तरफ से बहुत सारी खामियां रही हैं। हरियाणा के विकास का रोडमैप तैयार करने की खामियां रही हैं। हरियाणा की दिशा और दशा तय करने की खामियां बजट में रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की चीजें देश में डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है या प्रदेश में जा रही है और लोगों को भयभीत किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आपको बोलते हुए लगभग 43 मिनट हो गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी स्पीच को समाप्त कर दें क्योंकि आपके द्वारा समय ज्यादा लेने पर आपकी पार्टी के सदस्यों का बोलने का समय कम कर दिया जायेगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो डिक्टेटरशिप ऐटीट्यूड है इसमें समाज, प्रशासन, सैकुलरिज्म, सोशलिज्म और डैमोक्रेसी है वह खतरे में पड़ जायगी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सारे के सारे संस्थानों पर कब्जे हो गए हैं, देश और प्रदेश में भय का मौहाल बना हुआ है। आज प्रैस भी भयभीत है और आम आदमी भी भयभीत हो गया है। हमें प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहिए, लेकिन प्रदेश में दंगे हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मुझे लगता है कि आप बजट पर नहीं बोल कर दूसरे मुद्दों पर बोल रहे हैं क्योंकि बजट में दंगे का कोई भी जिक्र नहीं है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक गांव का किसान था। गांव का किसान शहर में चला गया और वह देखते–देखते पेंटिंग की दुकान पर चला गया। उस दुकान में एक बूढ़ा आदमी साफा बांधे हुए मुढ़े पर बैठ कर हुक्का पीते हुए की एक फोटो लगी हुई थी। वह किसान दुकानदार से बोला कि यह पेंटिंग मुझे दे दो। यह पेंटिंग कितने में दोग तो वह दुकानदार बोला कि 100 रूपये में, उसने कहा कि 70 रुपये में देगा, दुकानदार ने कहा नहीं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी बहन व बेटी शादी के लायक हो जाती है तो घर के चार–पांच आदमी लड़का देखने के लिए जाते हैं। जो पेंटिंग ले रहा था वही आदमी किसी गांव में लड़का देखने गया हुआ था। उसे वही घर बता दिया जो उस पेंटिंग को खरीद कर लाया था। वह किसान उस पेंटिंग को देखकर हंसने लगा और पूछने लगा कि यह फोटो किस की है। उसने कहा कि यह मेरा दादा की है। यह सुनकर वह आदमी और जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि यह 30 रुपये की ऐसी–तैसी हो गई वरना दादा तो मेरा था। यह सरकार तो हमारी थी लेकिन झुठे वायदे करके भाजपा और जजपा ने हथिया ली। (हंसी)

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, आप बजट पर ही बोले।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, ऑल इण्डिया जाट आरक्षण समिति ने मुझे एक ज्ञापन दिया है और उसमें हजारों आदमियों के हस्ताक्षर हैं। इसलिए मेरी जिम्मेवारी भी बनती है और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जिन लड़कों पर मुकद्दमे दर्ज हैं उन्हें सरकार को वापिस लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि उन दर्ज मुकद्दमों को वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, यह बात आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोला था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि 'सबका साथ सबका विकास' लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से विकास नहीं हुआ है। मैंने वर्ष 2015–16 में भी बेरी हल्के का लेकर विकास की बातें कही थी और वही बातें आज ज्यों की त्यों हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आज आप हाउस में कुल 46 मिनट तक बोले हैं ।

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak): Hon'ble Speaker Sir, I am grateful to the Chair that I have been given time to speak on the Budget as well as to make certain clarifications also. On 27th February, 2020, the Hon'ble Chief Minister raised certain points and I was not allowed to make clarifications at that time. I will also speak on the Budget Estimates. So far as Multi-Parking Commercial Complex, Rohtak is concerned, the Hon'ble Chief Minister, I can say with the conviction i.e. he has mislead the House. He has placed the untrue facts which should not be either there has been ill-feeding back or there was no correct facts before him. He specifically mentioned that this bid has finally put a stamp by the Supreme court. Through you Hon'ble Speaker Sir, I may request the Hon'ble Chief Minister that the writ petition which has been filed in the High Court and I can mention the number of the petition. The officers who are sitting here and looking after this very department, can also have a look at this Petition No. 9030 of 2019. This petition was filed by Shivalaya Construction Company Private Limited against the State of Haryana in which technical bid, I specifically mention the words "technical bid" was rejected by the MC Rohtak and that has been challenged by Shivalaya Construction Company Pvt. Ltd. and the Chief Justice Bench passed the order. I will read out the relevant portion with the permission of the Hon'ble Chief Minister to that Judgement to which you referred कि यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में सैटल हो गया था ।

(Interruption) Speaker Sir, I am coming to that point also. Firstly I will read out what was the judgement of the Hon'ble High Court and then I will come to the judgement passed by the Supreme Court also. Hon'ble Speaker Sir, I am open to it. Hon'ble Chief Minister, you can call your Advocate General in this Vidhan Sabha also to make clarifications before the House. What has been stated in this august House at that time, I think his opinion was not taken otherwise also. This is only technical bid of Shivalaya Construction Company was rejected. There was no stamp of any High Court on the basis of that the tender has been allotted in favour of Richa Krishna Construction Private Limited. No stamp of any High Court was there. (Interruptions)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बजट पर बोलना चाहिए ।

Shri Bharat Bhushan Batra: How you are objecting it? माननीय मंत्री जी भी कमाल करते हैं । मैंने अध्यक्ष महोदय से बजट पर बोलने की इजाजत मांगी थी । Hon'ble Chief Minister has acceded to my request कि आप रिप्लाई दे देना and he is listening my request. आप कहते हैं कि आप बजट पर बोलिये । मैं बजट पर भी बोलूंगा और आपके कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पर भी बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, माननीय सदस्य को बीच में इंट्रप्ट न करें ।

Shri Bharat Bhushan Batra: Hon'ble Speaker, Sir, petitioner has approached this Court under Article 226 of the Constitution of India challenging the order dated 11.3.2019 passed by the authorities rejecting the representation made by him against holding his technical bid to be non-responsive. There are three reasons set out in the order for rejecting the technical bid by the Technical Evaluation Committee:

(1) The Bidder has not furnished its banker's details; (2) The Bidder has not furnished a copy of concession agreement with each page initialed by the person signing the bid in pursuance of the power of attorney; and (3) In the Net worth certificate furnished by the bidder the methodology for Net worth admitted factual position, we see no illegality in the order

passed by the authorities, his technical bid has rightly been rejected and accordingly the appeal stands dismissed. It's alright.

It was a dispute between M/s Shivalaya Construction Company Pvt. Ltd. and The State of Haryana and others. M/s Shivalaya Construction Company Pvt. Ltd. again went to the Supreme Court.

Hon'ble Supreme Court on this point did not entertain the Special Leave to Appeal (c) Nos.11543-11544/2019 and passed the order that -

> "We see no reason to entertain this petition. Accordingly, the special leave petition is dismissed."

It is a legal position which is always arisen from the common parlance. What the thing is applied to a common man i.e. always a law. और लॉ से बाहर कोई नहीं जा सकता। शिवालिक कंस्ट्रक्शन कम्पनी की टैक्निकल बिड आयी और वहां पर उसकी टैक्निकल बिड को डिसमिस कर दिया। The matter is hence there. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसमें लॉ यह है कि without notice to the State, it has been rejected without any finding on merit. We do not see this is not an order of merit or never an order on merit. यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट के जजमैंट पर मोहर नहीं लगायी और न ही उसको इन्टरटेन किया। इसके बाद भी संबंधित इशू रेज हो सकता था। That is the legal position. I will request that you can take a legal opinion because at that time you said that कि आप वकील भी हैं, फिर भी आपको पता नहीं है that's why it pained me. That's why I am pointing out with all humanity at my command. So far as the next point is concerned, I will say that the Hon'ble Chief Minister in his speech has raised a very good point that was credible primary material. This is the wording used in the House. Hon'ble Chief Minister, Sir, this file has been approved by you and by giving your clearance. Clearance should have come from the other body. अब मैं इसमें बड़े– बड़े प्वॉयंट्स नहीं रखूंगा बल्कि छोटे–छोटे प्वॉयंट्स रखूंगा। There is one wording 'SPV' Special Purpose vehicle जब स्पैशल परपज

व्हीकल बनता है तो वह स्पैशल परपज व्हीकल एक कम्पनी को दिया जाता है **i.e.** Richa Construction Private Limited and Richa Industrial Limited was going through 'दिवालिया' and IRP was appointed there. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वह कम्पनी दिनांक 1.1.2019 को बनी थी और उसकी नैट वर्थ 1 लाख रुपये थी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्पैशल परपज व्हीकल दो एन्टीटीज के बीच में एक समझौता होकर बनता है। इसमें एक तो बता रहे हैं कि रीचा कम्पनी थी, परन्तु यह भी बता दें कि दूसरी कम्पनी कौन सी थी ?

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आई.एन.डी. सॉल्यूशन कम्पनी वर्ष 2016 में रजिस्टर्ड हुई थी, परन्तु बिड में कम्पनी की 5 साल की रजिस्टर्ड होने की रिक्वायरमैंट थी और संबंधित कम्पनी 5 साल की कंडीशन को पूरा नहीं करती थी। फिर इसके बाद बिड डाक्यूमैंट्स में देखेंगे तो उसमें सभी कम्पनीज के लिए 5 करोड़ रुपये की असैट्स की रिक्वायरमैंट और उनके एक्सपीरियंस में 20 करोड़ रुपये की टर्नओवर की कंडीशन थी। आप जो एस.पी.वी. बना रहे हैं उसका ट्रेडिशंज कहां पर देखेंगे, क्योंकि आपने एस.पी.वी. तो ऐसी कम्पनी को दे दिया जिसकी नैट वर्थ 1 लाख रुपये की थी। This is a point. अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त फैक्ट्स में देखें कि जस्टिस नागरथ्न ने दिनांक 21.12.2019 को आई.आर.पी. (Interim Resolution Professional) अपायंट किया था और वह कम्पनी दूसरे हाथ में चली गयी थी। Why the Government preferred with that Company?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय,(शोर एवं व्यवधार)

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को संबंधित विषय की जितनी डिटेल मालूम हैं, उतनी डिटेल मुझे मालूम नहीं हैं।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि संबंधित मामले की इन्कवायरी करवायी जाए। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जब इस तरह का कन्टैंट होता है तो स्पैशल परपज व्हीकल बनाया जाता है, वह कम्बाइंड परपज व्हीकल होता है। इसमें दोनों कम्पनीज का असैट्स और टैक्निकल बिड मिलाकर एस.पी.वी. का माना जाता है। यानी किसी एक कम्पनी का नहीं माना जाता। इसकी अगर कोई डिटेल होगी तो उसके बारे में बाद में बता देंगे।

श्री भारत भूशण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मान लो मैंने और दूसरे व्यक्ति ने दो अलग–अलग कंपनियां बना ली और हम तीसरे व्यक्ति को एस.पी.वी. बनाते हैं और एस.पी.वी. के पल्ले कुछ नहीं होता है। All the payments you will make to him, not to him or me. हरियाणा सरकार के सारे पैसे रिचा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को जायेंगे और इसकी सिर्फ 1 लाख रुपये नैट वर्थ है। सरकार चाहे तो इसको एग्जामिन करवा सकती है। I am speaking with all conviction.

श्री मनोहर लाल : बत्तरा जी, हम इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इसमें बड़ा भारी घोटाला है और आप इसकी जांच पड़ताल करवाओ। इसको आप विदहोल्ड करो। सभी को पता है कि वहां पर इस जमीन की क्या कीमत है? मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि आज इस जमीन की वैल्यू 150–200 करोड़ रुपये है और सरकार इसे 17 करोड़ रुपये में दे रही है। उनको दुकानें बेचने का अधिकार है।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, आपकी सरकार में इन दुकानों की एच.एस.वी.पी. ने 32 करोड़ रुपये में ऑक्शन की थी। जब वहां के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो सरकार ने उसको दिनांक 8 जनवरी, 2014 को रद्द भी किया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार भी इसको रद्द कर दे। जब हमारी सरकार को इस बारे में पता लगा तो हमारी सरकार ने इसको रद्द कर दिया था। आज हम इस बात को सरकार को कह रहे हैं कि इसका रद्द कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, सी.एम. साहब ने कहा है कि संबंधित विषय की जांच करवायेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमने इसकी ऑक्शन रद्द की थी क्योंकि हमारी सरकार वहां पर पार्किंग बनाना चाहती थी और वर्तमान सरकार ने वहां पर 15 लाख रुपये लगाकर कॉमर्शियल दुकानें बना दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा इस विषय में कोई व्यक्तिगत रोल भी नहीं है। मैं सरकार को यह बात सही कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां का निवासी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय से संबंधित इतना ही कहना है कि प्रदेश में यह बहुत बड़ा घोटाला है और यह बात सरकार के हित में है इसलिए इसको रद्द करके इसकी इन्क्वायरी करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा जी, सी.एम.साहब ने संबंधित विषय की इन्क्वायरी के लिए पहले ही कह दिया है।

श्री भारत भूशण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लीडर ऑफ दि अपोजिशन श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की कर्म भूमि रोहतक रही है और जहां पर यह दुकानें बनाई जा रही है उस भिवानी स्टैंड की पोजीशन के बारे में ये अच्छी तरह से समझते और जानते भी हैं और इन्होंने वह जगह एक बार नहीं बल्कि 10 बार देखी है। मैं सिर्फ दो छोटे–छोटे प्वॉयंट्स रखना चाहता हूं।

श्री मनोहर लाल : बत्तरा जी, हम आपको यह बात कह रहे हैं कि सरकार इसकी जांच करवायेगी इसलिए आप इस इशू को छोड़ दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बत्तरा जी, प्लीज आप बजट पर चर्चा करें।

श्री भारत भूशण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर जरूर चर्चा करूंगा लेकिन I will enlighten you कि ग्राउंड फ्लोर पर 1300 गज जमीन में 26 दुकानें बनी हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बत्तरा जी, सी.एम.साहब ने संबंधित विषय की इन्क्वायरी के लिए कह दिया है इसलिए प्लीज, अब आप बजट पर चर्चा करें।

श्री भारत भूशण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात दो लाइनों में ही समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि भी खराब हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, 1300 गज जमीन के लिए 2 करोड़ रुपये अपफ्रंट प्रीमियम और सरकार ने कंट्रेक्टर से 17 करोड़ रुपये लगवा लिए तथा उसको 1300 गज जमीन ग्राउंड

फ्लोर की सारी की सारी दे दी। सरकार चाहे तो वहां पर 1300 गज जमीन का क्या रेट है, उसके बारे में पता करवा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, आप ऐसे बीच में नहीं बोल सकते हैं। प्लीज, आप बैठ जायें (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, आपको बोलने के लिए अभी मैंने अलाऊ नहीं किया है। अगर सभी सदस्य बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो किस तरह से हाउस की कार्यवाही चलेगी? प्लीज, आप बैठ जायें। जब आपको बोलने के लिए समय दिया जायेगा तब आप अपनी बात कह लेना। अब प्लीज, आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) बत्तरा जी, क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है?

श्री भारत भूशण बत्तरा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक दो प्वॉयंट्स पर चर्चा करनी है और मेरी आपसे विनती है कि कूंडू साहब को बोलने के लिए जरूर टाईम देना। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि पानीपत शुगर मिल और करनाल शुगर मिल, I will only speak on Panipat. मैंने पानीपत शुगर मिल के बारे में सरकार को कभी भी नहीं कहा कि उसकी पिराई क्षमता 10 हजार टन या 15 हजार टन थी। डिप्टी स्पीकर सर, पानीपत शुगर मिल की पिराई क्षमता 1800 टन थी और सरकार द्वारा उसको 7500 टन किया गया। चार गुणा बढ़ाने के लिए सरकार के सम्बंधित विभाग की क्या डिस्क्रिशनरी थी। I will not question to the credentials of the Government. इसके अंदर यह था कि आपको नहीं पता जिसकी टर्म्ज एण्ड कंडीशंज ऐसे टेलर कर दी गई कि नेशनल को–ऑपरेटिव शूगर मिल्ज की 14 कम्पनियों को सैंट्रल गवर्नमैंट फैक्ट्रीज लगाने की एप्रूवल देती है। उसकी कंडीशंज आई कि सिर्फ तीन कम्पनियों ने ही क्वालिफाई किया है। चलो वह भी सरकार ने टैण्डर डॉकूमैंट कर दिया और सब कुछ कर दिया। मेरी इस मामले में आखिरी शिकायत है कि सरकार के रिकॉर्ड के अंदर मिसिज ज्योति अरोड़ा, सीनियर आई.ए.एस. ऑफिसर ने वहां पर एक रिपोर्ट

दी हुई है जो सम्बंधित डिपार्टमैंट में दबी हुई है अगर उस रिपोर्ट को निकालकर सदन के पटल पर रख दिया जाये तो सारी की सारी स्थिति पूरी तरह से क्लीयर हो जायेगी कि इस मिल के मामले में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंक्वॉयरी मार्क की हुई है और उसके ऊपर वह रिपोर्ट आई हुई है। सरकार ने इस बात माना भी है। सरकार के टैण्डर में यह डॉकूमैंट था कि यह टर्न की बेसिज पर होगी अर्थात् सब कुछ तुम करो हम तो आखिर में चाबी घुमाएंगे। अपने पैसे जितने हैं आप मांग लो। ये जो आपने इनको जी.एस.टी. का अलाऊ किया उसमें कंट्रैक्टर ने बहुत कुछ फायदा उठाया है। आपको कह दिया कि दो करोड़ रुपये की एक मशीन आयेगी। उसका जी.एस.टी. सरकार ने भरना है। उसकी इंवॉइस और चार करोड़ रुपये का बिल लेकर आ जायेगा क्योंकि सरकार ने यह एग्री कर लिया कि जी.एस.टी. सरकार भरेगी। मेरा यह कहना है कि इस मामले में सरकार को सीधे तौर पर यह कह देना चाहिए था कि जी.एस.टी. तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा और इतना कुछ तुम्हारा। हमारे से तो ये पैसे लो और हम चाबी घुमाएंगे और चाबी घुमाकर ये सभी कुछ कर देंगे। इस प्रकार से ये सारे का सारा मामला प्रॉयरिटी के अंदर था। तीसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए शरक मत कीजिए। आपसे मेरी रिकवैस्ट है कि इस मामले की इंक्वॉयरी करवाने के आदेश करने से आपकी रैपुटेशन इंहांस होगी। अगर इस मामले में सब कुछ क्लीयर है अर्थात् सभी कुछ ठीक है तो हमें कोई एतराज नहीं है। We will give credit to you और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दो बिल कहो तो दो मिलें। इस प्वॉयंट के ऊपर मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की लगी हुई है सेम पानीपत शुगर मिल के पैटर्न पर। अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहें तो मैं उनके नाम एक मिनट में सदन में पढ़कर सुना देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर सेम कैपेसिटी की बिल्कुल 5000 हजार टन की कैपेसिटी की मिल बनी और उसकी बिडिंग वगैरह आई। आप इसके बारे में अपने स्तर पर पता कर लें उसकी टोटल लागत 217 करोड़ रुपये आई। Everything is same. कैपेसिटी सेम, सारी मशीनरी नई, कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी हाउस में यह कहा था कि इसके ऊपर 356 या 370 करोड़ रूपये की लागत आई है। Why there is a difference? सिमिलरली महाराष्ट्र की भी हैं। जो आपके पास कम्पलेंट हैं और जिसमें मैडम ज्योति अरोड़ा जी ने रिपोर्ट दी है आपने उस कम्पलेंट में मार्क किया

हुआ है। उसमें सब फर्मों के नाम हैं इसीलिए जो भी नेगोसिएशन टेबल पर बैठा मैं उसकी बात नहीं करता that Government can sit and pass an order. सब कुछ है पर जो आपने आपकी बातों से यह लगा कि हमने जी.एस.टी. दिया तो 25 परसैंट तो जी.एस.टी. और एक्साईज हो गई इस प्रकार से 25 परसैंट का बैनीफिट तो आपने उसको नैगोसिएशन टेबल पर दे दिया और आपके टैण्डर्ड डॉकूमैंट पर यह आ गया कि टर्न की बेसिज पर सेल्स टैक्स और एक्साईज आप देंगे।

डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं थोड़ा सा समय बजट के ऊपर बोलने के लिए लेना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पीच में और प्रैस कांफ्रैंस में भी यह कहा कि हमने कर्ज लिया है और हम और भी कर्ज लेंगे। You justified it. 1.98 हजार करोड़ के कर्ज को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जस्टीफाई किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंदर हम इस कर्ज को ले सकते हैं। जी.एस.डी.पी. का हम 25 परसैंट लोन ले सकते हैं। यह ठीक बात है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वही एक्ट यह भी कहता है कि आपका रेवेन्यू डैफिसिट भी जीरो परसैंट होना चाहिए। अब आप अपना फायदा उठाने के लिए एक्ट के एक प्रावधान का तो फायदा उठा सकते हैं। आपका रेवेन्यू डैफिसिट जीरो तो है नहीं यह आपका 1.64 प्रतिशत है जो कि आपका रिकॉर्ड बता रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार के ऊपर घाटा बहुत ज्यादा है। अगर आप लोन लेते हैं तो साथ में ही आपको कैपिटल इनवैस्टमैंट करनी चाहिए। कैपिटल इनवैस्टमैंट तो आपकी हो ही नहीं रही हैं। 15 हजार कुछ करोड़ रुपये तो आप सीधा–सीधा रेवेन्यू डैफिसिट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। आप कैपिटल इनवैस्टमैंट कहां से करेंगें? बाकी बचे 11 हजार करोड़ रुपये तथा 25 हजार करोड़ रुपये का आपका लोन देने के बाद आपके पास खर्च करने के लिए क्या बचेगा? आपने बाइफरकेट करके देख लिया है आपका प्लान और नॉन प्लान का बजट कितना बनता है।उसके बाद हमारे समय के प्लान और नॉन प्लान की बात करेंगे। अब मैं कैपिटल एक्सपैंडीचर के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। कैपिटल एक्सपैंडीचर के बारे में बहुत से सदस्यों को तो पता भी नहीं होता है कि कौन सा कैपिटल एक्सपैंडीचर होता है। आप देखिए हमारे समय में वर्ष 2014–15 में जब हम सरकार छोड़ कर गये थे उस समय फिस्कल डैफिसिट 0.97 प्रतिशत था। उस समय हमने 6 महीने का बजट पेश किया था उस समय फिस्कल डैफिसिट जितना था उसको आपने किसी हालत में भी कम

नहीं किया। अब मैं डिवैल्पमैंट पर अपनी बात रखना चाहता हूं। वर्ष 2008–09 में डिवैल्पमैंट पर कुल बजट का 56 प्रतिशत खर्च होता था। उसके बाद वर्ष 2009–10 में 55 प्रतिशत, वर्ष 2010–11 में सबसे ज्यादा 67.77 प्रतिशत कुल बजट का डिवैल्पमैंट पर खर्च होता था। वर्ष 2011–12 में 57 प्रतिशत और वर्ष 2014–15 में जब हम सरकार छोड़ कर गये तब 60 प्रतिशत खर्च होता था जबकि मुख्यमंत्री जी आपके इस बजट ऐस्टीमेट्स में केवल 52 प्रतिशत विकास पर खर्च होना है। विकास पर तो आप बहुत कम खर्च कर रहे हैं। आपने इन आंकड़ों को डाउन किया है। आप कर्ज ले रहे हैं और कर्जे को जस्टीफाई भी कर रहे हैं लेकिन आपको रेवेन्यू डैफिसिट को जरूर कम करना चाहिए। रेवेन्यू डैफिसिट 15 हजार करोड़ रुपये है, आप उसको, कहां से पूरा करेंगे? आपने टोटल बजट में यह दर्शाया है कि आपके पास 11 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल इनवैस्टमैंट है जो कि आपके पास टोटल असैस्ट्स है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास केवल 11 हजार करोड़ रुपये का यही एक असैट्स है। 1,98,700/– करोड़ रुपये के कर्ज के बाद तथा 1,42,343.78 करोड़ रुपये के कुल बजट के बाद आप टोटल प्लान में जो खर्चा फिस्कल डैफिसिट को दूर करने के लिए हमें दे रहे हैं वह सिर्फ 11 हजार करोड़ रुपये है। इसके बाद आपकी इंट्रस्ट की पेमैंट कितनी चली जाती है? आपके कुल बजट का 28 प्रतिशत तो ऐसे ही चला गया तथा उसके बाद रेवेन्यू डैफिसिट आ गया।

श्री उपाध्यक्षः बतरा जी, आपको बोलते हुए 23 मिनट का समय हो गया है। अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों का समय कट जायेगा।

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि लोन की रीपेमैंट पर कुल बजट का 28.61 प्रतिशत खर्च हो रहा है जो कि अलार्मिंग सिचुशन है। आप कह रहे हैं कि हम और भी कर्जा लेंगे। अगर आप और कर्जा लेंगे तो आपको कैपिटल इनवैस्टमैंट भी बढ़ानी चाहिए तथा फिस्कल डैफिसिट आपको जीरो करना चाहिए। किसी को कोई ऐतराज नहीं है, आप स्टेट को चमकाइये। इसी प्रकार से अगर एग्रीकल्चर पर खर्च करने की जहां तक बात है तो आप देखिए कि आपने एग्रीकल्चर पर 12.42 प्रतिशत बजट ऐलोकेट किया है। अगर एग्रीकल्चर के साथ–साथ उसकी एलाइड की भी बात करें तो 3.85 प्रतिशत आप खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोऑपरेशन पर आप 0.9 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब मैं इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सिज को भी किसानों के साथ गिनता हूं आपने

इस बजट के अन्दर टोटल 28.27 प्रतिशत किसान के नाम अर्थात कृषि विभाग को दिया है और बाकी विभागों के लिए आपने 45 प्रतिशत बजट दिया है। हमारे सामने आपका जो बजट आया है उसमें मैं सिर्फ दो बातें मैंशन करूंगा। इस समय स्वास्थ्य मंत्री सदन में बैठे नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको तो स्वास्थ्य के बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपने स्वास्थ्य के लिए अपने बजट में तीन प्वॉयंट कुछ दिया है। आपने एजूकेशन के लिए अच्छा बजट दिया है लेकिन जब तक आप किसान की हालत को नहीं सुधारोगे तब किसान की आय नहीं बढ़ेगी इसलिए एग्रीकल्चर विभाग के लिए भी आपने बजट में ध्यान रखना चाहिए था। अब मैं आखिरी प्वायंट पर आंऊगा जिसमें आपने कुछ रिलीफ की बात की है। मैंने आपको subvention of interest का सुजैशन दिया था जिसको आपने अपनी बजट स्पीच के अन्दर मैंशन किया है कि इस समय ब्याज मुक्त ऋण सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं से लिये गये ऋणों पर उपलब्ध है और इसकी सीमा 1.5 लाख रुपये है। यह ठीक बात है। मैं इसको पढ़ देता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसान को राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड 60 हजार रुपये तक और अधिकतम 3 लाख रुपये तक फसली ऋण मिलेगा जिसका 4 प्रतिशत इंट्रस्ट है जिसको सरकार कहती है कि हम जीरो प्रतिशत कर देंगे। आपने कहा है कि कॉमर्शियल बैंक का भी कर दीजिए । कॉमर्शियल बैंक भी कर सकते हैं लेकिन आपको स्टेट गवर्नमैंट से पैसा देना पड़ेगा। सैंटर गवर्नमैंट आपको पैसा नहीं देगा। उसमें आपने अपने बजट में पफ आऊट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें पहली कंडीशन बिल्कुल ठीक है कि किसान निर्धारित समय पर ऋण की अदायगी करे। बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि तभी किसान को आगे ऋण मिलेगा, अगर किसान ऋण की समय पर अदायगी नहीं करेगा तो उसको आगे ऋण नहीं मिलेगा। दूसरा जो आपने 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' पोर्टल बनाया है जिसमें किसान को अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अध्यक्ष महोदय, किसान कमजोर व अनपढ़ किसान है। उसको आपने क्या पोर्टल में फंसा दिया है। इसी तरह से मेरा अगला प्वॉयंट है कि सरकार ने अब यह कर दिया है कि किसान की जो फसल बिकेगी उसका पैसा सीधा बैंक में जमा होगा। इससे तो किसान मर जाएगा। उसकी बेटी की शादी है, उसके बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना है। Why this condition?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : बतरा जी, अभी मेरे पास 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' स्कीम के तहत एक ताजा आंकड़ा आया है। उसी को मैं बताना चाहता हूं। मेरी

फसल, मेरा ब्यौरा यह एक रेगुलर डायनमिक प्रौग्राम है। अभी मैंने साढ़े तीन बजे जब सैशन चल रहा था तब यह आंकड़ा देखा था। उस समय 44 लाख 10 हजार एकड़ जमीन का डाटा उस स्कीम में दर्ज हुआ था और अब ठीक एक घण्टा बीस मिनट के बाद यह डाटा 44 लाख 13 हजार हो गया है। यह 3 हजार का डाटा अभी एक घण्टे के अन्दर बढ़ा है। यह सभी किसान अपनी इच्छा से दर्ज कर रहे हैं। इसमें किसी किसान पर दबाव नहीं दिया गया है। इसमें हमने ये भी किया है कि जो किसान मेरी फसल, मेरा बयौरा में अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करता है तो सरकार उस किसान को भी पैसा देती है और जो सी.एस.सी. यानि जो अटल सेवा केन्द्र हैं उनको भी दर्ज करने का पैसा देती है। अगर कोई किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन आखिर तक नहीं भी कर पाएगा जैसे अब फसल की कटाई के बाद तो उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह फसल की कटाई से पहले–पहले दर्ज करना होता है। फसल की कटाई से पहले–पहले जो बाकी जमीन रह गई है उस सारी जमीन का एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट और रेवैन्यु डिपार्टमैंट भी अपना डाटा इकट्ठा करेंगे और फिर उन सबका डाटा मिलाकर देखा जाएगा। हम चाहेंगे कि इसको अभी धीरे–धीरे करें क्योंकि अभी इस स्कीम को शुरू हुए एक साल हुआ है और अभी इसमें दो–तीन फसल का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम चाहेंगे कि किसान को धीरे–धीरे इस स्कीम की आदत लगे कि वह हर 6 महीने में उसने अपनी जमीन पर क्या बोया है, क्या नहीं बोया है उसका ब्यौरा दे? अगर जमीन खाली है तो उसमें खाली लिखे। उससे बहुत से विश्लेषण, बहुत सी प्लानिंग बनाने का काम, उसका कहीं कोई मुआवजा होता है, फसल खराब हो गई है तो उसको उसका लाभ मिल सकता है। बैंकों के साथ बहुत झंझट है। उसकी प्रक्योरमैंट क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि हम एम.एस.पी. पर सारी फसल खासकर जो फसल सैंट्रल गवर्नमैंट नहीं खरीदती है। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको भी खरीदने का प्रबंध करें। लेकिन वह तभी होगा जब हरियाणा के किसान का सारा डाटा हम सैट कर लें अन्यथा हरियाणा में पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान या यू.पी. का किसान आयेगा और फायदा उठाकर चला जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों को लाभ देना चाहती है और इसी वजह से हम अपने किसानों का निरंतर डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डाटा लेना सरकार का काम होता है और डाटा जितना बढ़िया होगा, जितना गोल्डन होगा उतना ही किसान को लाभ होगा।

डॉ रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का सारा डाटा तो रेवेन्यू डिपार्टमैंट के पटवारी जोकि गिरदावरी करता है, के पास भी होता है। यही नहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में भी यह सब डाटा होता है कि किसके पास कितनी जमीन है या किसान ने अपनी जमीन में क्या बोया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी फसल – मेरा ब्यौरा जो स्कीम है उसके तहत कवर होने के लिए मान लो मैंने अपनी फसल का ब्यौरा देते हुए अपनी 2 एकड़ जमीन में 60 मन बाजरा लिखवा दिया तो ऐसी हालत में जैसाकि सबको पता है कि सरकार ने जो कैप लगा रखी है उसके तहत वह अगर एम.एस.पी. से बाजरा लेगी तो वह मात्र 15 मन ही बनेगा तो बताओ जो यह 45 मन बाजरा बच गया, किसान के इस बाजरे को कौन खरीदेगा?

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे बाजरे को सरकार ही खरीदेगी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, यह वह प्रॉब्लम है जिसका आज किसान को सामना करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कैप लगाने के पैमाने को बढाया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कादियान जी, आप प्लीज बैठिए और बतरा जी को अपनी बात रखने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, बजट के स्पीच में पैरा न. 119 में कुछ गलत फैक्ट्स लिखे हैं कि सरकार ने इतने मैडिकल कॉलेज बनाये, मैं इस बात के डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसको एफ.एम. साहब/सी.एम. साहब अपने आप क्लीयर कर लेंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा पी.जी.आई.एम.एस. हरियाणा प्रदेश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में सरकार अगर जान फूंकना चाहती है ताकि हरियाणा के लोग गुड़गांव व दिल्ली की तरफ न इलाज के लिए न भागें, हम भी मेदांता जैसे अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो इन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यकता है कि सरकार को इस प्रीमियम इंस्टीट्यूट को एक विशेष पैकेज देने का काम करना चाहिए। सरकार ने इस इंस्टीट्यूट को सिर्फ खर्च के पैसे देकर इतिश्री समझ ली है लेकिन इसकी डिवेल्पमैंट के लिए कोई भी पैसे का प्रावधान नहीं किया है। बजट में यह तक नहीं बताया कि इस इंस्टीट्यूट में कितने वैंटीलेटर्ज दिए जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देखा होगा कि यहां पर जो पुरानी ओ.पी.डी. है वह

वर्ष 1960 में बनी थी। यहां से सरकार को एक प्रपोजल आई हुई है कि इसको गिराकर नई ओ.पी.डी. तथा ब्लॉक बनाया जाये लेकिन इसके लिए बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो राजीव गांधी स्पोर्टस स्टेडियम है उसके लिए बजट में पैसों को कोई प्रावधान नहीं किया गया है reason best known to him. But I will say that only कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात गीता की करते हैं और इसी प्रकार और बड़ी–बड़ी बातें सरकार की तरफ से की जाती है यहां तक की स्वामी विवेकानन्द जी का उदाहरण लेकर भी सरकार के लोग बात करते हैं लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि when you play football you are more near to heaven as compared to read Geeta. अगर सरकार इतने बड़े–बड़े लोगों का संस्मरण लेकर बात करती है तो सरकार को स्पोर्टस स्टेडियम जैसे विषय की महता को भी नहीं नकारना चाहिए और स्वामी विवेकानन्द जैसे लोगों की प्रेरणा पर हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्धार करते हुए, यहां पर बढ़िया क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहिए इसका टर्फ बढ़ाना चाहिए और अन्य दूसरी सुविधओं को मुहैया करवाकर यहां के खिलाड़ियों को राहत प्रदान करने का काम भी करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला) (एस.सीज.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी तथा जननायक जनता पार्टी का यह सर्वांगीण विकास का बजट है जो पूरी तरह टैक्स फ्री है। इस बजट में सभी वर्गों को जगह मिली है। बजट में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ समाज के कल्याण पर भी पूरा फोकस किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आम कॉमन मैन की बात इस बजट में सुनी गई है, इसलिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूँ। गठबंधन सरकार के बजट में जैसे कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट के आंकड़ों में बाजीगरी की गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गठबन्धन सरकार ने सीधा और स्पष्ट बजट पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में शिक्षा और चिकित्सा पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 142343 करोड़ रुपये का यह बजट पिछले वर्ष के मुकाबले 7 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने बजट में गरीब की रोटी, युवाओं को रोजगार और महिला की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। यह बात ठीक है कि बजट का 28 प्रतिशत हिस्सा ब्याज चुकाने में लग जायेगा परंतु यह पूरा बजट संतुलित है जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पेश किया है। इसके लिए माननीय

मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक अनमोल रत्न है। शिक्षा हर नागरिक के लिए जरूरी है। 28 प्रतिशत बजट शिक्षा पर पहले से ज्यादा रखा गया है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही सारी चीजें फोकस की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक सत्र 2020–21 से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर एवं अधिगम परिणामों में बढ़ौत्तरी के उद्देश्य से कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ की गई है। हरियाणा प्रदेश में 'बस्तामुक्त एवं अंग्रेजी माध्यम' के 418 प्राथमिक विद्यालय हैं। हमारी गठबन्धन सरकार ने 100 और विद्यालयों की स्थापना उन गांवों में करने का निर्णय लिया है, जहां अभी दो से अधिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से बहुत गहराई में जाकर बजट बनाया गया है। मार्डन आई0टी0आईज0 व 500 नये क्रैच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भारत से बाहर के विश्वविद्यालायों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने हेतु महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जायेंगे। शैक्षणिक सत्र 2020–21 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार करते हुए इसमें 1 लाख 80 हजार रूपये वार्षिक से कम आय वाले गरीब परिवारों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया जायेगा। इसके अन्तर्गत इन विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं वर्दी का प्रावधान किया गया है। हमारे प्रदेश की बेटियों के लिए बी0ए0 तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हमारी बेटियां जो देहात क्षेत्र से शहर में शिक्षा ग्रहण करने आती हैं उनको मुफ्त साईकिल देने का भी प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय उपमुख्यमंत्री जी को बधाई को देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृति योजना के तहत 5वीं कक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए संचालित परीक्षा के आधार पर 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1500 रुपये से 6000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्तियां देने का बजट में प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही अच्छा काम सरकार ने किया है। जो बच्चे पहले प्राईवेट स्कूल में जाने लगे थे और सरकारी स्कूल में नहीं जाते थे, अब सरकारी स्कूल्ज का गैप खत्म हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यालयों की प्रभावी ढंग से देखरेख के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से 500 विद्यार्थियों तक की संख्या वाले 3581 स्वतंत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3793 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और 500 से अधिक संख्या वाले विद्यालयों में 212 कार्यकर्ता नियुक्त किये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 हजार रुपये का मानदेय दिया जायेगा। इससे हमारे प्रदेश में बेरोजगारी भी दूर होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन, कैथ लैब और एम0आर0आई0 जैसी सेवाएं प्रदान की गई है। इसके अलावा कीमोथैरेपी की सुविधा दी गई है और डायलसिस के लिए उप–मंडल स्तर पर सुविधा दी जाएगी। यह एक बहुत बड़ी देन है क्योंकि पहले देहात में ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी । अब देहात में भी ये सुविधाएं प्राप्त होंगी । डिप्टी स्पीकर सर, हम रिजर्व कैटेगरी से चुनकर आते हैं, इसलिए हमारा यह दायित्व है कि हम सदन में उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनके हित की बात करें । अनुसूचित जाति और वंचित समुदाय के लिए यह बजट एक रामबाण साबित होगा । 2 अप्रैल, 2018 में सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला देकर एट्रौसिटी एक्ट को निरस्त कर दिया । एट्रौसिटी एक्ट के तहत जब कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाता था तो उस व्यक्ति को उसी समय अरैस्ट किया जाता था । सिंगल बैंच के फैसले के अनुसार सीधे ही एफ.आई.आर. दर्ज होने की बजाय एक डी.एस.पी. रैंक का अधिकारी उसकी इंकवायरी करेगा और उसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज होती । इस फैसले से यह सारा एट्रोसिटी एक्ट निरस्त हो गया । जब यह बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी के नोटिस में आई कि एट्रौसिटी एक्ट को खत्म कर दिया गया है तो उन्होंने उसको पुनः लागू कर दिया । हमारे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी ने इस एक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए सिंगल बैंच के फैसले से खत्म हुए एट्रोसिटी एक्ट को पुनः लागू कर दिया । इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । यह एक्ट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है क्योंकि जिसके साथ बीतती है वही जानता है । डिप्टी स्पीकर सर, एस.सी. वर्ग को इस सरकार ने सौगात दी है । उनको हरियाणा में कानूनी सहायता मिलती थी । जब अपराधी अपराध कर देते थे तो उस गरीब आदमी को 11 हजार रुपये ऐडवांस में कानूनी सहायता के लिए दिए जाते थे क्योंकि उनके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं होते थे । यह सरकार गरीब के

17:00 बजे

हितों के प्रति सजग है । इस सरकार ने उनके हित में फैसला करते हुए इस राशि को दोगुना बढ़ाकर 22 हजार रुपये कर दिया है । इस सरकार ने फैसला किया है कि एस.सी. कैटेगरी के कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को कोचिंग के लिए एक लाख रुपये सहायता दी जाएगी । विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एस.सी. कैटेगरी के बच्चे काफी समय से हॉस्टल्स में 20 परसैंट सीटें मांग रहे थे । सरकार ने अब उनके लिए हॉस्टल्स में 20 परसैंट सीटें रिजर्व्ड कर दी हैं । इससे वे बच्चे होस्टल्स में आसानी से रह सकेंगे । इससे समाज में समरसता, भाइचारा और समानता आएगी। यह एक बहुत ही अच्छी बात है । 9वीं और 10वीं कक्षा के एस.सी. कैटेगरी के बच्चों को सरकार मुफ्त में साइकिल प्रदान करेगी । उपाध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से एस.सी. कैटेगरी के लोगों को 100–100 गज के प्लॉट देने का प्रावधान है। आज से 10 साल पहले एस.सी. कैटेगरी के 46 परसेंट लोगों को प्लॉट अलॉट किये गये थे । मैंने इस विषय पर बहुत से फैसले भी करवाये हैं । उस समय की सरकार ने कहा कि हमने एस.सी. कैटेगरी को 100–100 गज के प्लॉट अलॉट किये हैं । मेरा कहना है कि वितरित किये गए उन प्लॉट्स में से 12 परसैंट प्लॉट्स पर दबंग लोगों ने कब्जे कर लिये हैं । रजिस्ट्री बेशक एस.सी. के नाम पर है लेकिन कब्जा दबंगों ने किया हुआ है । दबंगों द्वारा किए गए कब्जों को खत्म करने के लिए इस सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास बनाने की सुविधा दी गई । सरकार ने कहा है कि एस.सी. कैटेगरी के लोगों को 100–100 गज के प्लॉट के साथ–साथ प्रधानमंत्री आवास योजना भी लागू की जाए । मेरा कहना है कि यह बहुत सराहनीय बात है क्योंकि इससे दबंग लोग उन लोगों से दोबारा कब्जा नहीं ले सकेंगे । कई बार लोगों की शिकायत आती थी कि एस.सी. कैटेगरी के लोगों के लिए 100–100 गज के प्लॉट्स दिए गए थे लेकिन हमें कोई प्लॉट नहीं मिला लेकिन अब 100 गज के प्लॉट के साथ–साथ प्रधानमंत्री आवासीय योजना को लागू किया गया है । इसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि स्पैशल कम्पोनेंट प्लान सबके लिए रामबाण होता है। एस.सी. कैटेगरी के लिए स्पैशल कम्पोनैंट प्लान का एक बजट आता है। यह बजट जिन लोगों की आबादी 33 प्रतिशत है, उनके लिए रखा जाता है और वे 33 प्रतिशत लोग एस.सी. कैटेगरी से संबंध रखते हैं। इन 33 प्रतिशत लोगों की जो बस्ती हैं, यह बजट उन लोगों की बस्तियों की सफाई के लिए, उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिए, उनकी तकनीकी शिक्षा के लिए,

उनकी सुरक्षा के लिए और उनके रोजगार का प्रबन्ध करने के लिए संबंधित बजट का प्रावधान किया जाता है। यह बजट उन्हीं लोगों की 33 प्रतिशत आबादी के लिए दिया जाता है और सरकार ने भी उसको स्वीकार किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह भी आग्रह है कि एस.सी. कैटेगरी के स्पैशल कम्पोनैंट प्लान के बजट का पूरा पैसा खर्च किया जाए। प्रायः देखने में यह आता है कि सरकार तो एस.सी. कैटेगरी के लिए स्पैशल कम्पोनैंट प्लान का बजट तो दे देती है, लेकिन नीचे की मशीनरी यानी अधिकारीगण उन पैसों को नहरों पर पुल और नहरों के बंध बनाने पर लगा देते हैं। मैंने सरकार के समक्ष कई बार इस बात को उठाया भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में एक मीटिंग के दौरान विभागीय अधिकारियों से पूछा कि आपने एस.सी. कैटेगरी के स्पैशल कम्पोनैंट प्लान की संबंधित स्कीम्ज का 1 करोड़ 10 लाख रुपये कहां पर खर्च किये हैं ? इस बात पर अधिकारियों ने जवाब दिया कि उन्होंने संबंधित बजट को पुल बनाने में लगा दिया क्योंकि पुल पर से भी एस.सी. कैटेगरी के लोग गुजरते हैं। यह संबंधित बजट को खुर्द–बुर्द करने का एक बहाना है। यह चिंतनीय विषय है कि एस.सी. स्पैशल कम्पोनैंट प्लान का बजट दूसरी चीजों में खर्च किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को पहले भी इस बारे में अवगत करवाया था कि स्पैशल कम्पोनैंट प्लान स्कीम्ज के बजट का पैसा कभी भी पूरा नहीं लगता। इस स्पैशल कम्पोनैंट प्लान के बजट के पैसों को दूसरी चीजों में नहीं लगाया जाना चाहिए। यानी एस.सी. कैटेगरी के स्पैशल कम्पोनैंट प्लान के बजट का पैसा जिस मद के लिए दिया गया है, उसी मद पर खर्च किया जाए। इसके बाद एस.सी. कैटेगरी के लोगों को लोन्ज व ग्रान्ट्स देने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। यह पैसा खर्च किये जाने के बाद उनकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यह संबंधित स्कीम्ज के बजट का पूरा पैसा खर्च किये जाने के बाद किसी के आगे हाथ पसारने और विनती करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगर संबंधित बजट का पैसा दूसरे महकमों में खर्च करने के लिए डायवर्ट करेंगे तो उनकी स्थिति वैसी ही रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि आप लोगों के समय में दलितों पर कोई भी अत्याचार नहीं हुआ। इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है कि आपके समय में दलितों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। पहले की सरकार के समय में हरियाणा प्रदेश में मिर्चपुर कांड के अन्दर एक ही पल में 19 घरों को जला दिया गया। इस दौरान एक परिवार ऐसा भी था जिसमें एक घर

में एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी जवान अपाहिज बेटी रहती थी। वह घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी, परन्तु जब उसको उसका पिता जी घर में लगी आग से बाहर निकालने के लिए गया तो उस दौरान उस लड़की का पिता जी भी आग में जल गया। इस प्रकार आग में जलने के कारण उन दोनों की मौत हो गयी। वहां पर सभी परिवारों के लोग गांव छोड़कर चले गये और आज तक उस गांव में नहीं लौटे हैं। कोई एकाध परिवार के लोग संबंधित गांव में आते हैं, परन्तु फिर वापिस चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है और सरकार भी बधाई की पात्र है कि दलितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ और न ही कोई दुर्व्यवहार हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इससे दूसरी पार्टी के लोगों को भी सबक सीखना चाहिए कि लोगों की हमदर्दी कैसे प्राप्त की जाती है ? कैसे राज किया जाता है ? उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक घटना का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा कि दिल्ली में संत गुरू रविदास का मन्दिर सरकार ने नहीं गिरवाया बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर ध्वस्त करवा दिया। इस बात पर बड़ा आडम्बर हुआ। यह घटना घटने के बाद समुदाय के लोगों में बहुत रोष पैदा हुआ क्योंकि उनकी भावनाओं को इससे ठेस पहुंची, आध्यात्मिकता पर आंच भी आयी, परन्तु धन्य हो केन्द्र सरकार जिसने दिल्ली के उसी स्थान पर दोगुनी जमीन देकर वहीं पर दोबारा मन्दिर बनवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत जी ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जिसमें कुरूक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर उसी तर्ज पर एक वैसा ही विश्वस्तरीय मन्दिर बनाने की घोषणा की है। यह फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया था कि 5 एकड़ जमीन कुरूक्षेत्र में मंदिर बनाने के लिए देंगे और वहां पर एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है ? दलितों और गरीबों के हित की सरकार और क्या हो सकती है ? इस मंदिर में महर्षि भगवान वाल्मीकी जी, कबीर साहब जी और संत गुरू रविदास जी की मूर्तियां लगायी जाएंगी। गुरू रविदास जी के 40 शब्द गुरू ग्रन्थ साहिब में दर्ज हैं। उनका मान– सम्मान किया जाता है। इससे बढ़कर सरकार का गरीबों के प्रति क्या उद्देश्य होगा कि सरकार उनका मान– सम्मान करती है। यह ऋषि और मुनियों का देश है और इसी आधार पर हम उनका पूरा मान–सम्मान करते हैं। हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं और इसी आधार पर हम उनकी पूजा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था आज उसके परिणाम सकारात्मक साबित हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे भारत में खुले में शौच जाना बीते जमाने की बात हो गई है। इस योजना के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि देश के प्रत्येक गांवों में चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण था। मैं समझता हूं कि यह प्रदूषण अब जाकर खत्म हुआ है क्योंकि घर–घर में शौचालय बन गए हैं, जिससे नए युग की शुरूआत हुई है। अध्यक्ष महोदय, पहले लोग कागज के टुकड़ों को सड़क पर फाड़ कर फेंक देते थे लेकिन आज लोगों की सोच बदल गई है इसलिए आज वही लोग कागज के टुकड़ों को कूड़ेदान में डालने के लिए कूड़ादान ढूंढते फिरते हैं ताकि वे कागज के टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल सकें। अगर उन्हें कूड़ादान नहीं मिलता है तो वे अपनी जेब में रख लेते हैं, इससे बड़ा स्वच्छ भारत और क्या हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आज लोगों में एक आदत बन गई है कि हर नागरिक को इस बात का पता लग गया है कि यहीं स्वच्छता का नारा है और भारत देश को स्वच्छ रखना मेरा धर्म है। मैं समझता हूं कि इसमें हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कुरूक्षेत्र धर्मनगरी में बुद्ध स्तूप को पर्यटन आकर्षण स्थल के रूप में विकसित कर रही है। इस बुद्ध स्तूप को देखने के लिए देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इसे देखने के लिए आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल, श्रीलंका और श्रीनगर से भी लोग बड़ी–बड़ी गाड़ियां भर–भर कर इस बुद्ध स्तूप को देखने के लिए आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने यह बहुत अच्छा केन्द्र बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मल्टी आर्ट कल्चरल सैंटर अब कृति भवन के तौर पर पहचाना जाएगा। कला परिषद का मुख्यालय पहले चण्डीगढ़ में हुआ करता था लेकिन अब यह मुख्यालय कुरूक्षेत्र में शिफ्ट किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कुरूक्षेत्र में शिफ्ट करके हरियाणा के कद को बढ़ाने का काम किया है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत आभारी हूं और इस बात के लिए उनकी जितनी सराहना की जाये, उतनी कम है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विधान सभा गुहला चीका के बारे में बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बॉर्डर के ऊपर है और इसके अंदर एक घग्गर नदी भी आती है और इसके बीच से निकलती है । पंजाब की सभी फैक्टरियों का कैमिकल मिला हुआ विषैला

पानी इस घग्गर नदी में डाल दिया जाता है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस समय सदन में उपस्थित उपाध्यक्ष महोदय (श्री रणबीर गंगवा) भी मेरे साथ लोक सभा के सदस्य हुआ करते थे, इन्होंने भी मेरा साथ दिया था। हमने उस वक्त भी पार्लियामैंट में यह बात उठाई थी कि पंजाब की सभी फैक्टरियों का कैमिकल मिला हुआ पानी घग्गर नदी में डाला जाता है। जिनकी वजह से इतना प्रदूषण फैल गया कि लोगों को कैंसर, काला पीलिया और गुर्दे जैसी भयानक बीमारियाँ लग गई हैं और हमारे प्रदेश में इस प्रकार के रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मेन कारण यही है पानी का टी.डी.एस. 400 से भी ऊपर पहुंच गया है। यह पानी स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। मैं समझता हूं कि वह पानी पीने लायक तो क्या वह पानी हाथ धोने लायक भी नहीं है। इसी तरह से मेरे क्षेत्र से सरस्वती ड्रेन भी निकलती है, उसके अंदर भी जो हमारी गत्ता मिल है, उसका पानी भी डाल दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है लेकिन आज तक इस कमेटी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है और न ही इस पर किसी चीज की सूध ली है। मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि इस कमेटी का डिस्ट्रिक्ट लैवल का डी.सी. चैयरमैन भी होता है।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर जी, आपको बोलते हुए 20 मिनट से भी ज्यादा का समय हो गया है इसलिए आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री ई□वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जगबीर मलिक जी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है और मैं सदन में ठीक ही बोल रहा हूं इसलिए मुझे अपनी बात कहने दीजिए। हमारे गांव सीवन में सीवरेज सिस्टम का काम 80 प्रतिशत पूरा हो गया है लेकिन इस सीवरेज सिस्टम में 5 किलोमीटर में पाइप डालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 साल पहले घोषणा की थी लेकिन अभी तक 5 किलोमीटर की पाइप नहीं डाली गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इस गांव की 17 हजार के आसपास आबादी है। इसी तरह से बाघल गांव की 12 हजार के करीब आबादी है और इस गांव में भी सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था ठीक करवाने का काम किया जाये। जब मैं वर्ष 1977 में विधायक था तो वर्ष 1982 में हमारे यहां पर बस अड्डा बनाया था परन्तु आज तक भी उस बस अड्डे में कोई बस नहीं गई है क्योंकि वहां का माहौल आने जाने का नहीं है। उस बस अड्डे के लिए सड़क भी नहीं बनी हुई है क्योंकि यह बस अड्डा बहुत ज्यादा दूर बनाया गया है। श्री

मूलचंद शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, मैंने नये बस अड्डे के लिए माननीय मंत्री जी को भी लिखकर दिया हुआ है। हम विभाग को बस अड्डे के लिए 5 एकड़ सरकारी जमीन भी उपलब्ध करवा देंगे। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी को नया बस अड्डा बनवाने के लिए डी.सी. साहब ने भी लिखित में दिया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से परिवहन विभाग को बस अड्डा बनाने के लिए फ्री में जमीन मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि उसकी घोषणा की जाये और वहां पर नया बस अड्डा बनाया जाये। मेरे गुहला में कोई स्टेडियम भी नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी ने यह रेजोल्यूशन पाया है कि हम स्टेडियम के लिए 11 करोड़ देने के लिए तैयार हैं परन्तु स्टेडियम की मंजूरी नहीं मिली। किन कारणों से नहीं मिली सम्बंधित मंत्री जी अभी सदन में उपस्थित नहीं है। उन्होंने यह कहा था कि मैं देखकर बताउंगा। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गुहला में कैनाल बेस्ड वॉटर सप्लाई सिस्टम नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गुहला में कैनाल बेस्ड वॉटर सप्लाई स्कीम लागू की जाये। मेरे विधान सभ हल्के में एक कैनाल बेस्ड वॉटर सप्लाई स्कीम नहीं है जबकि कैथल में 12 कैनाल बेस्ड जल आपूर्ति स्कीम्ज़ चल रही हैं, कलायत में 33 कैनाल बेस्ड जल आपूर्ति स्कीम्ज़ चल रही हैं और पुण्डरी में चार कैनाल बेस्ड जल आपूर्ति स्कीम्ज़ चल रही हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक हैल्थ विभाग को ये निर्देश दिये जायें कि गुहला विधान सभा क्षेत्र में कैनाल बेस्ड वॉटर सप्लाई सिस्टम लागू हो जिसके लिए मारकण्डा डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी ले। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि मेरा गुहला विधान सभा क्षेत्र डॉर्क जोन एरिया है इस कारण से भी वहां पर कैनाल बेस्ड वॉटर सप्लाई सिस्टम लागू किया जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं कृषि और किसान कल्याण के विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगा। गठबन्धन सरकार ने इस बजट में कृषि के क्षेत्र के लिये अच्छे बजट का प्रावधान किया है। साथ ही गठबन्धन सरकार का यह कदम भी प्रशंसनीय है कि प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिये कुछ नई योजनायें भी हमारी सरकार द्वारा बनायी गई हैं। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कृत–संकल्पता किसानों के प्रति हमारी सरकार की अच्छी सोच को दर्शाती है। मेरी फसल–मेरा ब्यौरा स्कीम से किसानों को लाभ होने की पूरी उम्मीद है।

ऐसे ही पिंजौर में सेब मण्डी, सोनीपत में मसाला मण्डी व गुरूग्राम में फूल मंडियों की स्थापना सरकार का सराहनीय कार्य है। इसके लिए हम सरकार को हार्दिक बधाई देते हैं। यह हमारी सरकार की प्रोग्रैसिव सोच को दर्शाता है। सरकार के इन कदमों से प्रदेश के किसानों की आय में बेतहाशा वृद्धि होने की पूरी–पूरी उम्मीद है। डिप्टी स्पीकर सर, इस प्रकार की योजनाओं को सफल बनाना गठबन्धन सरकार के सामने एक चुनौती होगी। डिप्टी स्पीकर सर, जहां स्कीम बनाना आवश्यक है वहीं उसको अमलीजामा पहनाकर किसानों को वास्तविक लाभ पहुंचाना भी बेहद जरूरी है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब हमारी सरकार का प्रशासन पर बहुत ही सख्त नियंत्रण हो। डिप्टी स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार की बहुत सी स्कीमों के बारे में किसानों को सही जानकारी भी नहीं होती। बहुत सी स्कीमों में आवश्यक कागजी कार्यवाही व दूसरी टैक्नीकल परेशानियों की वजह से किसान उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। वास्तव में किसानों को पूरी जानकारी ही नहीं होती है कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन सी स्कीम्ज चलाई गई हैं? सरकार की किसानों से सम्बंधित सभी स्कीम्ज की किसानों पूरी जानकारी प्राप्त हो सके इसके लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न सेमिनारों का भी समय–समय पर आयोजन किया जाये। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि कृषि सम्बंधी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने की कोशिश की जाये जिससे कि किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिल सके। डिप्टी स्पीकर सर, किसानों की फसलों को जोखिम से बचाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व अन्य ऐसी योजनाओं को इस प्रकार सरल बनाने के प्रयास हों, जिससे कोई भी किसान किसी भी हानि के लिये, चाहे वह थोड़ी मात्रा में हो या फिर अधिक मात्रा में हो, किसान उससे वंचित न रह सके। सरकार के स्तर पर कुछ ऐसे इंतजाम भी किये जायें कि बीमा कराने वाले किसान के नुक्सान की तुरंत जांच हो जाये और उसे भुगतान के लिए तरह–तरह की खानापूर्तियों का सामना न करना पड़े। डिप्टी स्पीकर सर, आज की तारीख में पूरे हरियाणा प्रदेश के सामने पानी की एक बड़ी भयानक समस्या है। अतः भूजल प्रबंधन व संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भावान्तर भरपाई योजना को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने की आवश्कता है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कृषि भूमि की उपयोगिता की पहचान की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार किसानों की उपज की बिक्री व सही मूल्य

का प्रबन्ध करने की ओर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। डिप्टी स्पीकर सर, किसानों को निःशुल्क ट्यूबवैल के कनैक्शंज देना सरकार का एक सराहनीय कदम है। इससे किसानों को अच्छा लाभ होगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि प्रदेश के अंदर जो डॉर्क जोन हैं उनमें भी ट्यूबवैल कनैक्शंज देने पर जो रोक लगाई हुई है उसको भी तुरंत खोला जाये। इससे किसानों को अच्छा लाभ होगा। इसके साथ ही साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि किसानों को बिजली, पानी, खाद, कीटनाशक दवायें, कृषि उपकरण जैसी वस्तुएं समय पर मिल सकें। सर, बागवानी, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन इत्यादि भी किसानों से सम्बंधित हैं। सरकार को इन सभी मदों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देना एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। जिला अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला में हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। बागवानी के क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयत्न सरकार को तेजी के साथ करने की आवश्यकता है। प्रदेश की भूमि बागवानी के लिये उपयोगी है परन्तु इसे प्रोत्साहित करने, किसानों को जाग्रत करने, उनको उचित टेक्निकल, कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने की तथा यथासंभव आर्थिक सहायता व उनके उत्पादों के मार्केटिंग की उचित व्यवस्था करने की जरूरत है। पशुपालन व डेयरी दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन के साथ किसान की आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है। पशुधन को किसी जमाने में वित्त का हिस्सा जाना जाता था, हालांकि पशुपालन व डेयरी का आज के समय में भी किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा भारी योगदान है इसलिए सरकार को इसको अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही किसानों को इसकी योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। पशुपालन व डेयरी में एक और मुख्य समस्या है और वह है पशुधन को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबंध हो तो किसान अपने पशुधन को सुरक्षित जानकर इसकी तरफ उत्साहित होंगे और पशुपालन व डेयरी से उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। इसी तरह से सरकार की मत्स्य पालन की योजना लाभकारी सिद्ध हो सकेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों, जींद, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पलवल, नूंह, हिसार, फतेहाबाद व फरीदाबाद में इसको बढ़ावा देना सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गठबंधन सरकार का प्रतियोगी परीक्षाओं को युवाओं के गृह जिले में ही कराने का फैसला

प्रशंसनीय है। इससे जहां युवा वर्ग को आर्थिक लाभ होगा, वहीं वह अप्रत्याशित परेशानियों से भी बच सकेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि कैंसर की बीमारी का इलाज, मोबाइल डिसपैंस्रीज से चिकित्सा उपलब्ध कराना भी सराहनीय कार्य है। जे.जे.पी. के घोषणा पत्र में लोगों से वायदा किया गया था कि गृह जिले में परीक्षा आयोजित करवाएंगे, वह भी पूरा हुआ है। इसी तरह से मोबाइल डिस्पेंसरीज की व्यवस्था करना व एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन, कैथ लैब और डायलिसिज की व कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के ईलाज का प्रावधान सभी जिला अस्पतालों में किया जा रहा है जो कि एक सराहनीय कदम है। यह हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में किया वादा पूरा किया गया है इसलिए हम गठबंधन सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से गांव वालों की एक विशेष मांग थी कि गांवों में शराब के ठेके बंद होने चाहिएं। सरकार का गांवों में शराब के ठेके बंद करना एक सामाजिक उत्थान का उदाहरण है। यह सामाजिक सुधार की तरफ समयोचित कदम है। किसानों को निशुल्क ट्यूबवैल कनैक्शन देने का गठबंधन सरकार का निर्णय सराहनीय है तथा यह भी ज.ज.पा. के घोषणा पत्र में लोगों से वायदा किया गया था, जो आज पूरा हुआ है इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं क्योंकि इससे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

डॉ. अभय सिंह यादव(नांगल चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहता था कि मुझे बोलने के लिए टाईम उस समय दिया जाए जब सभी हाउस में बैठे हों, विशेष तौर पर हमारे विपक्ष के साथी। मुझे कुछ काम की बातें बोलनी थी। हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आंकड़ों को मैनीपुलेट करके पेश किया है, मैं उनको जवाब देना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि वे कहीं न कहीं सुन रहे होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जब 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा अलग प्रदेश बना उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत थी। उस समय जब हमारा राज्य पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा एक कृषि आधारित स्टेट था। हमारी इकॉनोमी के जो मुख्य तीन कंट्रीब्यूटर होते हैं उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसिज थी उनका योगदान 60.7 प्रतिशत था। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज का योगदान 17.6 प्रतिशत तथा सर्विस सैक्टर का योगदान 21.7 प्रतिशत था। यह वित्त

वर्ष 1969–70 के आंकड़े हैं। उसके बाद स्टेट ने उन्नति की। विभिन्न सरकारें आई और हर सरकार ने अपने–अपने लैवल पर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की कोशिश की जिसमें रोड्ज बने, बिजली आई और फरीदाबाद, बहादुरगढ़, कुंडली, मानेसर, बावल, हिसार, अम्बाला आदि बड़े–बड़े शहरों में इंडस्ट्रीज आई। वहां इंडस्ट्री आने से जो वर्ष 2019–2020 के फिग्गर्ज हैं वह बिल्कुल उलट गये हैं। वर्ष 1969–70 में एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा कम्पोनैंट था वह सबसे नीचे चला गया। आज की तारीख में एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन 16.6 प्रतिशत है। इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन 17.06 प्रतिशत से बढ़कर 32.08 प्रतिशत हो गया है और सर्विस सैक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 50.06 प्रतिशत हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इरीगेशन और एग्रीकल्चर में कोई विकास नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर में हरित क्रांति आने से अनाज की पैदावार बढ़ी है। पहले किसी जमाने में हमारा स्टेट फूड डैफिशिएंट स्टेट था जिसमें हम खाद्यान बाहर से मंगवाते थे लेकिन आज हमारा स्टेट फूड सरप्लस स्टेट हो गया है और अब हम हमारे खाद्यान बाहर भेजने की अवस्था में आ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 में हमारे प्रदेश की करंट प्राईसिस में पर कैपिटा इंकम सिर्फ 608 रुपये थी। आज वर्ष 2019–2020 में यह पर कैपिटा इन्कम 2,64,207 रुपये हो गई है। इसके साथ–साथ कॉन्स्टैंट प्राईस अर्थात वर्ष 2011–12 की जो कीमतें हैं उसके ऊपर भी हमारी पर कैपिटा इंकम 1,80,026 रुपये है । जो ऑल इण्डिया की पर कैपिटा इंकम है उससे हमारा प्रदेश बहुत ऊपर है क्योंकि करंट प्राईसिस पर जहां हमारी पर कैपिटा इंकम 2,64,207 रुपये है वहां ऑल इण्डिया की 1,35,050 रुपये पर कैपिटा इंकम है और कोन्स्टैंट प्राईस पर जहां हमारी 1,80,026 रुपये पर कैपिटा इंकम है वहां ऑल इण्डिया की 96,563 रुपये पर कैपिटा इंकम है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आश्य यह है कि हमारा स्टेट लगातार उन्नति व प्रगति के पथ पर आगे चलता रहा है। विपक्ष का काम है आलोचना करना उसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है। आलोचना करना उनका दायित्व भी है और उनके अपने हित में उनकी सोच भी यही रहती है। आज हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के पास बहुत अच्छे–अच्छे इकोनोमिक कारक हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारी अर्थ व्यवस्था को सबसे ज्यादा पुश करता है वह हमारी लोकेशन है। आज राष्ट्रीय राजधानी मार्ग व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीन तरफ हरियाणा लगा हुआ है जिसमें बहुत बड़ी–बड़ी मार्किट्स अवेलेबल हैं। उसी वजह से शहरों का डिवैल्पमैंट हुआ है। ज्यों–ज्यों सॉफ्टवेयर बढ़ा है उससे

आज हमारा गुरूग्राम साईबर सिटी के नाम से जाना जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सर्विस सैक्टर में जो हमें वृद्धि मिली है उसमें बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन सर्विस सैक्टर का है। इसके साथ ही हमारी जो मानव संसाधन है। हमारे जो बच्चे पढ़ लिखकर विदेश गये हैं उन्होंने यूरोप और अमेरिका की मार्किट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा धूम मचा रखी है। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर व सॉफ्टवेयर एक्सपर्टस की कहीं धूम है तो वह चाईना और इण्डिया दोनों की है। हमारे जो नोजवान बच्चे वहां जा रहे हैं वह फौरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा अमाऊंट यहां लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे विपक्ष के साथी जो कम्पेरिजन कर रहे थे कि हमारे समय में ये था, हमारे समय में ये था। उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ व्यवस्था कोई स्थिर चीज नहीं है और अर्थ व्यवस्था को ग्रीन हाऊस में भी पैदा नहीं किया जा सकता है। अर्थ व्यवस्था हालातों की देन है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्ज हैं स्थानीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय ऐसे बहुत बड़े फैक्टर्ज हैं जो अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आज चाईना में कोरोना वायरस का प्रकोप है तो उससे हिन्दुस्तान का संसैक्स डाऊन हो गया। हिन्दुस्तान की शेयर मार्किट डाउन हो गई। अपनी बात छोड़िए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, कारण या कारक भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यह सर्वविदित है कि आज का समय अर्थव्यवस्था के लिए स्लो डाउन अर्थात मंदी का समय है। यह सिर्फ हरियाणा या हिंदुस्तान के लिए मंदी की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया और यहां तक की अमेरिका व यूरोप जैसे देशों की मार्किट भी आज बैठी हुई है तो इस स्लो डाउन की अर्थव्यवस्था के इस समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह बजट पेश किया है, इसमें बहुत से उत्साहजनक कारक मौजूद हैं और इकोनोमिक दृष्टि से तथा हर पहलू से इस बजट के सभी फैक्टर्ज हमारे फेवर में ही हैं। अभी हमारे कुछ साथी जिनमें मैं डॉ. रघुवीर सिंह कादियान व श्री भारत भूषण बतरा का नाम लेना चाहूंगा, बड़े जोर–शोर से फिस्कल डेफिसिट तथा लोन के विषय पर बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीजें एक सैट प्रोसीजर के हिसाब से ही चलती हैं। इसके तहत एक संवैधानिक प्रोसीजर भी होता है। संविधान के आर्टिकल 293 में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कोई भी प्रदेश सरकार अगर प्रदेश से बाहर से लोन लेती है तो उसको पहले भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और पूर्वनिर्धारित सीमाओं के बाहर जाकर लोन नहीं लिया सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा लोन लेने के संदर्भ में भारत सरकार ने दो शर्तें नियत की हैं। पहली शर्त यह है कि कोई भी प्रदेश

सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जी.एस.डी.पी. से 25 परसैंट से ज्यादा लोन नहीं ले सकेगी और अगर ऐसा करना चाहेगी तो उसके लिए उसे स्पेसिफिकली भारत सरकार की स्वीकृति लेनी पड़गी। इसके अतिरिक्त दूसरी शर्त यह भी है कि जो प्रदेश का फिस्कल डैफिसिट अर्थात राजस्व घाटा है वह प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जी.एस.डी.पी. से 3 परसैंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दोनों ही स्थितियों में हम विद्‌िन लिमिट्‌स हैं और जिस तरह की चिंता हमारे विपक्ष के साथी कर रहे थे, इस तरह की अवस्था में उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विकासशील अर्थव्यवस्था और ऋण का चोली दामन का साथ होता है। अध्यक्ष महोदय, समय इतनी तेजी के साथ बदल रहा है कि हमें हर स्थिति में समय के साथ चलना होगा। अगर हम विपक्ष के साथियों की यह बात मान भी लें कि ऋण लेना ही नहीं चाहिए, के परिपेक्ष्य में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि मान लो कहीं पर इंफ्रॉस्ट्रक्चर की कमी है और कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट में मान लो स्टेट के रिसोर्सिज में हम उतना पैसा स्पेयर नहीं कर सकते हैं तो हम यह तो इंतजार नहीं कर सकते कि जब स्टेट के रिसोर्सिज हमें अलाउ करेंगे तो तब हम इस प्रोजेक्ट को बना लेंगे तो ऐसी सोच के साथ हम प्रदेश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिले में लिफ्‌ट इरीगेशन की मशीनरी काफी पुरानी पड़ चुकी थी और यही नहीं पिछले कई सालों से खेती के पानी की बात तो दूर रही पीने के पानी तक की समस्या आकर खड़ी हो गई थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सारी स्थिति को प्रकट किया और इसके बाद हमारे यहां 143 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बना और नाबार्ड ने इसको फाइनैंस किया और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया और इस प्रोजेक्ट का इलाके के विकास में इतना ज्यादा फायदा हुआ कि हमारे यहां आज क्यारी–क्यारी में खेत–खेत में बहुत तगड़ी फसल खड़ी हुई है। अगर हम यह सोचते रहते कि हमें ऋण नहीं लेना तो हम उसी स्थिति में खड़े रहते और हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, फिस्कल मैनेजमैंट के तहत सबसे अहम बात यह होती है कि ऋण जिस मकसद के लिए लिया होता है उस ऋण को उसी मकसद में प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी वित्तीय संस्था ऐसे ही ऋण नहीं देती कि सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है और सरकार

वित्तीय संस्था के पास जायेगी और वह वित्तीय संस्था ऋण दे देगी। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संस्थायें एक पर्टिकुलर प्रौजेक्ट के लिए ऋण देती है और यही नहीं जब सरकार ऋण के लिए किसी वित्तीय संस्था के पास जाती है तो सरकार को उस प्रौजैक्ट की अन्य सभी औपचारिकताएं व डी.पी.आर. तक को बनाकर उस वित्तीय संस्था को देना होता है। इसके बाद जो वित्तीय संस्थाओं के टैक्निकल लोग होते हैं वे सभी औपचारिकताओं को एग्जामिन करते हैं और सब बातों को देखकर ही लोन स्वीकृत किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के लोन पर 'श्वेत पत्र' जारी करने की बात कही जा रही थी। मैं यह कहता हूँ कि सरकार पर जो लोन है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है अर्थात् कोई गुप्त चीज नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि सिर्फ 20 रुपये की आर0टी0आई0 की एप्लीकेशन लगाकर सारी की सारी डिटेल सरकार से मांगी जा सकती है कि किस–किस काम के लिए कितना–कितना पैसा लगा है अर्थात् सरकार ने कितना किस परपज के लिए लोन लिया है। यदि मैं विपक्ष में होता तो मैं भी इस संबंध में यही काम करता और सूचना मांगता कि कितना–कितना पैसा किस–किस काम के लिए सरकार ने लगाया है। यह तो पब्लिक डॉक्यूमैंट है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पैसे हरियाणा के प्राजैक्ट पर ही लगे हैं और कई प्रोजैक्ट्स कम्पलीट भी हुए हैं। ऐसी कोई नहीं बात नहीं है। जब से हरियाणा बना है तब से स्टेट की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती रहती है। यदि ये बातें राजनीतिक करने के लिए कही जाती हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। वर्ष 2004–05 में हरियाणा पर 17353 करोड़ रुपये कर्ज था और उस समय स्टेट की टोटल जी0एस0डी0पी0 95795 लाख करोड़ रुपये थी। वर्ष 2014–15 में कांग्रेस सरकार के आखिरी साल में टोटल लोन 70931 करोड़ रुपये का था और बाद में भाजपा सरकार हरियाणा में आ गई थी। इस प्रकार से 17 हजार करोड़ रुपये से लेकर 70 हजार करोड़ रुपये तक हरियाणा राज्य पर लोन हो गया है। उस समय टोटल जी0एस0डी0पी0 437145 लाख करोड़ रुपये थी। वर्ष 2019–20 में बिना 'उदय' के 150882 करोड़ रुपये लोन हरियाणा पर हो गया और उस समय टोटल जी0एस0डी0पी0 831610 लाख करोड़ रुपये थी। उपाध्यक्ष महोदय, लोन का साईज हमेशा अर्थव्यवस्था के साईज के साथ कॉरिलेट किया जाता है। जिस आदमी के पास 10 रुपये हैं तो वह 1 रुपये की मांग की कोशिश करेगा और जिस आदमी के पास 100 रुपये हैं तो वह 10 रुपये की मांग की कोशिश करेगा। प्रदेश सरकार द्वारा लोन लेने के संदर्भ

में भारत सरकार ने दो शर्तें तय की हुई है। पहली यह है कि कोई भी प्रदेश सरकार सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् जी0एस0डी0पी0 से 25 प्रतिशत से ज्यादा लोन नहीं ले सकेगी और अगर ऐसा करना चाहेगी तो उसके लिए उसे विशेष तौर पर भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि जो प्रदेश का फिस्कल डैफिसिट अर्थात् राजस्व घाटा है वह प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् जी0एस0डी0पी0 से 3 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए । दोनों के well within limits हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई अनियमतताएं नहीं है। मैं इस बात से सहमत भी हूँ। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, 25 प्रतिशत लोन की लिमिट पूरे देश के लिए है लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसके लिए नहीं है।

डॉ0 अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी नॉलेज है यह लिमिट हर स्टेट में स्पेसिफिक नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि हरियाणा पर लागू होगी और राजस्थान पर लागू नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में अखबार में पढ़ा है और यह बात ठीक है कि स्टेट यह प्लानिंग कर रही है कि आगे से टोटल जी0एस0डी0पी0 का 3 प्रतिशत से ज्यादा एक साल में स्टेट गवर्नमैंट लोन नहीं लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ लोन की पेमैंट के जो फाइनैंस मैनेजर हैं उनसे रिक्वैस्ट करूँगा कि कम से कम जो वार्षिक पेमैंट है वह इन्ट्रस्ट और प्रिंसिपल अमाउण्ट दोनों बराबर करके जमा करवाई जाये ताकि इन्ट्रस्ट की मात्रा घटती रहे। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अब अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा । मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ओलावृष्टि के बारे में कहा कि इसके लिए स्पैशल गिरदावरी के ऑर्डर कर दिए गए हैं । अभी सदन में माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं । मैं उनसे रिकवैस्ट करूंगा कि ज्यों ही गिरदावरी पूरी हो जाए त्यों ही किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दे दिया जाए ताकि उनको तुरंत रिलीफ मिल सके । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे वहां दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरीडोर बन रहा है । वह लगभग समापन की स्टेज पर है । उसी पर हमारे नारनौल के नजदीक ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है । वह मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब दिल्ली के बाद पहला हब है । वह पूरे उत्तर भारत की फ्रेट हैंडलिंग को कैटर करेगा । जहां तक

रोड नैटवर्क की बात है तो प्रदेश में लगभग सारे स्टेट को कनैक्ट करते हुए 3 एन. एच. बन रहे हैं । मेरा निवेदन है कि मध्य हरियाणा में अनेक रेल लाइन बिछाई जा रही हैं । इसी तरह अगर रोहतक से दादरी, वाया नारनौल, महेन्द्रगढ़ को एक रेल लाइन से जोड़ दें और उधर से नारनौल को बहराड़, अलवर, जोधपुर से जोड़ दें तो उसके 2 फायदे होंगे । इससे पूरे उत्तर भारत को पूरी दिल्ली को बाइपास करके फ्रेट के लिए बहुत बढ़िया कॉरीडोर मिल जाएगा । इसके साथ–साथ यह फ्रेट कॉरीडोर राजस्थान के अलवर, भरतपुर से भी जुड़ जाएगा । यह पूरे नॉर्थ इण्डिया के लिए फ्रेट हैंडलिंग का मेजर कंड्यूड होगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखित में मांग पत्र सौपूंगा । अतः इसके लिए गम्भीरता से विचार करके भारत सरकार के साथ टेकअप किया जाए । यह फ्रेट के लिए बहुत बढ़िया कॉरीडोर बन जाएगा और उत्तर भारत को मुम्बई से सीधा जोड़ देगा । इसके साथ ही नारनौल में राजस्थान से जो टूरिस्ट्स आते हैं उनके आने–जाने का नारनौल ही मुख्य रास्ता है । हमारे नारनौल में एक रैस्टोरैंट है । मेरी उसके मैनेजर से बात हुई थी । उसने मुझे बताया कि सीजन में वहां पर खाना खाकर रोज 400–500 वहां से टूरिस्ट्स गुजरते हैं । मेरा निवेदन है कि नारनौल में 16वीं शताब्दी के शेरशाह सूरी के टाइम के 5–6 स्मारक जलमहल, बालमुकुन्द का छत्ता, चोर गुम्बद आदि हैं । उन सभी का जीर्णोद्धार कर दिया जाए और उनको टूरिस्ट चेन बना दिया जाए । वहां पर एक ढ़ोसी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो महर्षि चवन की तपोभूमि रही है । वह भूमि महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है । कहते हैं कि महाभारत काल में पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय वहां पर ढ़ोसी के पहाड़ों में कुछ समय बिताया था । वह टूरिस्ट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है । इस समय सदन में माननीय पर्यटन मंत्री बैठे हुए हैं । मैं उनसे कहूंगा कि वे इस बारे में गम्भीरता से विचार करें । अंतिम बात यह है कि सरकार यमुना से फालतू पानी लाने के लिए हमीदा और दादूपुर के बीच में एक पैरलर चैनल बना रही है । आवर्द्धन नहर/ ऑग्युमैंटेशन चैनल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस पर काम चल रहा है । इसके अलावा दिल्ली चैनल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस पर भी काम चल रहा है । इस चेन को पूरी करने लिए जे.एल.एन. फीडर जो खुबड़ू–साल्हावास तक जाता है, का भी जीर्णोद्धार करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो पूरे चैनल की कैपेसिटी इनहांस हो जाएगी । इससे दक्षिण हरियाणा में पूरा पानी आने लग

जाएगा । इन शब्दों के साथ आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। जय हिन्द । नमस्ते ।

श्री प्रवीण डागर (हथीन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आदरणीय मनोहर सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों पर अपने विचार रखने का समय दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं । गत् दिनों 28.02.2020 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए जो बजट अनुमान प्रस्तुत हुआ वह सभी वर्गों खासकर किसान वर्ग के लिए बहुत ही खुशी भरा रहा जिसमें कृषि व किसान कल्याण गतिविधियों के लिए 681.48 करोड़ रुपये का परिव्यय सुनिश्चित किया गया है । जिसमें पिछले बजट की तुलना में 23.92 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। सहकारिता विभाग के लिए 1343.94 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है। जो किसान के लिए आगामी वर्ष में खुशियां भी लेकर आया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अंतिम व्यक्ति तक समय पर सुविधाएं मिले, इसके लिए भी अच्छे–खासे बजट का प्रावधान किया गया है। मैं आपके आध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सभी वर्गों के हितों को ध्यान रखते हुए, पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल लेकर आया है। हरियाणा सरकार द्वारा अगले वर्ष 18 नये राजकीय कॉलेज खोले जाएंगे। इनके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा हथीन क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरा हथीन हल्का मेवात जिले के साथ लगता है और पलवल जिले में आता है। मेरे हथीन हल्के के मंडकोला गांव में एक कॉलेज पिछली योजनाओं के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बना है। मेरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बहुत ही टेढी–मेढी है और इस तरह की भौगोलिक स्थिति लगभग 65 प्रतिशत एरिया में है। आदरणीय स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बजट में जिन 18 नये राजकीय कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। उनमें से एक राजकीय कॉलेज मेरे हथीन हल्के के मानपुर गांव में बनाया जाए ताकि वहां की बहन– बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर न जाना पड़े। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे हथीन के लिए पिछले 20–25 वर्षों से बाईपास बनाने की जो मांग चली रही थी, उसके लिए बजट में प्रावधान किया है। हथीन हल्के में ऐसे छोटे–छोटे रास्ते हैं जहां पर ट्रक व दूसरे बड़े साधन नहीं जा

सकते थे। यह बहुत बड़ी समस्या थी, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में पास की और बजट में इसका प्रावधान किया है। इसके लिए, मैं हथीन हल्के की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा हथीन हल्का ग्रामीण एरिया है और वहां पर किसानों की स्थिति दयनीय बनती जा रही है क्योंकि वहां पर सेम की समस्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सेम की समस्या का मामला उठाया था और मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए इरीगेशन विभाग को आदेश दिया कि जितने भी किसानों की जमीनों में सेम की समस्या है। उनकी सेम की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करवाया जाए। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के किसानों की जो 5,000–6,000 एकड़ जमीन सेम की समस्या से ग्रस्त है, उससे वहां के किसान हताश और परेशान हैं। इसलिए उस जमीन से सेम की समस्या का समाधान करने के लिए जो प्रोजैक्ट तैयार हुआ है, उस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए। पिछले सप्ताह मेरे हथीन क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति रैली को संबोधित किया था। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दबालू माइनर को ड्रेन में तबदील किया जाएगा। इसके लिए बजट में 2.50–3.00 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए ताकि वहां के किसानों को लाभ मिल सके। इस बारे में मेरे अलावा मेरे साथी विधायक माननीय चौधरी आफताब अहमद जी और श्री संजय सिंह जी, द्वारा कई वर्षों से संबंधित मांग उठायी जाती रही है। यह हथीन, सोहना और नूंह विधान सभा क्षेत्रों के साथ लगते 70 गांवों की बहुत बड़ी समस्या है। दबालू माईनर को ड्रेन में तब्दील करवा दें ताकि वहां के किसान अपनी खेती का कार्य फिर से शुरू कर सकें। वे आज अन्न के लिए परेशान हैं और भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। आदरणीय डिप्टी स्पीकर सर, आपके माध्यम से यह काम हो जाएगा तो हमारे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और उन सबके घर में दिये जलने लग जाएंगे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और कहना चाहूंगा किः–

नये बजट में मुख्य मंत्री जी ने सभी वर्गों का ख्याल किया,
हरियाणा की जनता का पूरा किया हरेक सवाल,
जन–जन में है लहर खुशी की, हरियाणा किया खुशहाल।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पूंडरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बजट पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया। जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया है। उस बजट में किसानों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। इस बजट में सबसे पहले किसानों की आय दुगुनी करने का विषय आया था कि किसान की आय दुगुनी की जाये क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है। किसान एक ऐसा वर्ग है, जिसकी जमीन घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने कृत–संकल्प लिया है कि किसान की फसल के रेट ज्यादा कैसे मिले और किसान की फसल किस प्रकार से ज्यादा हो? उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लागू की थी। आज से पहले मेरे किसान भाई जब बैंकों से लोन की लिमिट बनवाते थे तो बिना किसान के पूछे उनका बीमा कर दिया जाता था। इस प्रकार की योजना किसान के लिए नुकसानदायक साबित हुई और किसानों को टाईम पर कभी किसी कम्पनी ने बीमा देने का काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ एक अन्याय था लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट के अंदर एक ऐसा प्रावधान किया है कि अगर कोई किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है तो उसका बीमा कर दिया जायेगा और अगर कोई किसान बीमा नहीं करवाना चाहता तो उस किसान का बीमा नहीं किया जायगा। मैं समझता हूं कि बजट के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक अच्छी योजना की शुरूआत की है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। जब सभी माननीय सदस्य प्री बजट पर चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी मेरे बहुत से साथी विधायकों ने एक मांग की थी कि इस योजना को किसान पर जबरदस्ती न थोपा जाये। प्रदेश

सरकार ने इस बजट के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान किया है। पहले जब किसान राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेते थे तो किसानों को ब्याज देना पड़ता था। हमारी सरकार ने इस बजट में किसान के लिए 3 लाख रुपये तक का प्रावधान किया है कि यह पूर्णतया ब्याज रहित है इससे प्रदेश के किसानों की हालत सुधरेगी और उनको फायदा भी होगा। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सदन में आभार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली के रेट की बात है इस बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया गया है कि जो गरीब किसान भाई हैं उनको बिजली विभाग की तरफ से 7.50 रुपये प्रति यूनिट की बजाय 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जायेगी। मैं समझता हूं कि यह गरीब किसान भाइयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक अच्छी योजना देना का काम किया है और यह हमारी सरकार के लिए एक सराहनीय कदम है। इसी प्रकार से अगर किसान कोई रोटावेटर, कंबाइन हारवैस्टर खरीदता है तो पहले इस पर सब्सिडी कम थी, इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसान को कम रेट पर सब्सिडी देने का काम करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे किसान भाई जो बाग लगाते हैं जैसे अमरूद का बाग, किन्नू का बाग और आम का बाग आदि के लिए पहले किसान भाईयों को 16,000 रुपये की सब्सिडी मिलती थी लेकिन अब वर्तमान सरकार ने 20,000 रुपये सब्सिडी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया है जोकि मैं समझता हूं कि हमारे किसानों भाईयों के लिए राहत भरा कदम साबित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी मांग जो हम सभी विधायक साथी करते थे और हम चर्चा भी करते हैं कि आज सड़कों के ऊपर और किसानों के खेतों में बड़ी भारी संख्या में आवारा पशु घूमते हैं। इनसे जहां सड़कों पर आये दिन भयंकर एक्सीडैंट्स होते रहते हैं वहीं इनकी वजह से किसानों की सभी फसलों का बहुत भारी नुक्सान होता है। प्रदेश की इस समस्या को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौजूदा बजट के अंदर 30 करोड़ रूपये की बजाय 50 करोड़ रूपये का प्रावधान गोशालाओं के लिए किया ताकि प्रदेश में घूम रहे सभी आवारा पशुओं को उनमें रखा जा सके। जिससे आवारा पशुओं के कारण होने वाले एक्सीडैंट्स में भी कमी आयेगी और किसानों की फसलों का भी बचाव होगा। दूसरी बात मैं को–ऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कहना चाहता हूं। लैण्ड मॉर्टगेज और को–ऑपरेटिव बैंक्स में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावों से

पहले एक योजना लागू की थी जो किसान एकमुश्त किश्त देगा उसके पहले के पैनल इंट्रस्ट को माफ करने का काम सरकार द्वारा किया जायेगा। सरकार की इस योजना से किसानों का काफी लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान बजट के अंदर एक बार पुनः उस स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। इससे हमारे प्रदेश के गरीब किसानों को जो कर्ज में डूबा हुआ है उसको कर्ज से मुक्त होने में सहूलियत मिलेगी। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री की किसान और मजदूर के हित के प्रति दूरगामी सोच को दर्शाता है। डिप्टी स्पीकर सर, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा का सुधार हो और हम सभी विधायकों ने इस सम्बन्ध में अपने सुझाव भी दिए थे कि स्कूल एक ऐसे मंदिर हैं जहां से पढ़ लिखकर हमें यहां पर इस सदन में आने का मौका मिला है। जो हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा और भी बहुत ज्यादा अच्छी हो इसके लिए हमारी सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। हमारी सरकार द्वारा बच्चों के लिए स्कूलों में बैठने के अच्छे स्थानों की व्यवस्था की जाये यह मेरी एक मांग है। उनको स्कूल्ज में अच्छी–अच्छी सुविधायें मिलें। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा लिया है कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसके अंदर चारदीवारी न हो, जिस तक जाने के लिए पक्का रास्ता न हो और जिसके अंदर पीने के पानी के लिए आर.ओ. की सुविधा न हो। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कम से कम 4000 नये प्ले स्कूल्ज खोलने का निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि हम आंगनवाड़ी को पंचायत डिपार्टमैंट में दे देंगे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, अभी आप कृपया करके बैठ जायें और जब आपको बोलने का मौका मिले तो उस समय आप अपनी सारी की सारी बातें कह लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह गोलन : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का एक नारा दिया था। हमारी सरकार इसी दिशा में बेहद गम्भीरतापूर्वक कार्य कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नारे "जय जवान–जय

किसान–जय विज्ञान" के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी देश हित में एक सोच थी कि मेरे देश में सड़क कैसी हों, मेरे देश में स्वास्थ्य कैसा हो? उनका एक सपना था और आज उस सपने को हमारी सरकार ने पूरा करते हुए आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम, हाईवे निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है।

श्री उपाध्यक्षः गोलन जी, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री रणधीर सिंह गोलनः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां स्वास्थ्य के मामले में हमारी सरकार ने उचित कदम उठाए हैं वही पीने के पानी के लिए भी एक अच्छी योजना चालू की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाग्राम योजना के तहत पाई गांव में सीवरेज का काम बहुत जोरों से चालू है और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। यह सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। इसी प्रकार से पूंडरी विधान सभा क्षेत्र में स्टोर्म वाटर की निकासी के लिए भी काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी प्रकार से पूंडरी में ट्रीटमैंट प्लांट को अपग्रेड करने के काम के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आभार प्रकट करना चाहूंगा। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, हमारे पर्यटन मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से जो हमारी धरोहर हैं उनका और ज्यादा विकास हो। चाहे कुरूक्षेत्र की धरती हो, महेन्द्रगढ़ की धरती हो या यमुनानगर की धरती हो, उसके विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। एक सबसे बड़ी हमारी सरकार की योजना है वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। आज तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कालोनियों के लिए पैसे देने का काम पिछली सरकारें करती रही हैं लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल जी की पहली सरकार है जिसने गरीब मजदूर के लिए नगर परिषद् और नगरपालिकाओं में पहली बार अढाई–अढाई लाख रुपये देने के लिए बजट में प्रावधान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि इस बार हरियाणा सरकार ने एक अच्छा बजट पेश किया है। इसी

प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 80 करोड़ रुपये देने की जो घोषणा की है वह भी हम सभी 90 सदस्यों के लिए खुशी की बात है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आंकड़ों की बात तो डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने बता दी है। मुझे ज्यादा तो कुछ समझ में आया नहीं। कुछ सदस्यों ने बजट को आंकड़ों की जादूगरी बताया है लेकिन डॉ. कादियान साहब ने जो बताया वह मुझे समझ में आ गया है। जितना कर्ज 6 साल में प्रदेश पर चढ़ा है उतना पहले कभी नहीं चढ़ा। हरियाणा के गठन के बाद से पिछले 48 सालों में 61 हजार करोड़ रुपये कर्ज चढ़ा था और पिछले 6 साल में कितना कर्ज बढ़ा है, वह आपके सामने है। यह जो कर्ज बढ़ा है उसके बावजूद भी धरातल पर काम नजर नहीं आता है। इस बजट को देख कर मुझे वही कहावत याद आती है कि घर की बही और काका लिखणिया। अब मैं यह बताना चाहूंगा कि जब बजट के लिए हमारे सुजैशन लिए जा रहे थे तो सभी से पूछ कर ही तो यह बजट लिखा गया होगा। इसमें वैसे हमारे सुजैशन की जरूरत भी नहीं थी। यदि मुख्यमंत्री जी ने यह बजट बनाना था तो उन्होंने अपने सहयोगी उप–मुख्यमंत्री जी की राय लेनी चाहिए थी। उप–मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं वही बता दें कि क्या उन्होंने इस बजट को पढ़ा है। यदि मुख्यमंत्री जी इस बजट को बनाने में उप–मुख्यमंत्री जी की सलाह ले लेते तो यह सारा रासा ही खत्म हो जाता । मुख्यमंत्री जी ने बजट को लिखने में उप मंख्यमंत्री जी को भी कॉन्फिडैंस में नहीं लिया जबकि वह उनकी सहयोगी पार्टी है तो इससे बड़ी बात क्या होगी।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : मलिक साहब, आप यह ज्ञान कहां से लाए हैं।

[illegible]क्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): मलिक साहब, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि बजट में विपक्ष भी सहयोगी है वह भी अपने सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद हम हरियाणा का बजट बनाएंगे और आपको वह बात भी ठीक नहीं लग रही है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जेजेपी के जन सेवा पत्र और बी.जे.पी. के संकल्प पत्र में 428 वायदे हैं क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ा है जिसमें किसानों का

कर्ज माफी का वायदा, पूरी फसल को खरीदने और फसल के रजिस्ट्रेशन को बन्द करने का वायदा, प्राईवेट कम्पनी से बन्द करवाकर सरकारी कम्पनी से फसल का बीमा करवाना, निःशुल्क ट्यूबवैल कनैक्शन, पंजाब के समान वेतनमान, बेरोजगारी भत्ता, कर्मचारियों की पुरानी पैंशन बहाल करने का वायदा किया गया था। शायद इसके बारे में तो उप–मुख्यमंत्री जी को याद होगा क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक लैटर भी लिखा था । जब ये लोक सभा में थे वहां भी इन्होंने पुरानी पैंशन बहाली का प्रश्न उठाया था। इनके उस लैटर को भी मुख्यमंत्री जी ने कंसीडर नहीं किया। ये सारी चीजें इसके अलावा एस.वाई.एल. नहर, दादूपुर नलवी नहर, हांसी बुटाना ब्रांच एवं गौचरान भूमि को मुक्त कराने के ये 5 साल के बहुत सारे ऐसे वायदे थे। पिछले बजट में सरकार ने पिंजौर की सेब मण्डी, कुण्डली की मसाला मण्डी के बारे में कहा था लेकिन आज तक यह बता दें कि कहीं पर भी कोई काम हुआ हो। यह पिछले बजट में भी था। इस बजट में भी है। एक साल तक भी इस पर काम नहीं हुआ। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो लोगों को दिखाए जाओ लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। 'भावान्तर भरपाई योजना' का भी बड़ा जिक्र आता है। इसमें किसान को आलू और टमाटर का जो 5 रुपये का रेट दिया जा रहा है उससे अधिक किसान का तीन गुना खर्चा आता है। आप चाहे इंटरनेट पर सारी चीजों के रेट और प्रोडैक्शन निकालकर देख लें । मैंने ये दोनों चीजें इंटरनेट से निकलवाई हैं। इसमें सरकार जो रेट किसान को दे रही है उससे ज्यादा किसान का तीन गुणा खर्चा आता है। सरकार ने पिछले बजट में किसान के लिए 40–50 लाख रुपये दिये थे। उससे पहले तो बिल्कुल ही 15–20 लाख रुपये दिये थे। यह कहां दिये और किस मंडी में दिये इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब सरकार ने कहा है कि हम बागवानी का क्षेत्र 8.17 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना है। पिछले बजट में भी यही बात थी लेकिन एक प्रतिशत भी नहीं बढ़ा। आप बेशक पिछला बजट उठाकर देख लें। सरकार ने एक साल में तो कुछ किया नहीं। अब सरकार कह रही है कि अगले बजट में कर देंगे। अब सरकार ने नाबार्ड की योजना के अन्तर्गत 52 राजकीय पशु चिकित्सालयों व 115 राजकीय पशुधन औषधालयों को खोलने की बात की है। यह पिछले बजट में भी थी और इस बजट में भी आ गई। सरकार कब तक इस तरह से लोगों को धोखा देती रहेगी। अब दो दिन पहले सरकार ने पशु गणना की बात की है। आज तक सरकार ने पशु गणना नहीं करवाई है। इसी तरह से आवारा पशुओं को मुक्त कराने की बात आई है

जोकि सभी सदस्यों की प्रॉब्लम है। इसी तरह से 5 साल तक सरकार 6 महीने की तारीख देती रही कि इस तारीख तक हर जिले को आवारा पशुओं की समस्या से मुक्त कर दिया जाएगा लेकिन यह काम भी आज तक नहीं हुआ। पांच साल पिछले गुजर गए और आज भी यही समस्या है। सरकार कहती है कि गऊशालाओं के लिए 20 करोड़ रुपये देने का काम किया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, गऊशालाओं में भी गऊएं भूखी मरी हैं। हरियाणा प्रदेश में गऊओं का जो मरने का आंकड़ा है उसमें भूख से मरने वाली गऊएं सबसे ज्यादा हैं। जहां तक मैडिकल कालेजिज की बात है, वहीं मैडिकल कॉलेज पिछले बजट में थे और उन्हीं को इस बजट में भी शामिल कर दिया गया है। एक भी नया मैडिकल कालेज सरकार ने खोलने का कोई काम नहीं किया है। क्यों लोगों को झूठे सपने दिखाने का काम कर रहे हो? इस बार पिछले बजट की अपेक्षा खेलों का भी बजट कम कर दिया गया है। सरकार कहती है कि नौकरी देगी और खिलाड़ियों के लिए तो यहां तक कहती है कि इनको एच.सी.एस. लैवल के क्लॉस–वन और क्लॉस–टू की नौकरियां देने का काम किया जायेगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह व्हाइट पेपर जारी करके बताये कि कितने खिलाड़ियों को यह नौकरियां दी गई हैं? अध्यक्ष महोदय, सरकार खेलों में भत्ते बढ़ाने की बात करती है लेकिन जब खेलों का बजट ही कम कर दिया गया है तो भत्ते कैसे बढ़ायेंगे? बजट में 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया गया है। सरकार कहती है कि 1000 नई खेल नर्सरीज चालू की जायेंगी लेकिन 150 खेल नर्सरियों को बंद करने का काम तो इसी सरकार ने ही किया है। इस तरह के प्रोग्राम यह सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह भी कहा था कि के.एम.पी. के साथ पांच शहर बसायेंगे। बजट में तो इस बारे में कुछ कहा भी नही कहा गया है। क्या इन पांच गांवों का बसाने का काम पूरा तो नहीं हो गया है? सरकार द्वारा लगातार खोखली बातें ही कही जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सोनीपत के खरखोदा गांव में 3000 एकड़ में आधुनिक टाउनशिप बनाने की बात कही गई है। उसके बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं है। वहां पर एक ईंट तक नहीं लगी है और इसी प्रकार सोहना में 1400 करोड़ रूपये की लागत से एक आई.एम.टी. बनाने की बात कही गई थी लेकिन इस दिशा में क्या कदम उठाये गए, इनका कोई जिक्र बजट में नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके के किलोहडद गांव में एक आई.आई.आई.टी. का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित होना था लेकिन आज तक इसकी नींव तक नहीं भरी गई है। सरकार बस

बड़ी–बड़ी बातें करती है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सरकार ने जलवायु व पर्यावरण पर बहुत बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया। सरकार के मंत्री, एम.एल.एज. और दूसरे लोगों ने इस कार्यक्रम के तहत झाड़ू लगाने का काम किया था। यही नहीं पिछले बजट में 100 स्मार्ट गांव बनाने का वायदा किया गया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जिन गांवों को स्मार्ट गांव बनाया गया क्या उनकी डिटेल सरकार दे सकती है? सरकार वन क्षेत्र को बढ़ाने की बात करती है लेकिन सरकार ने तो पूरे अरावली क्षेत्र को ही बेच दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पर्यावरण किस प्रकार सुधरेगा? अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश गंदा और प्रदूषित हरियाणा बन गया है। भारत के सबसे प्रदूषित 21 शहरों में हरियाणा के भी कुछ शहर हैं। वैश्विक गुणवत्ता के हिसाब से एक विदेशी कंपनी ने बताया है कि हरियाणा के पांच शहर गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, जींद और हिसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता के नाम पर सोनीपत शहर में एक साल का 72 करोड़ का ठेका दिया गया है लेकिन बावजूद इसके सोनीपत आज बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह पैसा गया कहां? अध्यक्ष महोदय, यह पैसा घोटालों में गया है। मेरे पास 45–46 घोटालों की लिस्ट है, मैं इन्हें सरकार को दे सकता हूँ तो सरकार को पता चल जायेगा कि कितना पैसा इन घोटालों में गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार जलवायु को साफ रखने के नाम पर पराली जलाने पर किसान पर तो जुर्माना कर देती हैं लेकिन सरकार यह बताये कि सरकार ने जो ठोस कचरा प्रबंधन के प्रौजैक्ट बनाने थे, वे क्यों नहीं बनाये। सरकार बतायें कि इनके लिए क्या इंतजाम किए गए? अध्यक्ष महोदय, किसान पर जब जुर्माना लगाना चाहिए जबकि सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी प्रौजैक्ट लगा रखे हो और किसान उनका प्रयोग न करता हो लेकिन जब यह प्रौजैक्ट सरकार ने लगाये ही नहीं है तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सरकार को किसान पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में गऊ हत्या की घटनायें बढ़ती ही जा रही हैं। मेरे पास गऊ हत्या के संबंध में आज तक की रिपोर्ट मौजूद है। हरियाणा में बढ़ती गऊ हत्याओं के केसिज को देखकर माननीय कोर्ट ने तो यहां तक पूछा है कि यह क्या मामला है? अध्यक्ष महोदय, जलवायु पर्यावरण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने गंगा और घग्गर नदी की सफाई के लिए हरियाणा स्टेट को फटकार लगाई है। आज तक सरकार ने एक पैसा भी इस प्रोजैक्ट पर नहीं लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय,

शिक्षा मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर माननीय मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। (विघ्न) परंतु मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है कि रैंकिंग के मामले में हरियाणा पहले चौथे स्थान पर था और अब 10वें स्थान पर आ गया है। (विघ्न) नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र पर काफी चिंता व्यक्त की है। हरियाणा प्रदेश निर्धनता, भुखमरी, स्वच्छ जल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में 18वें स्थान पर आ गया है, यह बात मैं नहीं बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। अध्यक्ष महोदय, पहले हरियाणा प्रदेश पहले नम्बर पर आता था, अब वह पिछड़ता–पिछड़ता काफी पीछे जा पहुँच गया है। यह बात मैं रिकॉर्ड से सदन में बता रहा हूँ कि इस प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं उनका मुख्य व सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में 28.7 प्रतिशत बेरोजगारी है। इससे पहले इतनी बेरोजगारी कभी भी नहीं हुई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आप अपनी स्पीच समाप्त कीजिए क्योंकि आपकी ही पार्टी के सदस्यों का बोलने का समय कम हो जायेगा। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, सोनीपत के बड़ी गांव में रेल कोच फैक्ट्री में हजारों बच्चों का रोजगार था, वह चला गया। पिछले साल सरकार ने जॉब मेले लगाए थे, उनमें भी किसी को रोजगार नहीं मिला। कितने एम.ओ.यूज. साइन हुए थे, उनका भी पता नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास की बातें करते हैं, मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में औद्योगिक विकास किस के समय में हुआ था। आज छोटे से लेकर बड़े औद्योगिक व्यवसाय खत्म हो गये हैं, इस प्रकार से बेरोजगारी दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। इस प्रकार की किसी भी बात का बजट में जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कितना विदेशी निवेश आया, इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैट्रो का भी कोई जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सोनीपत से जीन्द तक रेलवे लाइन पर आर0यू0बी0 लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दे रहा है। बरसात के समय पानी भर जाने के कारण इधर का आदमी इधर और उधर का आदमी उधर ही रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हर गांव वाईफाई करने का वायदा किया हुआ था, किसी एक गांव का नाम माननीय मंत्री जी सदन में बता दें, जिसमें वह गांव वाईफाई हुआ हो। इस प्रकार से किसान अपना रजिस्ट्रेशन

ऑन–लाइन किस प्रकार से करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार कोई भी काम प्रैक्टिकल नहीं करती, केवल दिखावे में ज्यादा जोर लगाती है। हाई कोर्ट की बैंच का भी बजट में कोई जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज तक सरकार ने गऊ चरान के लिए निर्धारित भूमि की एक गज जमीन से भी कब्जा नहीं छुड़ाया है जबकि सरकार हर गवर्नर एड्रैस में इस बात को लिख देती है । अगर सरकार ने कहीं भी केवल एक गज गऊ चारान भूमि से कब्जा छुड़वाया हो तो बताये । सरकार ने कहा कि हम छात्र संघ के चुनाव बहाल करवायेंगे लेकिन इस बजट में इसका कहीं जिक्र ही नहीं है । इस बात का गवर्नर एड्रैस में भी कोई जिक्र नहीं था । ये छात्र संघ के चुनाव करवाने की सिर्फ बात करते हैं । मैं एक बिना खर्च का काम बताना चाहता हूं । इस समय सदन में विज साहब उपस्थित नहीं है । ऐसे कई हजार युवा हैं जो अभी होम गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहे हैं । उनको काम करने के लिए कोई और विकल्प नहीं है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनको होम गार्ड के तौर पर रैगुलर बेस पर भर्ती किया जाए । इसके अलावा मैं एक और बिना खर्च का सरकार को काम बताना चाहता हूं और उस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हामी भरी हुई है । जाट आरक्षण संघर्ष समिति की सिर्फ 5 मांगें हैं । मेरा निवेदन है उन मांगों को भी मान लिया जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं इन मांगों को आपको लिखित रूप में दे देता हूं । इनको भी अवश्य ही पूरा करवाया जाए । किसानों की आय बढ़ाने के लिए मेरा आपको एक सुझाव है । मेरे पास किसानों के 20 प्वॉयंट्स हैं । सरकार को इन पर अमल करना चाहिए क्योंकि 6 लाख गरीब किसान आज भी कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं । किसानों पर लगभग 371 करोड़ रुपये का कर्ज है । उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपको अपने सुझाव लिखित रूप में भी दे रहा हूं । इसमें मेरे हल्के की डिमाण्ड्ज भी हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, आप अपने हल्के की डिमाण्ड्ज हमें लिखकर दे दीजिए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को पता है कि प्रदेश में न पीने का पानी है, न अस्पतालों में डॉक्ट्र्स उपलब्ध हैं, न स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हैं । सभी माननीय सदस्यों को इन सब बातों का पता है लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को यस कहना पड़ता है । अतः सरकार को अभी सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, अब आप बैठिये ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ बातें अभी कहने से रह गई हैं फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, आप उनको लिखित रूप में हमें दे दीजिए । हम उनको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देंगे।

***श्री जगबीर सिंह मलिक** : ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए अलग बजट का ऐलान किया जाए व किसानों के बजट को बढ़ाया जाए क्योंकि यह कुल बजट का 6 फीसदी भी नहीं है । किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया जाए । 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' के तहत प्रदेश का किसान बहुत परेशान है क्योंकि किसानों की पहली शिकायत ये है कि उन्हें इंटरनेट की समझ नहीं है । रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जटिल है व अधिकतर किसान अनपढ़ हैं, इसलिए इसको खत्म किया जाए । 'भावान्तर भरपाई योजना' में जो एम.एस.पी. तय किया गया है, वह मार्केट के हिसाब से या लागत के हिसाब से तय करना चाहिए न कि अपनी मर्जी से तय करना चाहिए । डीजल यूरिया, डी.ए.पी., दवाइयां और उगाही में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है लेकिन एम.एस.पी. की कीमत नहीं बढ़ाई गई । स्वामीनाथन रिपोर्ट व किसान को सी2 फॉर्मूला के तहत दाम तय करने चाहिए, जो उसकी मूल कीमत, लागत व 50 प्रतिशत मुनाफा के साथ हो । दादूपुर नलवी नहर परियोजना को फिर से बहाल करें, जिससे करनाल, अंबाला और कुरूक्षेत्र का भू–जल संरक्षण किया जा सके । हांसी–बुटाना नहर में पानी दिया जाए । ओलावृष्टि, बाढ़, पानी आग से हुए नुकसान में सीधा किसान की रिपोर्ट अनुसार मुआवजा खुद सरकार देने का काम करे । फ्री ट्यूबवैल क्नैक्शंज दिये जाएं । बेसहारा पशुओं की समस्या के लिए योजना का ऐलान किया जाए जोकि इस बजट में कोई जिक्र नहीं है । बेसहारा पशुओं की वजह से जो मौतें होती हैं उनका उचित मुआवजा दिया जाए । धान घोटाले की वजह से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो । 24 घंटे में फसल की कीमत अदा की जाए । कैथल में चिप घोटाला की जांच व नुकसान की भरपाई करें । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं कुछ गोहना हल्के से संबंधित अपनी मांग रखना चाहता हूं । गोहाना हल्के को जिला घोषित किया जाए । गांव किलोहडद में आई.आई.आई.टी. की बिल्डिंग के लिए बजट दिया जाए । गोहाना के तीनों सैक्टर्ज को जिनकी जमीन

---

*चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग का पार्ट बनाया गया।

हुड्डा विभाग के पास है, उनको जल्दी से जल्दी विकसित किया जाए । गांव भठगांव व मोहाना में आई.टी.आई. बनवायी जाए । मोहाना को सब तहसील व ब्लॉक बनाया जाए । बी.पी.एस. महिला मैडिकल कॉलेज खानपुर कलां में डॉक्टर्ज को समयबद्ध प्रमोशन दिया जाए । स्पैशिएलिस्ट डॉक्टर्ज को नियुक्त किया जाए । डी.सी. रेट पर लगे एल.टी. को समान काम समान वेतन दिया जाए । पैरा मेडिकल स्टॉफ को पूरा किया जाए । कानों के टेस्टिंग की मशीन उपलब्ध करवायी जाए । दवाइयां मिलने व संबंधित टैस्ट समय पर करने का इंतजाम करवाया जाए । गोहाना में टूरिस्ट कॉम्पलैक्स स्थापित किया जाए । इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग से संबंधित कुछ मांग रखना चाहता हूं । गुहणा माइनर में टेल तक पानी नहीं आता, इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने के लिए प्रबन्ध करवाया जाए । किलोहड़द – राई डिस्ट्रिब्यूट्री में पानी नहीं आता, इसलिए वहां पर भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था करवायी जाए । भटाना जाफराबाद में सोनीपत माइनर से पानी नहीं आता, इसलिए वहां पर भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था करवायी जाए । माच्छरी में जुआं माइनर से टेल पर पानी नहीं आता, इसलिए वहां पर भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था करवायी जाए । खानपुर कलां में रामगढ़ माइनर से टेल पर पानी नहीं आता, इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करवायी जाए । कैलाना खास में जवाहरा माइनर से पानी नहीं आता, इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था करवायी जाए । सरगथल माइनर में टेल तक पानी नहीं आता, इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था करवायी जाए । माहरा –खुबड़ू ब्रांच वाले रजबाहे में पानी नहीं आता, इसलिए वहां पर पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था करवायी जाए । अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको अपने हल्के की कुछ सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं जोकि इस प्रकार हैं – जौली से न्यात और जौली से खेड़ी दमकन की सड़क खराब है । खेड़ी दमकन से लाठ और खेड़ी से न्यात की सड़क खराब है । तिहाड़ मलिक से माहाना की सड़क खराब है । पिनाना से भैंसवाल कलां की सड़क खराब है । गुहणा से फरमाणा, गुहणा से भैंसवाल कलां, गुहणा से मोहाना और गुहणा से सलीमसर माजरा की सड़क खराब है । लुहारी टिब्बा से मोहाना और फरमाणा रोड़ से गांव तक की सड़क खराब है । हुल्लाहेड़ी, गोहाना रोड़ से दिल्ली ब्रांच नहर तक की सड़क खराब है । किलोहड़द गोहाना रोड़ से किलोहड़द तक की सड़क खराब है । खिजरपुर जाट माजरा गांव से चिटाना और गोहाना रोड़ से खिजरपुर जाट माजरा तक की सड़क खराब है । जाजी से माच्छरी तक की सड़क खराब

है । नैना तातारपुर से मोहाना सड़क अधुरी है और नैना से सलीमपुर ट्राली की सड़क खराब है । बाघडू महलाना पुल से बड़ी बाघडू तक की सड़क खराब है । सलारपुर माजरा से मोहाना की सड़क खराब है । माच्छरी, गोहाना रोड से गांव के स्कूल तक की सड़क खराब है । जुआं से माच्छरी की सड़क खराब है । सलीमपुर ट्राली से नैना तातारपुर सड़क खराब है । महलाना दिल्ली ब्रांच नहर के साथ वाली सड़क खराब है । चिटाना से चटिया ओलिया सड़क के बीच में बिजली के खम्भे खड़े हैं । दुभेटा से रोलद लतीफपुर की सड़क खराब है । कैलाना खास से मुण्डलाना की सड़क खराब है । खानपुर कलां से मुण्डलाना की सड़क खराब है । दोदवा से बोहला की सड़क पर पुल निर्माण करना है । माजरी की गन्दे पानी की निकासी नहीं होने के कारण मेन सड़क पर पानी जमा हो जाता है जिस कारण सड़क टूटी पड़ी रहती है । अतः मेरा निवेदन है कि इनको पुनः बनवा दिया जाए या रिपेयर करवा दिया जाए । सोनीपत से जीन्द रेलवे लाइन पर जो अन्डर ब्रिज है उसको फाइबर से कवर करके (गुरूग्राम की तर्ज पर) बरसात के मौसम में जलभराव से मुक्ति दिलाई जाये । अध्यक्ष महोदय, तिहाड़ मलिक गांव में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है । पिनाना गांव के जीलान पान्ने में पानी नहीं आता है । लाठ गांव से टयूबवैल तक पानी की पाइप लाइन डलवाई जाये जिसकी लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर है । जौली गांव में नया टयूबवैल लगवाया जाये । हुल्लाहेडी गांव में डिग्गी के लिए दिल्ली ब्रांच नहर में मोगा कनैक्शन करवाया जाये । अध्यक्ष महोदय, इस गांव में पानी की सारी लाइनें खराब है । गांव खिजरपुर जाट माजरा में हुल्लाहेडी गांव से पीने का पानी आता है जोकि बहुत गंदा है, इसे ठीक किया जाये । गांव बाघडू में पीने का पानी नहीं है। इसके लिए महलाना नहर टयूबवैल से कनैक्शन करवाया जाये। तिहाड़ कलां गांव में टयूबवैल का पानी खराब है, इस गांव की डिग्गी मंजूर है, इसे जल्दी से जल्दी बनवाया जाये । तिहाड़ खुर्द, रोलद, भादी, चिटाना गांवों में भी टयूबवैल का पानी खराब है, इसे भी ठीक करवाया जाये । अध्यक्ष महोदय, गांव करेवड़ी में पानी की लाइने खराब पड़ी हुई है । इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये । गांव जुआं–टू में पीने के पानी की भारी समस्या है। गांव दोदवा में पीने के पानी के लिए एक और टयूबवैल लगवाया जाये । गांव ककाना में पानी की डिग्गी का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है, इसे जल्दी से जल्दी बनवाया जाये । अध्यक्ष महोदय, गांव सलीमपुर ट्राली में पानी की डिग्गी के तालाब का बैंड टूटा हुआ है, जिसके कारण पानी जल्दी खत्म हो जाता

है, इस समस्या का भी निदान होना चाहिए । गांव बोहला में टयूबवैल मंजूर हो चुका है लेकिन पानी की लाइन नहीं डली है, इस कार्य को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये । अध्यक्ष महोदय, गांव रतनगढ़ में तो आधे गांव में पानी की लाइनें नहीं है, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान घोटालों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, रोडवेज में किलोमीटर स्कीम घोटाला, 6 जिलों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, डाडम माइन्ज घोटाला, यमुना रेत खनन घोटाला, बिजली मीटर घोटाला, रोडवेज टिकट (करनाल, पलवल और नारनौल) घोटाला, ओवरलोड वाहन घोटाला जिसमें 6 जिलों के उपायुक्त व आर.टी.ए. शामिल हैं, जीन्द में बिजली निगम का 6 करोड़ रुपये का घोटाला, जीन्द में जनस्वास्थ्य विभाग में घोटाला, सोनीपत पशु विभाग में घोटाला, किसानों की सब्सिडी में 17 करोड़ रुपये का घोटाला, फसल बीमा योजना में घोटाला, उद्यान विभाग का नकली क्लस्टर घोटाला, करनाल में आटा घोटाला, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत अस्पतालों में दवाई और टैस्ट्स के नाम पर घोटाला, प्रधानमंत्री मातृत्व वेदना योजना के अन्तर्गत 88 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती दिखाकर लाखों रुपयों का घोटाला, राज्य कर्मचारी बीमा निगम घोटाला, नागरिक अस्पतालों में ठेके पर नौकरी देने के एवज में पैसे वसूली का घोटाला, ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने का घोटाला, जी.एस.टी. के नाम पर घोटाला, सोनीपत ड्रैन नं. 6 के निर्माण में घोटाला, कारपोरेशन, नगर परिषद्, जिला परिषद्, पंचायत समितियों में घोटाले, स्वर्ण जयन्ती घोटाला, गीता जयन्ती घोटाला, कबीर जयन्ती घोटाला, ए.आई.पी.एम.टी. में 60 करोड़ रुपये का घोटाला, केन्द्रीय विद्यालय संगठन परीक्षा में 3 करोड़ रुपये का घोटाला, रोडवेज में चालक भर्ती में घोटाला, आंगनवाड़ी वर्कर भर्ती में घोटाला, स्टाफ नर्स के लिए 150 अयोग्य आवेदकों का घोटाला, चैकिंग में पकड़े गए फर्जीवाड़ा का घोटाला, जज भर्ती परीक्षा का घोटाला, एच.सी.एस. की परीक्षा में घोटाला, मतस्य पालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में घोटाला, पशु बीमा के नाम पर घोटाला, पैंशन व गोल्डन कार्ड में घोटाला, बिजली बिल में घोटाला, कूड़ा उठान के नाम पर घोटाला, एच.एस.वि.प्रा. में घोटाला, छात्रवृति घोटाला, जी.पी.एस. इंडेक्सिंग में घोटाला, धान घोटाला, मृदा कार्ड घोटाला न जाने कितने घोटाले हुए हैं । सरकार ने इन घोटालों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति से संबंध में भी कुछ बताना

चाहूंगा । हरियाणा में वर्ष 2013 में तत्कालीन सरकार द्वारा जाटों के साथ अन्य 5 जातियों को एस.बी.सी. में शामिल कर लिया गया था । दुर्भाग्यवश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 मार्च, 2015 को दिए गए फैसले में इसको रद्द कर दिया गया । हरियाणा में भाजपा के सांसद श्री राजकुमार सैनी, श्री अश्विनी चोपड़ा व अन्य नेताओं ने जातीय विद्वेष पैदा कर दिया था । हरियाणा सरकार के मंत्रियों श्री ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और पार्टी अध्यक्ष श्री सुभाष बराला के रिश्तेदारों व भाजपा के कार्यकर्त्ताओं द्वारा जाट आरक्षण आन्दोलन 14 फरवरी, 2016 से 22 फरवरी, 2016 तक करवाया गया । इस आंदोलन में जाट, गैर–जाट का नारा देने वाले नेता श्री राजकुमार सैनी द्वारा ओ.बी.सी. ब्रिगेड बनाई गई और पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर व अन्य नेताओं द्वारा 35–1 का नारा लगवाकर हरियाणा में सुनियोजित हिंसा करवाकर जातीय दंगे करवाने का काम किया गया । मार्च, 2016 से फरवरी, 2018 तक केंद्रीय मंत्रियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा सरकार के मंत्रियों/अधिकारियों की उपस्थिति में हुई मीटिंग्स के बाद हुए समझौतों के बाद भी आज तक हरियाणा सरकार द्वारा जाट समाज की मांगों को पूरा नहीं किया गया है । अध्यक्ष महोदय, आन्दोलन के दौरान दर्ज सभी केसों को वापिस लिया जाए और जिन केसों पर अदालत में स्टे है उनके बारे में अदालत को सही स्थिति से अवगत कराकर उन केसों को वापिस लिया जाए । हरियाणा सरकार फिर से जाट समेत 6 जातियों को हरियाणा के बी.सी. (बी.) में शामिल करने का बिल लाए । धरनों के दौरान धरनों पर बैठे लोगों के मृतक आश्रितों को भी सरकार द्वारा नौकरी का आश्वासन दिया गया था उसको भी जल्द पूरा किया जाए । हरियाणा में एस.बी.सी. आरक्षण के रहते हुए सभी 6 जातियों के जिन अभ्यर्थियों का सलैक्शन हुआ था उन्हें तत्काल नौकरी पर उसी तरह ज्वायन कराये जिस तरह एस.सी.बी.सी. के साथ ही लागू ई.बी.पी.जी. के तहत चयनित अभ्यर्थियों को ज्वायनिंग दी है । हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा पारित 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण में उम्र व अन्य छूट का प्रावधान किया जाए जैसे अन्य राज्यों ने किया है ।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, अब हाउस का समय काफी कम बचा है । अतः आप सदन का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा देना ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए । हम हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा देंगे ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही बढ़िया बजट है । आज तक ऐसा बजट कभी पेश नहीं हुआ है । इससे पहले इस धरती पर किसी भी सरकार ने विपक्ष से सलाह–मश्विरा करके बजट नहीं बनाया था । इस सरकार ने सभी विधायकों से 3 दिन तक बजट पर सुझाव लिये, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और संगठनों से सलाह करके बजट बनाया है । मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारा बजट पढ़कर सदन में सुनाया और उसके बाद बहुत–से माननीय साथियों ने उस पर अपने विचार रखे हैं । विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी बजट पर अपने विचार रख लिए और बाकी माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रख लिए । हालांकि विपक्ष ने तो बजट को क्रीटीसाइज किया है क्योंकि इनका काम ही ऐसा होता है । अगर ये बजट को क्रीटीसाइज ही नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी ? असलियत में यह बजट एक बहुत ही बेहतरीन बजट है । अतः मैं इस बजट को एक बहुत ही बेहतरीन बजट मानता हूं । सरकार ने जो बजट बनाया है मैं उसके पक्ष में हूं और उसकी तारीफ करता हूं । इसके अलावा मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप इस ठेकेदारी प्रथा को फौरन बंद कर दो । यह एक वाहियात और गलत काम है । ठेकेदार बेवजह ही गरीब लोगों से बीच में कमीशन लेते हैं । उन गरीब लोगों को 8–10 हजार रूपये तनख्वाह मिलती है और ठेकेदार उसमें से भी 2–3 हजार रूपये कमीशन के ले लेते हैं । (विघ्न) हुड्डा साहब ने वर्ष 2006 में डी.सी. रेट पर बच्चों को भर्ती किया था । इन्होंने गलती तो बहुत भयंकर की थी । इन्होंने प्रदेश पर 9 साल तक राज किया लेकिन आउटसोर्सिंग बेसिज पर लगे हुए बच्चों को अपनी सरकार के अंतिम समय में भी रैगुलर नहीं किया । इस वजह से वे बच्चे आज भी दर–दर की ठोकर खा रहे हैं । इस सरकार ने 5 साल तक राज कर लिया है और इनका छठा साल चल रहा है । इस सरकार ने भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का न करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर इनके परिवार के बच्चे उनकी जगह पर होते तो इनके दिलों पर क्या बीतती ? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि संबंधित कर्मचारियों को फौरन पक्का किया जाए क्योंकि उनको 14 वर्ष का समय बीत चुका है। इस प्रकार संबंधित कर्मचारियों को बहुत समय व्यतीत हो चुका

है। इसके अतिरिक्त अभी पीछे माननीय उपमुख्यत्री श्री दुष्यंत जी ने जवाब दिया था कि दोहलीदार, बुटीमार, मुकररीदार, भौंडेदार की जमीन के संबंध में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कानून बनाने में गलती की है। इसमें दोहलीदार, बुटीमार, मुकररीदार, भौंडेदार की जमीनें पंचायती जमीन नहीं हैं क्योंकि पंचायतें सन् 1952 में बनी थीं और संबंधित दोहली की जमीनें इससे पहले दी जा चुकी थी। ये जमीनें सिर्फ एक ब्राह्मण बिरादरी को ही नहीं दी गयी हैं बल्कि इसमें दूसरी 6 बिरादरी भी शामिल हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कानून बनाते समय गलती की थी तो वर्तमान सरकार उसको ठीक कर दे। अगर कोई सरकार दी हुई जमीनों को वापिस लेगी या दी हुई चीजें वापिस लेगी तो उसका सत्यानाश होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बातें ईमानदारी से कह रहा हूं और दिल से कह रहा हूं। दोहली की जमीनें अगर सरकार ने वापिस ली हैं तो उनको तुरंत संबंधित लोगों को वापिस करना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि लगभग 8500 परिवारों को ई.बी.पी.जी. कैटेगरी में शामिल किया गया था। यह कैटेगरी हुड्डा साहब के समय में बनायी गयी थी और इसको माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने भी चालू रखा। इसमें 560 बच्चे ऐसे हैं जिनका 4–5 कैटेगरीज की पोस्ट्स में सैलेक्शन हो चुका है। जिसमें एस.ए., जी.एस.ओ, स्टैनो और पी.जी.टी. हिस्ट्री की पोस्ट्स हैं। इन पोस्ट्स से संबंधित केस माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है, परन्तु सरकार की तरफ से संबंधित बच्चों की तरफ से डिफैंड करने के लिए ए.जी. कोर्ट में पेश नहीं होता है। इसमें सरकार को चाहिए कि संबंधित मामले में स्टैंड लेकर एफिडेविट जारी करे क्योंकि दिनांक 7.12.2017 से पहले की जितनी नौकरियों का प्रोसैस चला हुआ है। उनमें माननीय हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया हुआ था कि संबंधित कैटेगरी के बच्चों को ज्वॉईन करवाया जाए। इसमें माननीय हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस बात से डरते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह सरकार 36 बिरादरी के गरीबों ने बनायी है और ई.बी.पी.जी. में जिन कैटेगरीज के परिवार आते हैं, उनका सरकार बनाने में अहम रोल है। इसमें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, पंजाबी, बैकवर्ड क्लॉसिज के अलावा सभी कौमों ने सरकार को अपना वोट देकर बनाया है। इन सभी का सरकार बनाने में अहम रोल है। ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी दबाव में आकर इस कैटेगरीज के बच्चों को संबंधित पोस्ट्स पर ज्वाईंन करवाने में टाल –मटोल कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत बात

है। इस मामले में माननीय हाई कोर्ट में 16.3.2020 की तारीख लगी हुई है और इस तारीख पर सरकार की तरफ से ए.जी. को पेश होकर माननीय हाई कोर्ट में सबंधित कैटेगरीज में कैंडीडेट्स को ज्वाइन करवाने के लिए ऐफीडेविट देना चाहिए। इन 560 बच्चों के परिवारों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं क्योंकि ये बच्चे पिछले सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। दर–दर की ठोकरे खा रहे हैं और अपना केस लड़ने के लिए वकीलों को भी बहुत पैसे दे चुके हैं। इसके अलावा मैंने पिछले सैशन के दौरान भी कहा था कि सरकार मजबूती के साथ 10 प्रतिशत आरक्षण जाटों समेत 5 जातियों को दे। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार ने संबंधित जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी माना था। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी और बनिया भी शामिल हैं। इनके सभी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून मजबूती के साथ बनाया जाए। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि संबंधित स्टेट्स अपनी हालात के मुताबिक 70 प्रतिशत आरक्षण दे सकते हैं और इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। ये वे लोग हैं जो सदियों से पिस्ते चले आ रहे हैं। इनमें बहुत सी ऐसी बिरादरी हैं जिनके पास न तो जमीन है, न ही कोई जायदाद है और न ही कोई अपना कारोबार है। यानी सुकी दादी पाई वो भी लंगा खोपरा ने खोस ली, क्या करें ? अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे नारनौंद हल्के की कुछ मेरी मांगें रखना चाहूंगा। वैसे तो मैं ये बातें रिपीट कर रहा हूं, परन्तु बहुत महत्वपूर्ण मांगें हैं। सरकार ने मेरे हल्के नारनौंद को सब डिवीजन बनाया था, परन्तु जिस सब डिवीजन में कोर्ट नहीं होगा। उस सब डिवीजन के कोई मायने नहीं रहते, इसलिए जल्दी से जल्दी वहां पर कोर्ट लगवायी जाए।

.....

बैठक का समय बढ़ना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त नारनौंद हल्के का बाईपास बनाया जाए क्योंकि नारनौंद हल्के का बाईपास सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह नारनौंद हल्के के दोनों तरफ के गांवों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब नारनौंद को क्रॉस करते हैं तो वहां पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जिसके कारण वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, वहां पर सरकार ने हिसार से चण्डीगढ़ तक जाने के लिए बहुत अच्छी सड़क बनायी है और यह माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है। इससे पहले वहां पर सड़के बनाने का कोई जिक्र ही नहीं था क्योंकि ज्यादातर सड़के हुड्डा साहब के एरिया की तरफ ही बनायी जाती थी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडड्ाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस सड़क के बनाने की बात कह रहे हैं , वह हमारी सरकार के टाइम पर ही मंजूर की गयी थी।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बीच में बोलने की बजाए, मेरी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी बातें चाहे किसी को सूत आएं या किसी को कसूत आएं। जो बात कहने की है, मैं उस बात को कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज मेरे हल्के की कुछ सड़कों की हालत खराब है। इसमें हांसी से भिवानी की तरफ जाने वाली सड़क खराब है और हांसी से बरवाला की तरफ जाने वाली सड़क भी खराब है। हमारी पिछले इलैक्शन के दिनों में हांसी से राजथल तक की 33 फुट की सड़क बनाने का काम किया है। इस सड़क को बनाने के लिए हमें पहले यह कहा गया था कि यह सड़क नैशनल हाईवे के अंडर आयेगी। अगर यह सड़क नैशनल हाइवे के अंडर नहीं आई तो स्टेट हाईवे के अंडर आयेगी। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में ऐसे–ऐसे काम किए हैं जो पहले की सरकारों के समय में कभी भी नहीं होते थे। पहले की सरकारों में कुछ भाइयों की तरफ से कह दिया जाता था कि मेरे–मेरे हल्के में सड़क बन जाये बाकी सारे कहीं जाओ। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अभिमन्यु जी ने राजथल तक सड़क बनाने का काम किया। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजथल से जींद तक की सड़क पर काफी सालों से कुछ काम नहीं हो रहा था। इसी तरह से जींद से कैथल तक की छोटी सड़क थी जो कि बिल्कुल ही टूटी पड़ी थी। इसी तरह से पानीपत की सड़क का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है और यह सड़क आज के दिन चलने लायक भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जींद से

रोहतक की सड़क का भी बहुत बुरा हाल बना हुआ है। मेरे नारनौंद हल्के में अनेकों ऐसी सड़कें हैं, मैं समझता हूं कि इन सड़कों के निर्माण के लिए विभाग के पास बजट की भी कोई कमी नहीं थी, मैं इस महान सदन में यह भी नहीं कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब के कार्यकाल के बारे में इस महान सदन में बताना चाहूंगा कि नारनौंद हल्के के लिए बड़ी मुश्किल से जाते–जाते हुड्डा साहब से बड़ी मिन्नतें करके एक कॉलेज खोलने की मंजूरी दिलवाई थी। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर 4 कॉलेज बनवाये। मैं इस बात के लिए सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि हुड्डा साहब के समय में सिर्फ एक आई.टी.आई. बनाई गई थी, अब वहां पर 3 आई.टी.आई. बन चुकी है। मैं यह नहीं कहता हूं कि बिल्कुल भी काम नहीं हुए। सरकार ने बहुत काम किए हैं और सड़कें भी बनाने का काम किया है लेकिन मेरे हल्के में आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। मैंने इन सड़कों के बारे में पहले भी जिक्र किया था परन्तु मैं बताना चाहूंगा कि लोहरी से डाटा की सड़क भी चलने लायक नहीं है। इसी तरह से मदनहेडी से पूठी की सड़क भी चलने लायक नहीं है और भी अनेकों ऐसी सड़कें हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में अनेकों ऐसे कच्चे रास्ते हैं जिन पर सड़क बनाने की बहुत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सड़कों का बहुत बुरा हाल हो रखा है और कुछ नई सड़कें भी बनानी है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इनका जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाये ताकि लोगों को यातायात की सुविधाएं मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में काफी गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की बहुत खतरनाक समस्या है और पानी के विषय पर मैंने विधान सभा में एक सवाल भी लगाया था। मेरे हल्के में 10–12 ऐसे गांव हैं जिनमें पीने का पानी और सिंचाई के लिए भी पानी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में बताना चाहूंगा कि डाटा मसूदपुर में भी पानी की बहुत भारी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन इलाकों में पानी की समस्या पर जल्दी से जल्दी विचार करके इन गांवों को अच्छा पानी मुहैया करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई गांवों का शिष्टमंडल मिलवाया था और उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि रोजाना ही रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री के रोजाना ही पैसे दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बात को

एक महीना बीत गया है परन्तु उनको अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। वे कह रहे हैं कि हमने 70–75 परसेंट तक रजिस्ट्रियां करवा दी हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 60 परसेंट्ज ही रजिस्ट्रियां करवाई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जितनी भी रजिस्ट्री की हैं और जो आदमी जिस दिन रजिस्ट्री करवाता है उसको उसी दिन पैसा मिल जाना चाहिए। तभी इन लोगों का हौंसला बढ़ेगा। इस संबंध में मेरा यही कहना है कि इस पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में जैसे लोहरी से डाटा मसूदपुर तक, भरतपुर खेड़ी, सोहरण, खेड़ी जालम, राखी और गामड़ा आदि में पानी की बहुत भारी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के के अस्तपालों में डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है। इस बारे में मैंने सवाल भी लगाया था कि हमारे नारनौंद हल्के के अस्पताल में 45 डॉक्टरों की पोस्ट्स रिक्त पड़ी हुई हैं और गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने इसका लिखित में जवाब दिया था कि वहां पर 41 डॉक्टरों की पोस्टें रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, हिसार जिले का बास गांव बहुत बड़ा गांव है। इस गांव में पी.एच.सी. है। इस गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु जी ने गांव खेड़ी चौपटा में एक पी.एच.सी. का निर्माण करवाया था लेकिन पहले वहां पर पी.एच.सी. नहीं थी, सरकार ने इस पी. एच.सी. में एक छोटे कर्मचारी को भी नियुक्त नहीं किया हुआ है डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहता हूं कि इस गांव में सी.एच.सी. का निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं इस महान सदन में बताना चाहूंगा कि गांव मिरचपुर, सिसाय, गुराणा और पूठी में एक–एक डॉक्टर नियुक्त कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बास गांव बहुत बड़ा गांव है इस गांव के अस्पताल में एक भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। न वहां पर कोई एक्सरे की मशीन है और न ही कोई अन्य दूसरी मशीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस गांव में कम से कम 2 लाख वोटर हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इस गांव की आबादी 4 लाख के करीब है। इस गांव के अस्पताल में एक भी डॉक्टर नियुक्त नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी इस गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस गांव का कोई गरीब व्यक्ति जब अपना इलाज हिसार के अस्पताल में करवाने जाता है तो बाद में 4 लाख रुपये का बिल उसके हाथ में थमा दिया जाता है। उस गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं इसलिए वह अपनी जमीन

बेचने पर मजबूर हो जाता है। वहां पर इन गरीब आदमियों का इतना बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इतने बड़े गांव के लोगों की भलाई के लिए सरकार को अगर डॉक्टरों की स्पैशल भर्ती भी करनी पड़े तो सरकार को डॉक्टरों की स्पैशल भर्ती करने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी भर्ती भी शुरू कर दो कि wanted doctors for Narnaund. अध्यक्ष महोदय, जब तक डॉक्टर देहात में नहीं ठहरेंगे तब तक प्रदेश के लोगों का किस प्रकार से भला होगा। मेरी प्रार्थना है कि डॉक्टरों की भर्ती के लिए ऐसा प्रौविजन कर दिया जाये कि अगर प्रदेश के गांवों में कोई डॉक्टर नौकरी करना चाहता है तो ही वे एप्लाई करे। गांवों के लोगों को डॉक्टर अपनी सेवाएं दें क्योंकि उनके लिए यह बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं कि यह समय की मांग भी है। देहात में सब जगह डॉक्टर्ज को शहरी डॉक्टर्ज से 50 हजार प्रति महीने का इंसैंटिव फालतू दिया जाये तभी गांव में डॉक्टर टिकेगा। इसके साथ ही साथ उनके लिए बढ़िया मकान बनाये जायें, उनके लिए पानी की पूरी सुविधा हो और वहां पर बिजली की भी पूर्ण सुविधा हो। उनको हॉटलाईन से भी जोड़ा जाये। ये सभी कुछ करना बहुत जरूरी है क्योंकि हैल्थ का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पीकर सर, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हैल्थ और एजुकेशन की तरफ खट्टर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और भी जितनी बातें उन्होंने कही हैं और जितनी भी चीजों के बारे में बजट में जिक्र किया गया है वो सारी की सारी सराहनीय हैं। मैं बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और इस सरकार का वैल विशर हूं। सरकार को अपनी तरफ से अच्छे बजट के लिए बहुत–बहुत बधाई देता हूं। मनोहर लाल सरकार द्वारा बहुत बढ़िया बजट बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद गौतम साहब। माननीय सदस्यगण, अब सदन कल मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2020 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*18.37 बजे

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2020 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)